RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 15 अंक 7
लखनऊ, बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

कच्चे तेल के मूल्यों में नरमी की आशा

राष्ट्रीय - 10

शांति को मौका दें: पीएम मोदी

पीटीआई। कजान (रूस)

कजान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए और भारत इसके लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर में पहुंचने के कुछ घंटों बाद पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित अपनी शुरुआती टिप्पणी में पुतिन से कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का पूर्ण समर्थन करता है।

मोदी ने यह भी कहा कि पिछले तीन महीनों में रूस की उनकी दूसरी यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय और गहरे विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम शांति और स्थिरता की जल्द बहाली का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्राथमिकता देते हैं। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर है।

मोदी ने जुलाई में मास्को में पुतिन के साथ अपनी शिखर वार्ता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में सहयोग मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देते हुए कहा कि कई देश अब इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कज़ान में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन संघर्ष पर प्रमुखता से चर्चा हुई। मॉस्को में 9 जुलाई को शिखर वार्ता में मोदी ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और बम और गोलियों के बीच शांति प्रयास सफल नहीं होते। कुछ सप्ताह बाद वे यूक्रेन गए। ज़ेलेंस्की के साथ अपनी वार्ता में मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए साथ बैठकर चल रहे युद्ध को समाप्त करना चाहिए और भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत यह कहता रहा है कि यूक्रेन में संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेजेशकियन ने पश्चिम एशिया में शांति की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी पक्षों के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। जुलाई में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने पेजेशकियन और मोदी के बीच यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने यहां प्रेसवार्ता में बताया कि मोदी और पेजेशकियन के बीच सार्थक चर्चा हुई। मिसरी ने कहा, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत के आह्वान को दोहराया। उन्होंने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरी ओर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी

हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे: सेना प्रमुख

पीएनएस/पीटीआई। नई दिल्ली/बीजिंग

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने के समझौते पर पहुंचने के बाद, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल 'हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं' और इसे हासिल करने के लिए दोनों पक्षों को 'एक-दूसरे को आश्वस्त करना होगा।' नई दिल्ली में उनका यह बयान भारत द्वारा चीन के साथ गश्त करने के समझौते की घोषणा के एक दिन बाद आया है। चीन ने मंगलवार को पुष्टि की कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत के साथ उसका समझौता हो गया है। इसका मतलब है कि दोनों सेनाएं अब अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करेंगी (शेष पृष्ठ 9)

फर्जी धमकियों से होती है वित्तीय क्षति

राजेश कुमार। नई दिल्ली

भारतीय एयरलाइनों को निशाना बनाकर बम की धमकी देने वाले संदेशों का खतरा थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोमवार रात से मंगलवार तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाली करीब 80 और उड़ानों को नई धमकियां मिली हैं। लेकिन इससे एयरलाइन ऑपरेटरों पर भी भारी वित्तीय असर पड़ा है, जो पहले से ही वित्तीय तनाव में हैं, सुरक्षा बलों, रसद और नियामक निकायों जैसे संचालन हितधारकों को सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास करने के लिए कहा गया है। विमानन उद्योग के सूत्रों के अनुमान के अनुसार, सुरक्षा अभ्यास करने में औसतन एक से तीन करोड़ रुपये का खर्च आता है और इसका बोझ सरकार से लेकर निजी एजेंसियों तक सभी हितधारकों पर पड़ता है। इसका मतलब है कि फर्जी कॉल के बाद कुल 180 उड़ानों पर लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सतर्क कर दिया गया और नियामक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के मार्गदर्शन के अनुसार सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया। बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) के लिए प्रोटोकॉल, किसी विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी के कॉल की स्थिति में बुलाई जाती है, ताकि विभिन्न भारतीय एयरलाइनों को दी जा रही धमकियों की बाढ़ से निपटा जा सके। सोमवार की रात, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, मैंगलोर, बेंगलुरु और कोझिकोड के सात हवाई अड्डों पर एकत्रित हुई बीटीएसी (शेष पृष्ठ 9)

सीआरपीएफ के और स्कूलों को धमकी

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

दिल्ली के रोहिणी इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पब्लिक स्कूल के बाहर हुए बम विस्फोट के कुछ दिनों बाद, मंगलवार को तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय एजेंसी के स्कूल को एक ईमेल मिला, जिसमें देश भर के पांच स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि, बाद में आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि ईमेल फर्जी निकला। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद के पास मेडचल में एक सीआरपीएफ स्कूल को एक ईमेल मिला, जिसमें दिल्ली और हैदराबाद में तीन सीआरपीएफ स्कूलों और अन्य शहरों में बल के कार्यालय परिसर में स्थित दो केंद्रीय विद्यालयों को उड़ाने की धमकी दी गई। तीन सीआरपीएफ स्कूलों में दिल्ली (रोहिणी और द्वारका) में दो, हैदराबाद (तेलंगाना) में एक, जबकि दो केंद्रीय विद्यालय पंचकूला (हरियाणा) और रामपुर (उत्तर प्रदेश) में अर्धसैनिक बलों के कार्यालय परिसर में हैं। पुलिस उपायुक्त, द्वारका, अंकित सिंह ने कहा, द्वारका में सीआरपीएफ स्कूल को इस बारे में कोई संदेश या मेल नहीं मिला। हालांकि, हमें यह संदेश दिया गया कि सतर्क रहें। स्कूल ने छात्रों के लिए छुट्टी की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है।

वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा-टीएमसी सांसद

नई दिल्ली में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) बिल पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य बैठक से बाहर जाते हुए।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी, चेयरमैन की ओर फेंकी, एक दिन के लिए सस्पेंड

एक अजीबो-गरीब घटना में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को संसद में एक अहम वक्फ बैठक के दौरान हंगामा किया, जहां उन्होंने एक कांच की पानी की बोतल तोड़कर अध्यक्ष की ओर फेंकी। बनर्जी ने खुद को घायल कर लिया और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति पर चर्चा के लिए एकत्र हुए अन्य सांसदों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। बनर्जी को उनके इस नाटक के बाद वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। बाद में वे अपने हाथ पर पट्टी बांधकर साथी सांसदों के साथ बाहर आए।

बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भाजपा के अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी नोकझोंक के दौरान एक कांच की पानी की बोतल तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पैनल अध्यक्ष जगदंबिका पाल की ओर फेंकी। यह दूसरी बार है जब बनर्जी अजीब कारणों से चर्चा में आए हैं, पिछली बार उन्होंने संसद के पीठासीन अधिकारी की नकल की थी। इस कृत्य की भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने निंदा की थी।

सूत्रों के अनुसार, पैनल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर नौ-आठ मतों से वोट दिया, जिसमें पैनल अध्यक्ष के लिए उनके शब्दों के चयन और कांच की बोतल तोड़कर पाल की ओर फेंकने के लिए बनर्जी को एक दिन के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव था। बैठक समाप्त होने के बाद, बनर्जी ने घटना के बारे में पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद बनर्जी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता संजय सिंह बैठक कक्ष में वापस ले जाते हुए देखे गए। समिति ओडिशा के दो संगठनों के विचार सुन रही थी, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वकील शामिल थे, जब (शेष पृष्ठ 9)

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आयुध निर्माणी जबलपुर (ओएफजे) के विस्फोट स्थल पर निरीक्षण करते अधिकारी।

जबलपुर आयुध निर्माणी में विस्फोट, कई घायल

पीएनएस। जबलपुर

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आयुध निर्माणी खमरिया में मंगलवार सुबह एक शक्तिशाली विस्फोट में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। प्रतिष्ठान के अधिकारी ने बताया, विस्फोट सुबह करीब 9.45 बजे हुआ, जब कारखाने के एक रिफिलिंग सेक्शन में बमों में विस्फोटक सामग्री भरी जा रही थी। घायलों में से दो की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य कर्मचारी लापता है और संभवत: उस सेक्शन के मलबे में फंसा हुआ है, जिसमें विस्फोट हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे कुछ किलोमीटर दूर के लोगों ने भी सुना। आयुध निर्माणी खमरिया रक्षा उत्पादन विभाग के तहत प्रमुख गोला-बारूद उत्पादन इकाइयों में से एक है।

अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल हो गए और एक लापता कर्मचारी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, जो संभवत: इमारत के मलबे में फंसा हुआ है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के पीछे की असली वजह का पता चल पाएगा। अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री के फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मचारियों ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

पराली जलाने का मामला: हरियाणा के 24 अधिकारी निलंबित किए गए

● एडीए से लेकर सुपरवाइजर तक पर हुई कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

प्रतीकात्मक चित्र

हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं तो कम नहीं हो रही हैं अलबत्ता कृषि विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में 24 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कृषि विभाग में यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पराली के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिसमें मुख्य सचिव स्वयं पेश होकर अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट देंगे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को इस मामले में फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।

कृषि विभाग द्वारा मंगलवार को जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (एडीए) से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कर्मचारी भी शामिल है। कृषि विभाग के डायरेक्टर राज नारायण कौशिक की तरफ से 9 जिलों के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इसमें पानीपत, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पराली जलाने के बढ़ रहे केसों पर कार्रवाई न होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। इस बीच मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों तथा जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह रोजाना की रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय में भेजेंगे।

इस बीच विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिसार में कृषि विभाग ने मंगलवार को 11 मामले दर्ज किए हैं। कुरुक्षेत्र में अब तक 58 किसानों के फॉर्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की है। 58 और किसानों पर कार्रवाई की तैयारी है। 39 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को कागज सौंप दिए हैं। अंबाला में फसल अवशेष जलाने पर 35 किसानों पर कार्रवाई करते हुए कृषि अभिलेखों में रेड एंट्री की गई। 2 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। जींद में 38 जगहों पर पराली में आग लगी है। 38 किसानों की रेड एंट्री हुई और 17 पर मामला दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में तीन एफआईआर दर्ज करके चार किसानों को गिरफ्तार किया गया है। एक खेत के मालिक पर भी मामला दर्ज हुआ है। 23 किसानों की रेड एंट्री कर दी है। सिरसा में पराली जलाने पर 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैथल में पराली जलाने पर अब तक 14 मामलों की जांच के दौरान 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। (शेष पृष्ठ 9)

लाइलाज ट्रैफिक जाम
पायनियर

भारी ट्रैफिक जाम बन गया है गुरुग्राम की पहचान

● जिला प्रशासन ने की है शहर की सड़कों पर 18 हॉटस्पॉट की पहचान

परवेश शर्मा। गुरुग्राम

शहर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शहर की सड़कों पर 18 ऐसे स्पॉट की पहचान की है, जहां पर भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या है। अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों से इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। इन जगहों में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, सोहना रोड, दिल्ली-जयपुर हाईवे, शीतला माता रोड, पुरानी दिल्ली रोड और अन्य प्रमुख सड़कें शामिल हैं। शहर प्रशासन ने हाल ही में ट्रैफिक पुलिस को पत्र लिखकर पहचाने गए स्पॉट पर जाम कम करने को कहा है। अधिकारियों ने सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और कानून व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है, ताकि सड़कों पर जाम की समस्या से जल्दी निपटा जा सके।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज ने पायनियर को बताया, 'हम भीड़भाड़ कम करने और यातायात की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए अभियान चलाते हैं। हमने इन 18 हॉटस्पॉट पर यातायात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी बढ़ा दी है और नियमों का सख्ती से पालन कराया है। हम वाहन मालिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।'

यातायात भीड़भाड़ का एक और कारण बारिश है। कुछ घंटों की बारिश से गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में भारी जलभराव हो जाता है, जिससे शहर में यातायात बाधित होता है। यातायात पुलिस ने शहर में 55 से अधिक स्थानों की पहचान की है, जिसमें एक्सप्रेसवे पर प्रमुख मुख्य बिंदु शामिल हैं, जहां बारिश के कारण जलभराव हुआ है। विभिन्न स्थानों पर जमा बारिश का पानी दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर यातायात की आवाजाही को भी बाधित करता है। एक्सप्रेसवे के इस प्रमुख जंक्शन पर यातायात की आवाजाही धीमी हो गई, खासकर जब दोपहिया और चार पहिया वाहनों को बारिश के पानी के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा।

पहचाने गए 18 स्थानों में एंबियंस आइलैंड, इफ्को चौक, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उमंग भारद्वाज चौक, सोहना चौक, खेड़की दौला टोल प्लाजा, द्वारका एक्सप्रेसवे, हुडा सिटी सेंटर, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक अंडरपास और सुभाष चौक शामिल हैं। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से गलत पार्किंग, खतरनाक सामान की ढुलाई और सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं देने वाले पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए अभियान शुरू करने को कहा। शहर के यातायात पुलिस विभाग ने कहा कि उन्होंने इन हॉट स्पॉट पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी है और ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) के अनुरूप उपाय किए हैं। पिछले महीने यातायात पुलिस ने 24,000 से अधिक जुर्माने जारी किए। अपराधों में गलत साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट के सवारी करना, गलत पार्किंग, सिग्नल जंप करना, कम उम्र में गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ओवरलोडिंग और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना शामिल है। विज ने कहा कि गुरुग्राम में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वे खुद को और अपने परिवार को सड़क दुर्घटनाओं से बचा सकें (शेष पृष्ठ 9)

पिछली सरकारों के कारण किसानों-उद्यमियों को झेलना पड़ा था दंश: योगी

● यूपी देश का पहला ऐसा राज्य, जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए बनाई पॉलिसी: सीएम

मुख्यमंत्री ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का किया उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेडिमेट गारमेंट्स में दुनिया के छोटे-छोटे देशों की धमक है। जिन लोगों के पास संसाधन कम और संभावनाएं न के बराबर हैं, वे आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास संभावना और संसाधन भी है। काम चाहने वाली आधी आबादी के बड़े तबके को रेशम उत्पादन, प्रोसेसिंग, रेडिमेड गारमेंट, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें तो दुनिया में रेडिमेड गारमेंट में धमक बनाने वाले देशों का स्थान उत्तर प्रदेश व भारत ले सकता है। इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने रेशम उत्पादन को 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। एक समय वह जरूर आ सकता है, जब यूपी का किसान रेशम उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन किया। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों,उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पं. दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। सीएम ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश ने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए पॉलिसी बनाई। 75 जनपदों के लिए वहां के एक उत्पाद को चिह्नित करते हुए आगे बढ़ाया। यही कारण है कि 75 जनपद का यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट कहा। ओडीपीओपी को सरकार ने मार्केट, डिजाइनिंग, पैकेजिंग से जोड़ा तो इससे रोजगार का सृजन हुआ और परंपरागत उत्पादों का एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हुआ। यूपी के 75 जनपदों में 75 जीआई प्रोडक्ट हैं, जिन्हें देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। यह संभावना यूपी में हैं। वाराणसी, भदोही व मुबारकपुर की साड़ियों के माध्यम से भी यूपी के पोटेंशियल को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। सिल्क एक्सपो इस फील्ड में यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बने, इस पर हमें प्रयास करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा सदैव से प्रचलित रहा है। जीव सृष्टि व किसी भी व्यक्ति के लिए हवा-पानी तो आवश्यक है ही, लेकिन रोटी, कपड़ा ,मकान भी आवश्यक है। कपड़ा न सिर्फ जीवन की आवश्यकता है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही रोजगार सृजन का भी सशक्त माध्यम भी है। रेशम, प्राचीन काल से ही इसकी अलग-अलग पद्धतियां रही हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में इस फील्ड में अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। उप्र ने पिछले कुछ समय में प्रगति की है। पहले की तुलना में यह संतोषजनक है, लेकिन अभी उप्र जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से यह अपर्याप्त है। यहां अत्यंत संभावनाएं हैं।

सीएम योगी ने कहा कि सभी को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। यूपी में वाराणसी-भदोही, आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक, चाहे वह मुबारकपुर की साड़ी हो या वाराणसी की। सिल्क कलस्टर विकसित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। वाराणसी की सिल्क साड़ियां पूरे देश में हर मांगलिक कार्यक्रम के लिए पसंद बनती हैं। काशी विश्वनाथ धाम बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं व पर्यटकों की बढ़ी संख्या ने इस व्यापार को नई ऊंचाई दी है। वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है।

विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्रों में 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन

● अब तक कुल 15 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 09 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उप निर्वाचन 2024 के तहत 22 अक्टूबर 2024 को 05 विधानसभा क्षेत्रों में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस प्रकार अब तक कुल 15 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गये। मीरापुर (मुज़फ्फरनगर) विधानसभा के लिए 5 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी से वकार अजहर, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से जाहिद हुसैन, निर्दलीय प्रत्याशियों में राजबाल सिंह राणा, रजनीश कुमार तथा मो. अनस है। इस प्रकार अब तक कुल 06 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया है। कुदंरकी (मुरादाबाद) विधानसभा के लिए आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से चांद बाबू ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। गाजियाबाद (गाजियाबाद) विधानसभा के लिए 2 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, इसमें सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभाष पार्टी) से रवि कुमार पांचाल, निर्दलीय प्रत्याशी में विजय कुमार अग्रवाल ने नामांकन पत्र किया। फूलपुर (प्रयागराज) विधानसभा के लिए 2 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, इसमें परिवर्तन समाज पार्टी से उषा, प्रगतिशील समाज पार्टी से योगेश कुमार कुशवाहा ने नामांकन पत्र किया। कटेहरी (अम्बेड़कर नगर) विधानसभा के लिए 02 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, इसमें समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा, बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा ने नामांकन किया। इस प्रकार अब तक कुल 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया। खैर (अ.जा.) (अलीगढ़), 213-सीमामऊ (कानपुर नगर) तथा 397-मझवां (मिर्जापुर) में अब तक कुल नामांकन शून्य है।

सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव: अजय राय

लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नौ सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) मिलकर लड़ेंगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राय ने कहा, समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के नतीजे चाहे जो भी हों लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया मिलकर उपचुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने 10 में से पांच सीट की मांग की थी हालांकि सपा ने पहले ही सात सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कांग्रेस को दो सीट से ही संतोष करना पड़ा। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अदालत में मुकदमा लंबित होने के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहा है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस के साथ हमारा समझौता हो गया है। दस में से दो सीट खैर (अलीगढ़) और गाजियाबाद पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जबकि आठ पर सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा करहल, सीसामऊ फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझावां और मीरापुर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। लोकसभा चुनावों में विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की नौ सीट रिक्त हुईं जबकि सीसामऊसीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने से रिक्त हुई। सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया।

युवा शक्ति को कुशल बनाने का आधार बन रही 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना'

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● प्रदेश में वर्ष 2021 से 2023 के बीच 19.84 लाख टैब व 26.91 लाख स्मार्टफोन समेत कुल 46.75 लाख गैजेट हो चुके हैं वितरित

उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला राज्य है। ऐसे में, प्रदेश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने और उसे वर्तमान व भविष्य की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रदान करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना बेहद प्रभावी साबित हो रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2021 से 2023 के बीच 19.84 लाख टैब व 26.91 लाख स्मार्टफोन समेत कुल 46.75 लाख गैजेट वितरित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 13.14 लाख गैजेट (जिनमें 12.94 लाख स्मार्टफोन व 20 हजार से ज्यादा टैबलेट शामिल हैं) को पात्र विद्यार्थियों को आवंटित करने पर योगी सरकार का विशेष फोकस है। ऐसे में, प्रदेश में पात्र विद्यार्थियों को गैजेट्स के वितरण की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले जिलों को चिह्नित किया गया है जिसमें से 8 जिलों का परिणाम 100 प्रतिशत रहा है। वहीं, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण की दिशा में 6 जिलों में 70 प्रतिशत से ज्यादा आवंटन की दर रही है और 10 टॉप जिलों में 69 प्रतिशत से ज्यादा सफलतापूर्वक आवंटन हो चुका है।

सीएम योगी के विजन अनुसार, प्रदेश में युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए न केवल स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण हो रहा है बल्कि डिजी शक्ति पोर्टल के जरिए सरकार की योजनाओं और कौशल विकास के विभिन्न कोर्सेस का एक्सेस व एंड टू एंड मॉनिटरिंग उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना को प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2022-23 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को प्रदेश में 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। ऐसे में, परियोजना के जरिए उच्च व उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कोर्स, कौशल विकास के प्रशिक्षणार्थी तथा पैरामेडिकल व नर्सिंग जैसे कोर्सेस के विद्यार्थियों को टैब व स्मार्टफोन वितरण के जरिए लाभान्वित किया जाता है। सीएम योगी के युवा सशक्तिकरण के विजन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश में स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना बेहद सार्थक कदम बनकर उभरा है। प्रक्रिया के अंतर्गत, पात्र विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टैब वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के 8 जिलों में स्मार्टफोन वितरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।

शानदार जल प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश को मिला राष्ट्रीय जल अवार्ड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की ओर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात-पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर प्रदेश में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की मुहिम में किए गए कार्यों और जल संरक्षण की दिशा में किए गए अभिनव प्रयोगों की तारीफ की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी उत्तर प्रदेश द्वारा बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने और जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों को सराहा। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश ने 2023 में सबसे तेजी से 17,900 गांवों को हर घर नल से जल पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया था। योगी सरकार के निर्देश पर 2023 में डायरेक्टर ग्राउंड वॉटर-सचिव नमामि गंगे रहते हुए डॉ. बलकार सिंह ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए कई अभिनव प्रयोग किए थे। जिसका लाभ जल प्रबंधन के साथ-साथ किसानों को सिंचाई में भी मिला। प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कुल 6000 से अधिक चेक डैम और 1000 तालाबों का निर्माण किया गया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिला प्रदर्शन कर रहे बीबीएयू छात्रों से

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में जो नियमावली छात्रों पर लागू की जा रही है इससे पूर्णतय: छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके विरोध में बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय के छात्र पिछलों दो दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उक्त घटना के संज्ञान में आने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय पहुंचा जहां प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने धरने पर बैठे छात्रों से बात चीत कर उनकी समस्याओं को जाना। प्रतिनिधिमंडल से समक्ष अपनी बात रखते हुए धरने पर बैठे बीबीएयू छात्रों ने बताया कि बीबीएयू प्रशासन के मनमाने और तानाशाहीपूर्ण रवैए के खिलाफ छात्रों द्वारा किये जा रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज दूसरा दिन है। परन्तु प्रशासन की ओर से छात्रों से बातचीत करने लिए अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि हम बीबीएयू के छात्र मांग करते हैं कि तानाशाहीपूर्ण शासन व्यवस्था समाप्त कर समाज के दलित छात्रों के मौलिक अधिकारों के दमन को रोका जाए। धरने पर बैठे छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह जी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की ओर समर्थन देते हुए लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़कर उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह जी के साथ भारतीय राष्ट्रीय संगठन (एनएसयूआई) के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रिन्स प्रकाश, कार्यकर्ता दिव्यांश शुक्ला, उत्कर्ष मिश्रा, लोरिक यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

बहराइच में दंगा भाजपा ने कराया है: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बहराइच में दंगा भाजपा ने कराया है। दंगा कराने में भाजपा के नेता शामिल है। भाजपा के विधायक ने खुद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दंगा कराने, षड्यंत्र कराने का एफआईआर कराया है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह बात मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि बहराइच दंगे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट हो रहा है। दंगा साजिश और षड्यंत्र का नतीजा है। पुलिस ने दंगाइयों को खुली छूट दी थी। पुलिस को हटा देना या खुल छूट दे देना बड़ी साजिश का हिस्सा है। यादव ने कहा कि हिटलर भी इसी तरह से काम करता था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सैनिक बनाकर आगे कर देता था। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास महंगाई, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। वह घबराई हुई है इसीलिए दंगा करा रही है। भाजपा आरक्षण छीन रही है। संविधान के अनुसार आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे लागू नहीं होने दे रही है। निवेश के नाम पर जो झूठ फैलाया था उसका पर्दाफाश हो गया है। कहीं उद्योग कहीं कारखाना नहीं लगा। भाजपा सरकार ने अगर कोई काम किया होता और निवेश लाया होता तो दिखाई देता। लेकिन कहीं भी कोई उद्योगधंधा और कारखाना लगता दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली महंगी है। किसान को खाद नहीं मिल रहा है। फसलों की खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं। पिछड़े, दलित, अलपसंख्यक और गरीब लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था जीरो हो गई। हालात यह है कि महिला पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानपुर में महिला कांस्टेबल के साथ भी घटना हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में बनाये गये पहले डीजीपी भाजपा सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत दबाव में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पा रही है। निष्पक्ष कार्यवाही करने पर संस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भाजपाईयों ने पुलिस के भी हथकड़ी लगा दी है। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। इसीलिए किसी भी घटना पर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो पा रही है। देश में सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउण्टर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को कस्टोडियल डेथ और फेक एनकाउण्टर में नम्बर एक बना दिया है।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

मैं, अफरोज खानम (जिसे अफरोज या अफरोज बानो के नाम से भी जाना जाता है), पत्नी अब्दुल वहाब खान निवासी ग्राम व पोस्ट पूरे शिवा बख्तावर, जिला गोंडा, मैने दिनांक 07. 10.2024 को नोटरी त्रिपुरारी प्रसाद उपाध्याय के समक्ष निष्पादित एक हलफनामे के माध्यम से मैं पुष्टि करती हूं कि मेरा आधिकारिक नाम, अफरोज खानम है तथा अब से, मुझे सभी उद्देश्यों और दस्तावेजों के लिए इसी नाम से जाना जाएगा।

सूचना

मैने अपना नाम राशिद से बदलकर राशिद खान पुत्र ताज मोहम्मद् पता पालपुर गरौंदा अयोध्या, भविष्य के लिए कर लिया है।

सूचना

मैं, Rashmi Singh पुत्री Raghuvir Singh, निवासी, अर्जुनपुर बीसलपुर, मंगलपुर, सिकंदरा, कानपुर देहात,यह घोषणा करती हूँ कि मेरे सीबीएसई 10वीं और 12वीं प्रमाणपत्रों में मेरा और मेरे पिता का नाम गलत तरीके से Rashmi Devi और Raghuveer Singh लिखा गया है। सही नाम Rashmi Singh और Raghuvir Singh है।

महाकुंभ 2025 के निर्माण कार्यों से बढ़ी प्रयागराज में होटल्स व होम स्टे की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ प्रयागराज

सानातन आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 को सीएम योगी के मार्गदर्शन में दिव्य, भव्य, नव्य और ग्रीन बनाने के कार्य प्रयागराज में जोर शोर से चल रहे हैं। प्रयागराज में न केवल संगम क्षेत्र बल्कि पूरे शहर में निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। शहर में सड़कों, चौराहों, फ्लाई ओवर, पार्कों और होटलों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है।

इसके चलते शहर में पिछले कुछ महीनों से कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंसट्रक्शन कंपनियां डेरा जमाए हुए हैं। इन कंपनियों के इंजीनियर, अधिकारियों और कर्मचारियों के शहर में ठहरने की जरूरत ने प्रयागराज निवासियों, होटल और मकान मालिकों को आय का नया स्रोत प्रदान किया है।प्रयागराजवासी महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर आशान्वित और उत्साहित हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर पूरे शहर, आस-पास एवं मेला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के अनुरूप सभी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य 15 दिसंबर तक पूरे किये जाने हैं। कई सरकारी व निजी कंसट्रक्शन कंपनियां शहर में अपने प्रोजेक्टस तेजी से पूरे करने में जुटी हैं। इसके चलते इन कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर में ठहरने के लिये किराये के मकान, होटल व होम स्टे की जरूरत पड़ रही है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक शहर में वेल फर्निश्ड, नॉन फर्निश्ड मकानों की मांग बढ़ी है। प्रयागराज के प्रापर्टी डीलरों का कहना है बड़ी संख्या में उनके पास क्वेरी आ रही है। इसके दृष्टिगत कई मकान मालिक अपने खाली पड़े कमरों और मकानों को होम स्टे में बदल रहे हैं। जहां लोगों को रहने, खाने व अन्य दैनिक जरूरतों की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही, रेस्टोरेंट्स व टिफिन संचालकों की भी आमदनी बढ़ी है। प्रयागराज होटल्स व रेस्टोरेंट्स ओनर्स असोशिएशन के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह का कहना है कि महाकुंभ 2025 को लेकर शहर के सभी होटल्स व रेस्टोरेंट संचालक उत्साहित हैं। वो अपने-अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में महाकुंभ के मुताबिक सुविधाओं का निर्माण करा रहे हैं। शहर के होटल्स में कई नेश्नल और मल्टीनेश्नल कंपनियों के लिए कमरे बुक हैं व उनके कई अधिकारी पिछले कई दिनों से उनमें रह भी रहे हैं।

मोबाइल टॉवर्स पर हाई रिजॉल्यूशन कैमरे से होगी निगरानी

प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल लाइसेंस वाले सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के अलावा मोबाइल टॉवर्स पर हाई रिजॉल्यूशन वाले कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा। ये कैमरे इतने हाई रिजॉल्यूशन के होंगे कि संगम तट, विभिन्न घाट और प्रमुख मार्गों पर होने वाली एक-एक गतिविधि पर नजर रखेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में कुंभ पुलिस की मदद करेंगे। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ के दौरान कुंभ पुलिस द्वारा पूरे मेला क्षेत्र में 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिसमें आधे से ज्यादा एआई लाइसेंस्ड युक्त कैमरे भी शामिल हैं। वहीं एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी के अनुसार, इस बार महाकुंभ 2025 में भारी पैमाने पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। खासतौर पर प्रमुख स्नान के दौरान ये संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हर अधिकारी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है।

3.50 करोड़ की लागत से 'शहीद वॉल' बनकर तैयार

लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ महाकुंभ जैसी सनातन धर्म की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण का कार्य कर रही तो वहीं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की बलिदान की गाथा को भी जन-जन तक पहुंचाने में जुटी है। शहीद चंद्र शेखर आजाद की शहादत स्थली प्रयागराज में गुमनाम शहीदों की स्मृति में शहीद वॉल का निर्माण इसी का हिस्सा है। ये ऐतिहासिक स्मारक महाकुंभ के दौरान पर्यटकों को प्रयागराज के बलिदानी सपूतों की स्मृति से परिचित कराएगा। कुंभ नगरी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस बार महाकुंभ में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ शहीदों के बलिदान की गाथा से भी रूबरू हो सकेंगे। इसी क्रम में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में देश की आजादी में अपना बलिदान करने वाले गुमनाम बलिदानियों को चिन्हित कर उनके बलिदान की गाथा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए शहीद वॉल का निर्माण कराया है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा वनस्पति विज्ञान विभाग में वित्तपोषित शोध परियोजना हेतु एक शोध सहायक की आवश्यकता है। साक्षात्कार दिनांकः 05.11.2024 को महाविद्यालय में होगा।
अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट lbsdc.org.in देखें।

प्रो० रवीन्द्र कुमार
प्राचार्य

डॉ० रेखा शर्मा
मुख्य अन्वेषक

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Indian Bank (A Govt. of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम-8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (धारा 54, 2002) की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3, 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।
ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व-साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय **इंडियन बैंक** के अधीन रहेगा।
उधारकर्ता / जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
विवरण निम्नुसार हैं:-

क्र. सं.	ऋणी / प्रोपराइटर / जमानतकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
	शाखाः बालागंज शाखा		
1.	1. श्रीमती शैल कुमारी पत्नी श्री राजेंद्र कुमार तिवारी (ऋणी एवं बंधककर्ता), डी-946, नई बस्ती, पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017 2. श्री राजेंद्र कुमार तिवारी पुत्र श्री धर्मदत्त तिवारी (जमानतकर्ता), डी-946, नई बस्ती, पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017 3. श्री अश्वनी कुमार राय पुत्र बटुक राय (जमानतकर्ता), मकान सं. सी-13/70/73, आवास विकास कॉलोनी, सी ब्लॉक, विषम नंबर, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017	प्लॉट सं. 55 पर डी-946, खसरा सं. 709 का भाग, नई बस्ती पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 259.293 वर्ग मी0, **मालिकः** श्रीमती शैल कुमारी पत्नी श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, **चौहद्दीः पूर्व**- सड़क 20 फीट, **पश्चिम**- श्री जगदीश पाण्डेय का मकान, **उत्तर**- श्री राज बहादुर सिंह का मकान सं. डी945, **दक्षिण**- प्लॉट सं. 55ए	20.02.2024 19.10.2024 रु. 21,63,804.00 एवं उसपर ब्याज
	शाखाः इंदिरा नगर शाखा		
2.	1. मेसर्स यश कार बाजार प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी) पता-1: 10, द्रौपदी विहार, लक्ष्मण पुरी, फैजाबाद रोड लखनऊ-226016 पता-2: 2, माउंट कार्मेल स्कूल रोड, हनुमान मंदिर के सामने, बादशाहनगर क्रॉसिंग, महानगर, लखनऊ 2. श्रीमती रेशमा वसीम पत्नी मोहम्मद वसीम (जमानतकर्ता), 10, द्रौपदी विहार, लक्ष्मण पुरी, फैजाबाद रोड लखनऊ-226016 3. मोहम्मद वसीम (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता), 10, द्रौपदी विहार, लक्ष्मण पुरी, फैजाबाद रोड लखनऊ-226016	प्लॉट सं. 10 के सभी भाग व खण्ड, खसरा सं. 149 का भाग, द्रौपदी बिहार, दूसरा फेस, लक्ष्मणपुरी, ग्राम-शेखपुरी, कसैला, वार्ड-गोमती नगर, लखनऊ। विक्रय विलेख के अनुसार बुक संख्या-1, जिल्द संख्या-20152 पृष्ठ संख्या 23 से 46 क्रमांक संख्या-1595/01 दिनांक 05.03.2001 को उप रजिस्ट्रार लखनऊ-2 में पंजीकृत। **चौहद्दीः पूर्वः** प्लॉट सं. 09, **पश्चिमः** सड़क 40 फीट चौड़ी, **उत्तरः** सड़क 40 फीट चौड़ी, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 11	16.08.2024 21.10.2024 रु. 50,96,970.00 एवं उसपर ब्याज

दिनांकः 23.10.2024 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

बच्चों से जुड़ी बीमारियों को लेकर संसद और सड़क पर मैंने किया आंदोलनः योगी

सीएम योगी ने एसजीपीजीआई में 1,147 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017 से पहले जहां प्रदेश के 18 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज प्रदेश के 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में आज एमबीबीएस और पीजी की सीटें पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हुई हैं। प्रदेश में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की आवश्यकता काफी समय से थी क्योंकि प्रदेश में बच्चों से जुड़ी बीमारियों को मैंने नजदीक से देखा है। इसको लेकर सांसद रहने के दौरान संसद और सड़क पर आंदोलन भी किया। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एसजीपीजीआई की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आने के बाद डबल इंजन के प्रयास से जल्द ही एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर मूर्त रूप लेगा। हमने जापानी इंसेफेलाइटिस का समाधान करने में सफलता पायी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते थे। सीएम योगी ने कहा कि एसजीपीजीआई देश और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। ऐसे में, प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की प्राथमिकता होती है कि उसे यहां बेड प्राप्त हो जाए, लेकिन इसको लेकर काफी समस्या अक्सर सामने आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इससे पहले सीएम ने सलोनी हार्ट सेंटर, एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने दीपावली से पहले एसजीपीजीआई को इन योजनाओं के लिए बधाई दी।

संस्थान समयबद्ध तरीके से आगे चले इसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, एसजीपीजीआई प्रो. राधा कृष्ण धीमन, सलोनी हार्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष मृणालिनी (मिली) सेठ, हिमांशु सेठ, यूएस के डॉ. वी मोहन रेड्डी आदि मौजूद थे।

सलोनी हार्ट सेंटर में मिलेगी 200 बेड की विश्व स्तरीय सुविधाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई में 1,147 करोड़ रुपये की एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू, सलोनी हार्ट सेंटर (प्रथम चरण), कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी का छात्रावास का उद्घाटन और एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेंटर (द्वितीय चरण), रैन बसेरा का शिलान्यास किया। इसी के तहत एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में 575 बेड्स के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।

यहां 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें हार्मोंस, डायबिटीज, पीडियाट्रिक आईसीयू, इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी समेत अन्य बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे होगा। सीएम योगी ने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर के पहले चरण की शुरुआत हो गयी है। वहीं, सेंटर के दूसरे चरण का एमओयू साइन हो गया है। इसके जरिये सलोनी हार्ट सेंटर 200 बेड की विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर साल 5 हजार बच्चों की हार्ट से जुड़ी हुई गंभीर सर्जरी कर उन्हे सुखमय जीवन देगा। साथ ही, हर साल दस हजार बच्चों को सेकेंड ओपिनियन आदि उपलब्ध कराएगा। इसके लिए, सलोनी हार्ट फाउंडेशन के प्रयासों के हम सभी आभारी हैं।

रैन बसेरे में तीमारदारों को 20 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओएनजीसी के 51 करोड़ के सीएसआर फंड से एक हजार बेड के रैन बसेरा के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो गयी है। इससे यहां आने वाले तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां पार्किंग और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जहां तीमारदारों को 15 से 20 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। वहीं, 200 छात्रों के लिए कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी छात्रावास का निर्माण पूरा हो चुका है।

इन परियोजनाओं का उद्घाटन

एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू, सलोनी हार्ट सेंटर (प्रथम चरण), कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी का छात्रावास

इन परियोजनाओं का शिलान्यास

एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेंटर (द्वितीय चरण), रैन बसेरा

नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक

नालों की सफाई के लिए खरीदे जाएंगे 20 और रोबोट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

शहर के नालों की सफाई के लिए रोबोट की खरीद से नाले उफनाने की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। एक माह में 20 रोबोट को खरीदने पर सहमति बनी है। स्ट्रीट लाइटें के चोरी होने की घटनाओं से कार्यकारिणी को अवगत कराने पर एबीसी की वायर विद्युत विभाग को डालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लेसा को नगर निगम के पार्कों में ट्रांसफारमर्र लगाए जाने से पूर्व नगर निगम को जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यकारिणी में गुलालाघाट पर अत्येंष्टि के दौरान मृतकों के परिजनों से अवैध वसूली के मुद्दे का निस्तारण किया गया है।

मंगलवार को महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम कार्यकारिणी की हुई। बैठक में नगर के विकास से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई व जनहित के लगभग समस्त प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। मुख्य रूप से पार्षद हरिश्चंद्र लोधी के रोबोट की खरीद, मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रणजीत सिंह के गुलालाघाट पर अवैध वसूली और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर वार्ता हुई, जिन प्रस्तावों को पास किया गया। बैठक में लेसा के मुख्य अभियंता अपने अन्य अधीनस्थों के साथ कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हुए, जिस पर महापौर द्वारा लेस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहाँ भी आपके विभाग द्वारा एबीसी के वायर डाले जा रहे हैं उसमें स्ट्रीट लाइट तत्काल लगाई जाये। जिससे स्ट्रीट लाईट चोरी पर रोकथाम लग सके। कार्यकारिणी में लेसा के अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि पार्कों में जो भी ट्रांसफ र्मर लगाए जाएं उसकी जानकारी नगर निगम को जरूर दी

गुलालाघाट पर अत्येंष्टि के दौरान मृतकों के परिजनों से अवैध वसूली पर रोक लगाने के निर्देश

जाए । बैठक में जल निगम के अधिकारियों को महापौर ने निर्देशित किया कि आपके विभाग ने शहर में जो भी योजनाएं की कार्यवाही प्रचलित हैं उनका संपूर्ण विवरण नगर निगम को उपलब्ध कराए। समस्त जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंता या सुनिश्चित करेंगे की शहर में सभी ओवर ब्रिज के नीचे अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और साफ सफाई की जाए वह अन्य जनहित की योजनाएं जल्द बनाई जाए। साथ ही 3 माह मे वेडिंग जोन सुव्यवस्थित की जाये। वहीं नगरीय क्षेत्रों में यातायात के सुगम प्रबन्धन उन के दृष्टिगत टैम्पो. टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा के संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टैम्पो . टैक्सी एवं क ऑटोरिक्शा संयुक्त मोर्चा, लखनऊ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 18 मई 2023 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 45 ठहराव स्थलों पर ऑटो व टैम्पो समिति के माध्यम से संचालन के लिए एवं 27 पिक एण्ड ड्रॉप स्थलों के अनुमोदन के लिए अधिशाषी अभियन्ता ट्रैफिक द्वारा भेजा प्रस्ताव पर उप समिति बनाने के लिए महापौर को अधिकृत किया गया। उप समिति में पार्षद सौरभ सिंह मोनू, मुकेश सिंह मोंटी, पीयूष दीवान एवं लईक आगा को नामित किया गया। कार्यकारिणी में हरिश्चन्द्र लोधी ने कहा हर वार्ड में रोबोट हफ्ते में एक दिन भी नहीं मिल पाता है अगर वह वार्ड में आ जाता है तो फिर से उसको कॉल आ जाता है कि आप वापस आ जाओ यहाँ काम है और उस वार्ड का काम नहीं हो पाता है। नगर आयुक्त ने कहा मेरा इसमें विचार है रोबोट हमें मार्केट में नहीं मिलते हैं वह हमें खरीदने पड़ते हैं अगर कार्यकारिणी निर्णय ले तो हम 15वें वित्त से रोबोट खरीद सकते हैं। हरिश्चन्द्र लोधी ने कहा पिछली कार्यकारिणी में इस रोबोट के मुद्दे पर बात हुई थी। 20 रोबोट खरीदने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया था, जिस पर अगले एक माह में 20 रोबोट की खरीद किये जाने का फैसला लिया गया।

यह कार्य भी कराए जाएंगे

- सफाई और स्वच्छता को लेकर नगर निगम क्षेत्र में सफ ाई और स्वच्छता के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिए
- सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए योजनाएं बनाये जाने के निर्देश दिए
- जल आपूर्ति जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए।
- सामाजिक जन कल्याण योजनाएं विभिन्न सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

इन्हें मिली मंजूरी

- साहित्य सूर पद्मविभूषण पं. अमृताल नगर, चौक के सौन्दर्याकरण की अति आवश्यकता है। यह चौराहा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व पूर्व नगर विकास मंत्री द्वारा बनवाया गया है। चौक पर्यटकों व व्यापारियों का मुख्य स्थल है और साहित्य सूर पं. अमृतलाल नागर का मुख्य क्षेत्र रहा है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पं0 अमृतलाल नागर के जन्म पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।
- चौक वार्ड में लाजपतनगर प्राथमिक विद्यालय से नींबू पार्क तक वेंण्डिग जोन निर्माण का प्रस्ताव है। अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए।
- महाराजा अग्रसेन पार्क की जर्जर बाउण्ड्री जो गिर गई है शीघ्र निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- चौक खुन.खुन जी रोड मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- मौलवीगंज वार्ड में गंगा प्रसाद रोड के किनारे छोटा वेन्डिंग जोन बनाने की मंजूरी

अब म्यूटेशन के लिए खर्च करने होंगे 10 हजार

लखनऊ नगर निगम सीमा में अब म्यूटेशन के लिए 10 हजार रुपए खर्च करने होंगे। अब तक प्रापर्टी की कीमत का एक फीसदी म्यूटेशन शुल्क लिया जाता था। अग एक करोड़ की कोई प्रॉपर्टी, तो म्यूटेशन क लिए एक लाख रुपए देने होते हैं। नया नियम लागू होने पर 10 हजार रुपए देने होंगे। यह शुल्क 5 श्लैब में फिक्स कर दिया गया है। नया शुल्क तत्काल प्रभाव से बुधवार (23 अक्टूबर) से लागू होगा। वहीं नगर निगम सूत्रों की मानें तो यह रेट कम करने से विभाग को 25 करोड़ का नुकसान होगा।

विवेकानंद हास्पिटल पर विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश

लखनऊ के प्रतिष्ठित हास्पिटल विवेकानन्द हास्पिटल जो कि जोन-3 के अन्तर्गत विवेकानन्द नगर में स्थित है। उक्त हास्पिटल के द्वारा दी जाने वाली सभी मेडिकल सेवाएं प्राइवेट हास्पिटल की भाँति दी जाती है। हास्पिटल एक बहुत बड़े भू-भाग पर संचालित हो रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से हास्पिटल के द्वारा नगर निगम को टेक्स नहीं जमा किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।

अंत्येष्टि पर अवैध वसूली का किया विरोध

गुलाला श्मशान घाट में नगर निगम नियमावली का बोर्ड उचित स्थान पर नहीं लगा है जिसके कारण वहीं के पण्डों एवं कर्मचारियों के द्वारा मृतक के परिवारजनों से अवैध रूप से पैसा वसूला जाता है। स्थानीय पण्डा टिंकू पाण्डेय द्वारा अन्तिम संस्कार के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 600 रूपये की जगह 1500 रुपये से 2000 रूपये तक वसूला जाता है। पैसा न देने पर मृतक की अंत्येष्टि रसीद देने से मना किया जाता है। सफ ाई के नाम पर जबरन 200 रूपये अलग से लिया जाता हैए जबकि अन्तिम संस्कार के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 600 रूपये में सफाई, गौदान, फूल चुनना इत्यादि शुल्क शामिल रहता है। मुखाग्नि में उपयोग होने वाला पतावर का भी 200 रूपये लिया जाता है, जबकि इसका मूल्य बाजार में 50 रूपये है। लकड़ी न जलने पर रार नामक प्रदार्थ को पण्डों के द्वारा 300 रूपये प्रति किलो बेचा जाता है, जबकि इसका मूल्य बाजार में 100 रूपये प्रति किलो है। इस तरह से गुलाला श्मशान घाट के पण्डा (टिंकू पाण्डेय) के द्वारा नगर निगम नियमावली के विरूद्ध मृतक परिवारजनों से जबरन अवैध वसूली की जा रही है जिससे नगर निगम शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। गुल्लाला घाट की उपरोक्त सभी समस्याओं के निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिए गए।

गुलाला श्मशान घाट पर लगेंगे नए गेट

गुलाला श्मशान घाट के अन्तर्गत शव दफन वाले स्थान की बाउण्ड्री के दोनों गेट टूट गये हैं जिससे कुत्ते घुसकर मिट्टी खोदकर दफन किये गये शवों को खा जाते है। अक्सर इस कारण मृतक परिवारजनों के सदस्य पुलिस कार्यवाही करते हैं। स्थानीय पण्डों एवं अन्य कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है जो एक गम्भीर समस्या है। ल उक्त शव दफन स्थल की बाउण्ड्री पर लोहे के गेट लगाकर उस स्थल को सुरक्षित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

सीसीटीवी लगाने की मिली मंजूरी

गुलाला श्मशान घाट में रात्रि 8 बजे के बाद अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है। ये अराजक तत्व वहाँ पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं गाली-गलौज करते हैं। अनैतिक कार्य भी किये जाते है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। कृपया उक्त पूरे परिसर में सर्विलांस, सीसी टीवी कैमरे लगाकर सुरक्षित करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी में भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शीघ्र कार्य कराने के निर्देश दिए गए।साथ ही उक्त स्थल पर शौंचालय व टॉयलेट बनवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।

लखनऊ में डेंगू के 56 केस आये सामने

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ जनपद में डेंगू की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को जनपद में डेंगू के 56 केस सामने आये हैं। जिन इलाकों से डेंगू के रोगियों के मिलने की पुष्टि हुई हैए उनमें अलीगंज-8, इन्दिरानगर-7, बीकेटी-3, चिनहट-3, ऐशबाग-4, सिल्वर जुबली-7, चन्दरनगर-9, सरोजनीनगर-4, मोहनलालगंज-2, एनके रोड-5, गोसााईगंज-2, टूडियागंज-2) धनात्मक रोगी पाये गये। माह जनवरी 2024 से अब तक जनपद में डेंगू के कुल 1562 एवं मलेरिया के 460 धनात्मक रोगी पाये गये। आज लगभग 1083 घरों एवं आस-पास मच्छरजनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया और कुल 8 घरों में मच्छरजनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। नगर मलेरिया इकाई एवं जिला मलेरिया अधिकारी की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलो/भवनों का निरीक्षण किया गया तथा लार्वा रोधी रसायन का छिडकाव किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम लखनऊ की टीमों द्वारा काकोरी कोठी कैसरबाग, शान्ति भवन के पास राजेन्द्रनगर, सेक्टर-एफ गौशाला जानकीपुरम, एमएच ग्रैण्ड लॉन यादव जनरल स्टोर, दयानन्द पुरम अर्जुनगंज, तपोवन नगर मेट्रो स्टेशन, मर्दन खेडा प्राथमिक विधालय के पास आलमनगर वार्ड, पटेल चिकित्सालय फरीदीनगर, रीजनल आफस इग्नू के आस-पास क्षेत्रों में सघन मच्छर रोधी अभियान चलाया गया तथा क्षेत्र में साफ-सफाई, लार्वा रोधी रसायन का छिडकाव एवं फागिग का कार्य कराया गया। क्षेत्रीय जनता को घर के आस-पास पानी जमा न होने, पानी से भरे हुए बर्तन एवं टंकियों को ढंक कर रखें, हर सप्ताह कूलर के पानी को खाली करके साफ कपड़े से पोछ कर सूखा एवं साफ करने के बाद ही पुनः प्रयोग में लाने, पूरी बांह के कपड़े पहनने, बच्चों को घर से बाहर न निकलने, मच्छर रोधी क्रीम लगाने एवं मच्छरदानी में रहने तथा डेंगू एवं मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें सम्बंधित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी।

सआदतगंज व तालकटोरा क्षेत्र में दो अवैध निर्माण सील

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में

तालकटोरा और सआदतगंज क्षेत्र में 2 अवैध निर्माण को एलडीए द्वारा सील किया गया। विहित प्राधिकारी द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस देकर सीलिंग आदेश दिए थे। आदेश पर एलडीए प्रवर्तन दल द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गयी।

मंगलवार को एलडीए ने तालकटोरा व सआदतगंज क्षेत्र में 02 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये। प्रवर्तन जोन.7 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि फैजए शब्बू व अन्य द्वारा तालकटोरा में पत्थर कटा चौराहे के पास लगभग 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से दो मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया

जा रहा था। इसके अलावा यासीन व अन्य द्वारा सआदतगंज में नजमा प्लाजा के सामने लगभग 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो मंजिला व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त दोनों निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता रवि प्रकाश द्वारा दोनों भवनों को सील कर दिया गया।

राजभवन कार्मिकों को बैंकिंग सेवाओं व उत्पादों के बारे में दी गयी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से मंगलवार को राजभवन में भारतीय स्टेट बैंक सिविल सेक्रेटेरिएट शाखा, लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राजभवन कार्मिकों हेतु विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बैंक के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों ने राजभवन कार्मिकों को सैलेरी पैकेज एकाउंट, फैमेली सेविंग एकाउंट, नेट बैंकिंग, पर्सनल लोन, एसबीआई वेल्थ, नामनीज डीटेल, साइबर फ्राड, टर्म लोन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लांट, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की। उनके द्वारा बैंकिंग सेवाओं के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और वित्तीय योजना के बारे में भी बताया गया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, डॉ सुधीर महादेव बोबडे ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजभवन में विशेष शिविर आयोजित किये जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारी होना आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान की गई ये जानकारियाँ निश्चय ही राजभवन कार्मिकों के लिए लाभप्रद होंगी तथा आने वाले पीढ़ी को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को बैंकिंग सम्बन्धी जानकारियों हेतु उन्हें बैंक विजिट की सलाह दी तथा बैंक जाकर उन्हें वित्तीय ट्रान्जेक्शन के बारे में जानकारियाँ लेने हेतु कहा। उन्होंने बैंक के प्रतिनिधियों को राजभवन में भी एक एटीएम की स्थापना हेतु कहा, जिससे राजभवन कार्मिक एटीएम सुविधा का लाभ उठा सकें। विशेष शिविर के माध्यम से राजभवन कार्मिकों ने अपने बैंकिंग सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान बैंकिंग विशेषज्ञों से प्राप्त किया और उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

शगुन के नाम पर गांव-घर में जुएं ने दी दस्तक, लाखों के हो रहे वारे-न्यारे

मोहनलालगंज के गदियाना में जुए को लेकर हुए विवाद का दर्ज हुआ केस

संवाददाता। मोहनलालगंज

दीपावली नजदीक आते ही शगुन के नाम पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में साउथ जोन के कुछ गांव में जुएं का गैरकानूनी खेल तेजी से पांव पसारने लगा है। मोहनलालगंज के गदियाना गांव में इसे लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने मां बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पिछले दो दशक में यह गैरकानूनी खेल आधा दर्जन लोगों की जिन्दगी छीन चुका है। इस खेल के चस्के में दर्जनों परिवारों की खुशहाल गृहस्थियां तबाह हो चुकी हैं। फिर भी लोग जुएं के खेल से तौबा करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि पुलिस टीमों को जुंआरी तलाशे नहीं मिल रहे हैं।

राजधानी से सटे इलाकों में जुएं का गैरकानूनी खेल तेजी से अपनी जड़ें फैलाने लगा है। हजारों और लाखों का वारा न्यारा करने की चाहत में लोगों की सीमित आमदनी भी आड़े नहीं आ रही है। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के गदियाना कुढ़ा गौरा सिसेण्डी अतरौली खुझौली दहियर मऊ देवती निगोहां परेहटा मोहिद्दीनपुर कनकहा मोहनलालगंज कस्बा पुरसेनी मस्तीपुर भीलमपुर रायभानखेड़ा हुलासखेड़ा नगराम गोशाईगंज शिवढ़रा मोहारीखुर्द करोरा समेसी जैतीखेड़ा बिन्दौवा दीवानगंज धरमावत खेड़ा उदवतखेड़ा दाउदनगर गढ़ी मेंहदौली समेत कई गांव में जुएं का गैरकानूनी खेल धड़ल्ले से बेरोंकटोंक शुरू हो गया है। भाग्य आजमाने के बहाने इस गैरकानूनी कारोबार के दीवाने पूरे साल जुएं की फड़ पर अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। पेशेवर खिलाड़ियों के साथ ही नौसिखिए भी जुएं की फड़ पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने में पीछे नहीं रहते हैं। जुआरियों में इस गैरकानूनी खेल को लेकर इस कदर नशा रहता है कि घर-गृहस्थी के सामान और जेवर तक गिरवी रखकर अपना शौक पूरा करते हैं। यहां तक कि कई बार जुएं की फड़ पर हुए विवाद कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन पुलिस इस पर सख्ती से रोंक लगाने में नाकाम है। जुएं के गैरकानूनी खेल के जरिए जुआरियों को रुपये देकर हजारों और लाखों कमाने वालों की भी गांवों में फौज तैयार है। यह लोग सीधे तौर पर जुएं की फड़ पर तो नहीं शामिल होते लेकिन जुआरियों को रुपये देकर मुनाफा कमाने के लिए दिन-रात जुटे रहते हैं।

जुआरियों को लग जाती है पुलिस के मूवमेण्ट की सूचना

जुआरियों और उन्हें रुपये देने वाले लोगों का नेटवर्क पुलिस से भी ज्यादा मजबूत बताया जाता है। सूत्रों की मानें तो पुलिस के मूवमेण्ट से पहले ही उन्हें इसकी भनक लग जाती है। लिहाजा गांवों में पुलिस के पहुंचने से पहले ही जुआरी फड़ खाली करके नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश छापेमारी में पुलिस की कार्रवाई कुछ छुटभैया जुआरियों को पकड़ने तक ही सीमित रह जाती है। एडीसीपी साउथ राजेश यादव ने बताया जुएं के गैरकानूनी खेल की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कहीं से भी इस तरह की शिकायत मिलेगी तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस टीम गोपनीय रूप से गांवों में छापेमारी भी करेगी।

एकेटीयू में रिक्त सीटों पर हुई स्पेशल राउंड की काउंसलिंग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी एवं सरकारी स्ववित्त पोषित संस्थानों में खाली सीटों पर स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में सीयूईटी पीजी के तहत के एमबीए, एमसीए और एमसीए लेटरल एंट्री और सीयूईटी यूजी के तहत बीटेक लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग एवं सीट आवंटन मंगलवार को हुआ। विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य भवन के चौथे तल पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गयी थी। अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए अलग अलग काउंटर बनाये गये थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों ने सबसे पहले ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करायी। इसके बाद उनके प्रमाणपत्रों की जांच की गयी। इसके बाद सीट आवंटन किया गया। अभ्यर्थियों की च्वॉइस और उपलब्ध सीटों के अनुसार आवंटन किया गया। सीट आवंटन के बाद विभिन्न कॉलेजों के बनाये गये 22 काउंटर पर अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट किया। यहां भी उनके प्रमाणपत्रों की जांच की गयी। अभ्यर्थियों से 70 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराया गया। माननीय कुलपति प्रो जेपी पांडेय के निर्देशन में समन्वयक प्रो ओपी सिंह के नेतृत्व में काउंसलिंग हुई। जबकि उप समन्वयक अभिषेक नागर, डॉ पुष्कर त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने सहयोग प्रदान किया।

सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन करें: नरेन्द्र कश्यप

● शादी अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा और भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं के

कार्यान्वयन में तेजी लाने, लंबित मामलों के निस्तारण और योजनाओं के प्रचार-प्रसार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर देरी अस्वीकार्य होगी और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर योजना का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने योजनाओं की धनराशि खर्च न करने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी और निर्देश दिया कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि समय से सदुपयोग करते हुए लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाये।

मंत्री कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी/ओ लेवल) के प्रशिक्षार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी लाभार्थियों को उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि शीघ्र हस्तांतरित की जाए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने समयबद्ध तरीके से सभी आवेदकों को भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

मंत्री ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की जनपदवार स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रेषित धनराशि की जानकारी जनपद और मण्डलीय अधिकारियों को भी समय पर दी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। वेबसाइट की धीमी गति से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने अधिकारियों को इसका तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में, मंत्री कश्यप ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और उनके लिए अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2024-25 के बजट के उपयोग की समीक्षा करते हुए विभागीय निर्माण कार्यों और संचालित विद्यालयों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए।

मंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का किया निरीक्षण

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का संयुक्त निरीक्षण किया। इस अवसर पर दोनों ने आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोग के कार्यों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। मंत्री कश्यप और अध्यक्ष वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त और सुगम मंच उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोग से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो और पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक तेजी से पहुंचाया जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री और अध्यक्ष ने आयोग की कार्यक्षमता का आकलन किया और कहा कि आयोग को और अधिक सक्रिय कर उसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक विस्तारित किया जाए, जिससे पिछड़ा वर्ग के लोगों को समय पर न्याय और लाभ मिल सके। आयोग के कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

गो आश्रय स्थलों में खरीदे जा रहे चारे की गुणवत्ता का सत्यापन अनिवार्य रूप से हो: धर्मपाल

● मोबाइल वेटरनरी यूनिट के इमरजेंसी चिकित्सा का सत्यापन डैशबोर्ड पर प्रतिदिन किया जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गोआश्रय स्थलों को आवंटित धनराशि, खरीदे जा रहे भूसा एवं अन्य चारा की मात्रा तथा गुणवत्ता का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि गोआश्रय स्थलों में एकत्रित गोबर की खाद किसानों को देकर उसके बदले पराली या अन्य अवशेष प्राप्त कर लिया जाए, जिससे गोबर के निस्तारण तथा फसल अवशेष के जलाये जाने की समस्या का निदान आसानी से हो सके। अधिकारियों द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय से लाभार्थियों को दिया जाए और योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दुग्ध विकास एवं पशुधन विकास विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कार्य में और तेजी लायी जाए और निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा कियाजाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए। श्री सिंह ने डेयरी प्लांट की उपयोगिता क्षमता, दुग्ध उपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री, बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति, निराश्रित गोवंश संरक्षण तथा गोशालाओं के निर्माण की प्रगति, वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण की अद्तन स्थिति तथा कब्जामुक्त गोचर भूमि पर हरा चारा उत्पादन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। सिंह ने कहा कि वन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर हरा चारा उत्पादन किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के गांवों का हो रहा चहुंमुखी विकास: केशव मौर्य

● समूहों की दीदियों की समृद्धि के लिए 747 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति की प्रदान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के जिलों में गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के उद्देश्य से रू 747 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की प्रदान की है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह धनराशि शीघ्रातिशीघ्र जिलों को भेजना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाय। एस आर एल एम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाय। निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को परखा जाय और जहां सुधार की आवश्यकता हो ,सुधार किया जाय। केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अपने कैम्प कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को सतत् आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। गरीबों को स्थायी रूप से आजीविका उपलब्ध कराने के एन आर एल एम में उनके क्षमता के संवर्धन (जानकारी, कौशल विकास, वित्त पोषण एवं एकजुटता के माध्यम से) की व्यवस्था की गयी है।

दीपोत्सव को अलौकिक एवं अभूतपूर्व बनाने की तैयारियां जोरों पर: जयवीर

● 25 लाख दीप प्रज्वलित करने के अलावा 10 लाख अतिरिक्त दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया जायेगा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के 8वें चरण के अंतर्गत लगभग 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर राम नगरी में त्रेतायुग के दृश्य को जीवंत करने का प्रयास किया जाए। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने दीपोत्सव-2024 को ऐतिहासिक एवं अलौकिक बनाने के लिए पूरी अयोध्या को सजाया और संवारे जाने के निर्देश दिये है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके 28 से 30 अक्टूबर तक अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस अवसर पर विदेशी तथा प्रदेश एवं देश के मशहूर कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जायेंगे। इस आयोजन में कोई कमी न रहे, इसके लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गयी है।

पर्यटन मंत्री सोमवार देर शाम अपने सरकारी आवास पर दीपोत्सव-2024 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मंच एवं प्रदर्शनी संस्कृति विभाग द्वारा लगाई जायेगी। दीपोत्सव के लिए 10 बड़े सांस्कृतिक मंचों का निर्माण किया जा रहा है। इन मंचों पर अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से त्रेतायुग की झलकियां प्रदर्शित की जायेगी। इस प्रदर्शनी से श्रद्धालु त्रेतायुग का अनुभव कर सकेंगे तथा रामायण के महत्वपूर्ण पलों को अपनी आंखों में कैद कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के प्रतीक दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस वर्ष भी होने जा रहा है। देश दुनिया के कोने-कोने में बैठे श्रद्धालु अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़कर भगवान श्रीराम के विभिन्न प्रसंगों का साक्षी बनेगे। जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या की पवित्र नदी सरयू भगवान श्रीराम की मर्यादा, रामराज्य की परिकल्पना, लोक जीवन के आदर्शों तथा गौरवशाली संस्कृति को समेटे हुए है। इस वर्ष भी अयोध्या के घाटों और प्रमुख स्थलों पर दीप जलाये जायेंगे जो पूरी रात अलौकिक दृश्य उत्पन्न करेंगे। मुख्य आयोजन 30 अक्टूबर को रामपथ, रामकथा पार्क, राम की पैड़ी तथा सरयू तट आदि पर आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित झांकियां एवं 30 कलाकारों के साथ दलों द्वारा रामपथ सचल प्रदर्शन का वह स्वयं शुभारम्भ करेगे। अपराह्न 03 बजे मा0 राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी तथा दोनों उपमुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डल के सदस्यगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि रामकथा पार्क अयोध्या में पहुंचकर शोभायात्रा की झाकियों का अवलोकन करेंगे। जयवीर सिंह ने कहा कि श्रीराम-सीता एवं लक्ष्मण जी के स्वरूपों का हेलीकाप्टर से रामकथा पार्क के हेलीपैड पर प्रतीकात्मक पुष्प विमान द्वारा अवतरण होगा एवं भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा श्रीराम जानकी का पूजन, आरती एवं श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जायेगा। इस मौके पर पर्यटन ऐप एवं काफी टेबल बुक का विमोचन होगा तथा गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया जायेगा। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री , राज्यपाल महोदया एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों द्वारा सम्बोधित किया जायेगा।

वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

लखनऊ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग सात लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव यूपीनेडा को प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 57 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत बायो ऊर्जा क्षेत्र के हैं। इस क्रम में कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो डीजल तथा बायोकोल के प्लांटों की स्थापना हेतु 198 प्रस्तावों को यूपीनेडा द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें से 32 प्रस्तावों को पूर्व में राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में 21 परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन मंगलवार को प्रमुख सचिव, ऊर्जा व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल 53 जैव ऊर्जा परियोजनाओं के सापेक्ष 2,525 करोड़ रू0 के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 210 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ सीबीजी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित है।

पलक यादव मिस फ्रेशर एवं रजत कुमार बने मिस्टर फ्रेशर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में मंगलवार को एमए सेमेस्टर प्रथम के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एम ए सेमेस्टर तृतीय के विद्यार्थियों द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। जिसमें पलक यादव को मिस फ्रेशर तथा रजत कुमार को मिस्टर फ्रेशर चुना गया । कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर विभाग अध्यक्ष प्रो. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा विद्यार्थियों को जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए एकेडमिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत एवं अकादमिक जीवन में अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभागीय शिक्षकों के साथ-साथ भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पीडीए परिवार को समाजवादी पार्टी में ही सम्मान मिलता है: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए परिवार को समाजवादी पार्टी में ही सम्मान मिलता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पीडीए को न्याय, हक और सम्मान मिलेगा। भाजपा सरकार पीडीए के साथ अन्याय, अत्याचार कर रही है। हक छीन रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी रणनीति बना ले, साजिश और षडयंत्र कर ले, इस बार पीडीए परिवार एकजुट होकर भाजपा को हराएगा।

अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं, नेताओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि कुशवाहा, सैनी, समाज का लम्बा इतिहास रहा है। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। समाजवादी पार्टी पर आपके भरोसे का सम्मान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी भी आप पर भरोसा करती है। उन्होंने समाज के समर्थन और स्वागत के लिए आभार जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ ही पीडीए है। भाजपा से मुक्ति समाज के हित में है। भाजपा पीडीए परिवार की दुश्मन है। यह उपचुनाव में भी देखने को मिल गया। भाजपा पीडीए से जुड़े बीएलओ, अधिकारियों, पुलिस के लोगों का नाम देखकर, जाति के आधार पर हटा रही है। जाति के आधार पर निर्देश दे रही है। लखनऊ में बैठे बड़े-बड़े अधिकारी भाजपा को जिताने और समाजवादी पार्टी को हराने की रणनीति बना रहे है और अपने जाति के अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं।

सरसों के बीज की मुफ्त मिनी किट पाकर किसानों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान

मोहनलालगंज। तिलहनी फसल की बुवाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को मोहनलालगंज के राजकीय कृषि बीज भण्डार पर एक सौ से अधिक किसानों को ब्लॉक प्रमुख ओमप्रकाश शुक्ल और जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरसों के बीज की निशुल्क मिनी किट वितरित की। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने इस मौके पर किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए फसल चक्र का पालन करने और मिट्टी के सेहत की नियमित जांच कराकर कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों की सलाह लेकर पोषक तत्वों की कमी पूरी करते रहने की अपील की। उन्होंने किसानों को हर फसल की सही नमी और समय पर बुवाई करने का महत्व भी बताया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी कृषि शोभनाथ यादव सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा उपेन्द्र नाथ सिंह राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी परमजीत और राजकीय कृषि रक्षा ईकाई प्रभारी महर्षि प्रताप सिंह समेत अन्य टीएसी मौजूद रहे।

जनता सपा मुखिया के जाति-धर्म आधारित प्रलोभन में कभी नहीं आएगी: डॉ. राजेश्वर सिंह

● सपा सरकार में पुलिस अधिकारियों के मान-सम्मान से लेकर उनका जीवन तक सुरक्षित नहीं था: विधायक सरोजनीनगर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में विधानसभा उप चुनावों की बढ़ती सरगर्मी के बीच मंगलवार को सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। डॉ. सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जबाव देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर उंगली उठाकर और पुलिस पर 'हथकड़ी' जैसे शब्दों का प्रयोग कर प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाले अपना 'जंगलराज' भूल गए लेकिन जनता नहीं भूली है! डॉ. सिंह ने सपा सरकार को घेरते हुए आगे लिखा, सपा सरकार में पुलिस अधिकारियों का मान-सम्मान, जीवन तक सुरक्षित नहीं था, ईमानदार आईएएस अधिकारियों का काम करना भी मुश्किल था, वर्ष 2005 में सपा संरक्षित गुंडों ने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश साहनी को जीप की बोनट पर लटकाकर कैसरबाग से हजरतगंज तक खींचा था, वर्ष 2013 में सपा संरक्षण में कुंडा सीओ जिया उल हक की नृशंस हत्या की गई, सपा संरक्षण में ही मथुरा एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई थी। समाजवादी सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों पर की गयी कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने आगे लिखा वर्ष 2013 में ही सपा सरकार ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर मस्जिद की अवैध दीवार गिरवाने पर कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित किया, यही नहीं निलंबन को सही ठहराते हुए केंद्र से सभी ड्ढ्ढस अधिकारियों को वापस बुला लेने की असंवैधानिक मांग तक की। सपा सरकार ने काले धन के विरुद्ध आवाज उठाने पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय शंकर पाण्डेय जी पर विभागीय जांच करवाकर परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन विभागीय जांच को निरस्त करने का आदेश देना पड़ा और यूपी सरकार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। विधायक डॉ. सिंह ने सीएम योगी योगी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए आगे लिखा, जनता सपा सरकार का कुशासन न भूली है, न भूलेगी, न ही उनके जाति - धर्म आधारित किसी भी प्रलोभन में आएगी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी देश का ग्रोथ इंजन है, यहां अपराधियों-माफियाओं को सही जगह दिखाई जाती है।

संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को दिया जा रहा है पांच दिवसीय प्रशिक्षण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ द्वारा 12 जनपदों के 27 विकास खण्डों से, सहायक विकास अधिकारी के पद से प्रोन्नति प्राप्त संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों हेतु, पांच दिवसीय आवासीय 'पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन संस्थान पर किया जा रहा है। 21 से 25 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रशिक्षण अवधि में सभी संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विषयों यथा-सामुदायिक विकास की अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभागीय संगठनात्मक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 , विभिन्न स्तर के शिकायत निवारण प्लेटफार्म, टी ए नियम एवं एल टी सी, लघु दण्ड, वृहद दण्ड व निलम्बन की अवधारणा, यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली, यूपी सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तित्व का विकास एवं अभिप्रेरणा इत्यादि विषयों पर राज्य/राष्ट्रीय स्तर के प्रबुद्ध विषय-विशेषज्ञो द्वारा प्रासंगिक एवं यथोचित वार्ताएं प्रदान की जा रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिवस दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को ग्राम पंचायत जुग्गौर, विकास खण्ड चिनहट, लखनऊ में, ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जा रही योजनाओं के पर्यवेक्षण, आकलन व अध्ययन के सन्दर्भ में, क्षेत्र भ्रमण भी कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू ने प्रतिभागी प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि शासकीय सेवाओं को कर्मठता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ निष्पादित किया जाना, प्राथमिकता में होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, जनहित के होते हैं।

अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम को बनाने के लिये पैरामेडिकल प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पैरामेडिकल विज्ञान संकाय मे मंगलवार को नव प्रवेशित वैच 2024 के लगभग 570 छात्र/छात्राओं के आगमन समारोह का आयोजन कलाम सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रो सोनिया नित्यानन्द एवं सम्माननीय अतिथि के रूप में प्रति कुलपति प्रो अपजीत कौर एवं प्रोफेसर अमिता जैन डीन एकेडेमिक उपस्थित रहीं।

अपने संबोधन में कुलपति ने छात्र/छात्राओं को इस संस्थान में प्रवेशित होने की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं छात्र/छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम को बनाने के लिये पैरामेडिकल प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके लिए केजीएमयू एवं अधिष्ठाता पैरामेडिकल विज्ञान संकाय निरंतर प्रयासरत है। उन्होने पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विकास एवं नये बैचलर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु पूर्ण आश्वासन दिया जिससे पैरामेडिकल विज्ञान संकाय नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। प्रति कुलपति ने छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखने तथा अनुशासन का वातावरण बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होने तीमारदारों तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ उचित व्यवहार रखने की भी नसीहत दी, जिससे कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। सभा में उपस्थित प्रोफेसर अमिता जैन डीन एकैडेमिक ने संबोधित करते हुए पैरामेडिकल छात्र/छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा के महत्व के बारे मे बताया तथा डॉक्टर व स्टॉफ के साथ सहभागिता कर कार्य सीखने एवं रोगी उपचार प्रदान करने हेतु प्रेरणा दी। अधिष्ठाता पैरामेडिकल विज्ञान संकाय प्रोफेसर अनिल निश्चल द्वारा स्वागत सम्बोधन में पैरामेडिकल संस्थान की कार्यप्रणाली एवं छात्र/छात्राओं के शिक्षण-प्रशिक्षण की जानकारी दी गयी उन्होने संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाले के बारे में बताया एवं छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता को प्रेरित किया जिससे उनका सम्पूर्ण विकास हो सके।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत बलिया हेतु 88.78 लाख रुपये मंजूर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद बलिया में सड़क निर्माण से संबंधित तीन कार्यो हेतु कुल 88.78 लाख रूपये मंजूर किये हैं। मंजूर की गई धनराशि जिलाधिकारी, बलिया के निवर्तन पर रखी गई है। जारी शासनादेश की प्रति जिलाधिकारी, बलिया को प्रेषित कर दी गई है। जारी शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा मुंडेरा में सीसीसड़क, नाली निर्माण एवं लेपन कार्य हेतु 37.02 लाख रूपये, ग्राम सिंगही सुल्तानपुर (रसड़ा) में सीसी सड़क, नाली निर्माण एवं लेपन कार्य हेतु 31.10 लाख रूपये तथा ग्राम सभा अमहर में सीसीसड़क, नाली निर्माण एवं लेपन कार्य हेतु 20.66 लाख रूपये मंजूर किये गये हैं।

धर्म के आधार पर किसी भी देश का विभाजन नहीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में मंगलवार को समकालिक वैश्विक चुनौतियों एवं समस्याएं विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी धर्मबन्धु, संस्थापक, श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट, गुजरात उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुरूआत में विभाग प्रमुख व संकायाध्यक्ष प्रो. दिनेश कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर तथा प्रो. यूसी वशिष्ठ ने अंगवस्त्र देकर स्वामी को सम्मानित किया। अपने संबोधन में स्वामी धर्मबन्धु ने वैश्विक चुनौतियों में मुख्य रूप से वैश्विक जल संकट, राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा, प्रोद्योगिकी असमानता, विकसित और विकासशील देशो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरूपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी छात्रों को दी। प्रौद्योगिकी असमानता के अर्न्तगत उन्होंने बताया कि हमारा भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केवल 0.72 प्रतिशत निवेश कर रहा है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। तत्पश्चात उन्होंने वर्तमान वैश्विक संकट की उत्पत्ति के बारे में बताया। जिसमें उन्होंने समझाया कि मुख्य कारण अध्यात्मिकता की कमी है। उनका मानना था कि अत्यात्मिक मूल्यों का अभाव ही समस्याओं और नैतिक पतन का मुख्य कारण है। स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिसके लिए हमे अपने आहार पर ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना, गहरी नींद लेना, अनैतिक आचरण और तनाव से बचने चाहिए।

समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता: सांसद प्रवीण पटेल

संवाददाता। प्रयागराज

ब्वायज हाईस्कूल एंड कॉलेज की ओर से आयोजित तीन दिवसीय अंतर संस्थागत सांस्कृतिक और खेल उत्सव एल्फ्रेस्को मंगलवार को सेंट पैट्रिक ऑडिटोरियम में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर फूलपुर से भाजपा सांसद प्रवीण पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो योगेश्वर तिवारी और शुआट्स के प्रो डॉ आरिफ ए ब्रॉडवे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत प्रिंसिपल डी ए ल्यूक ने किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत भाग लेने वाले स्कूलों द्वारा शानदार मार्च पास्ट के साथ हुआ। जिसके बाद स्कूल कैप्टन समर्थ खरे ने स्कूल गीत गाया और शपथ ली। उद्घाटन भाषण में सांसद प्रवीण पटेल ने समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए, ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश पाना अभी भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने नई पीढ़ी को सोशल मीडिया की लत से दूर करने और उन्हें नेतृत्व और खेल कौशल सीखने के लिए खुले मंच पर लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के एक लोक सेवक के रूप में उनके लिए यह बहुत गर्व की बात है कि बीएचएस जैसी संस्था और कॉलेज के पूर्व छात्र राष्ट्रीय मंच पर सबसे प्रतिष्ठित स्थान पर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों में द बिशप को एड स्कूल पुणे सेंट जॉन्स को एड स्कूल डी पी पब्लिक स्कूल खेलगांव पब्लिक स्कूल टैगोर पब्लिक स्कूल श्रीनिवास रामानुजन पब्लिक स्कूल बाल भारती स्कूल एनी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज और मेजबान बॉयज हाईस्कूल एंड कॉलेज शामिल थे। मेगा फेस्ट में शैक्षणिक संस्थानों के कुल पांच सौ से अधिक लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। पहला कार्यक्रम वाद विवाद था। जिसका संचालन रोवन ल्यूक ने किया। टीमों ने भारतीय शादी में बेशुमार धन प्रदर्शन प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए। इसके बाद क्विजिंग का शानदार दौर था। जिसमें बीएचएस ने पहला स्थान हासिल किया। दर्शक बुद्धि हास्य और सहजता से मंत्रमुग्ध हो गए।

मंच पर अंतिम कार्यक्रम रॉक ऑन रहा और प्रस्तुति इतनी शानदार रही कि जज निर्णय लेने में असमंजस में पड़ गए। प्रिंसिपल डी ए ल्यूक ने भाग लेने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों और छात्रों का स्वागत किया एवं उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जागरूकता के लिए हों समर्पित

प्रयागराज। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आयोडीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर टाटा सॉल्ट ने जोर दिया है। देश में आयोडीन युक्त नमक के अग्रणी निर्माता टाटा सॉल्ट ने विश्व आयोडीन अल्पता दिवस डब्ल्यू आईडीडी के अवसर पर देश भर के बच्चों में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों आईडीडी से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दीपिका भान प्रेसीडेंट पैकेज्ड फूड्स ने कहा कि आयोडीन की कमी से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। नेशनल ब्रांडेड आयोडाइज्ड सॉल्ट के रूप में टाटा सॉल्ट आम जन को आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयोडीन खासतौर से आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान मानसिक विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है।

पूर्व ग्राम प्रधान की जाति पर राज्य स्तरीय कमेटी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक

- राज्य सरकार से हाईकोर्ट नेतीन हफ्ते में मांगा जवाब
- शिकायतकर्ता को नोटिस

संवाददाता। प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर की ग्राम पंचायत अंध्या टप्पा के पूर्व प्रधान अमरनाथ खरवार को जारी अनुसूचित जाति का मानने से इंकार करने के राज्य स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी के 25 सितंबर 2024 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता पूनम देवी को नोटिस जारी की है तथा राज्य सरकार सहित विपक्षी से तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अमरनाथ खरवार की याचिका पर अधिवक्ता के आर सिंह को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची को वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी किया गया। जिसका परीक्षण जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी ने किया विपक्षी ने याची की जाति को लेकर शिकायत की थी। जिला स्तरीय कमेटी के याची के पक्ष में फैसले के खिलाफ विपक्षी पूनम देवी ने राज्य स्तरीय कमेटी को अपील की। जिस पर विजिलेंस सेल को जांच सौंपी गई। अपनी 22 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट में विजिलेंस सेल ने याची का पक्ष सही माना।

इसके बावजूद राज्य स्तरीय कमेटी ने याची को अनुसूचित जाति का नहीं माना। जिसे चुनौती दी गई है। याची अधिवक्ता का कहना है कि कमेटी ने कुमारी माधुरी पाटिल केस के फैसले और शासनादेश की अनदेखी की है।

कमेटी को आदेश देने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। क्योंकि नियमानुसार राज्य स्तरीय कमेटी में डायरेक्टर सोसल वेलफेयर कमेटी के सदस्य होने चाहिए,जबकि सरकार ने डायरेक्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को सदस्य बनाया है। जो विधि विरूद्ध है। इसलिए कमेटी नियमानुसार गठित न होने के कारण उसे जाति पर फैसला लेने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। आदेश विधि सम्मत नहीं है।

28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अवकाश घोषित

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ सहित 28 अक्टूबर 24 को अवकाश घोषित किया गया है। इसके बदले में हाईकोर्ट 23 नवंबर शनिवार को खुलेगा। इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक राजीव भारती ने जारी की है।

महाकुंभ के लिए चार पाण्टून पुलों का निर्माण कार्य हुआ प्रारम्भ

प्रयागराज। महाकुंभ मेला 2025 के दृष्टिगत गंगा पर पाण्टून पुलों का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। कुंभ मेला सीडी फोर लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि सोमवार से अभी चार पाण्टून पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ओल्ड जीटी रोड पर दो पाण्टून पुल गंगोली शिवाला मार्ग पर एक पाण्टून पुल और हरिश्चंद्र मार्ग के घाट पर एक पाण्टून पुल का निर्माण हो रहा है और सभी 30 पाण्टून पुलों का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा हो जाएगा। महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि महाकुंभ 2025 का प्रचार प्रसार देश और विश्व स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में संत महात्मा स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पाण्टून पुल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महाकुंभ में 22 पाण्टून पुल बनाये गये थे लेकिन इस बार 30 पाण्टून पुल बनाये जा रहे हैं। जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि तीन पाण्टून पुल नैनी से मेला क्षेत्र के झूंसी की ओर बनाए जा रहे हैं।

मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि इस बार सभी पाण्टून पुल 30 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। जिससे संत महात्मा श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों को मेला क्षेत्र में आने जाने में कोई परेशानी न होने पाए।

कोयला मंत्रालय स्टार रेटिंग अवार्ड में एनसीएल ने लहराया परचम, 5 परियोजनाओं को स्टार रेटिंग

संवाददाता। सोनभद्र

सोमवार को भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार रेटिंग अवार्ड में परचम लहराया है। एनसीएल की 9 परियोजनाओं को 5 स्टार रेटिंग मिली है एवं उत्कृष्टता हेतु सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित अवार्ड कार्यक्रम में केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार जी. किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार सतीश चंद्र दुबे द्वारा एनसीएल को इस उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सचिव कोयला मंत्रालय भारत सरकार विक्रम देव दत्त, चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड पी. एम. प्रसाद, कोल इंडिया, अनुषंगी कंपनियों एवं अन्य कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य उपस्थित रहे। एनसीएल की ओर से ये पुरस्कार जितेंद्र मलिक सुनील प्रसाद सिंह, विभिन्न परियोजनाओं के महाप्रबंधकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रहण किए।

सोमवार को आयोजित स्टार रेटिंग अवार्ड कार्यक्रम में कोल इंडिया सहित देश भर की विभिन्न कंपनियों की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 5 स्टार प्राप्त खदानों को पुरस्कृत किया गया। ओपनकास्ट श्रेणी में 33 खदानों को पुरस्कार दिए गए जिसमें एनसीएल की 9 खदानें कृष्णशिला जयंत झिंगुरदा अमलोरी बीना ब्लॉक बी दूधीचुआ खड़िया निगाही परियोजनाएं सम्मानित हुईं हैं। इस दौरान 5 स्टार प्राप्त खदानों में से एनसीएल की कृष्णशिला परियोजना ने विभिन्न मानकों के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम तथा जयंत एवं झिंगुरदा परियोजना ने तृतीय स्थान हासिल किया है।

कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत खदानों का सात प्रमुख मानकों जैसे खनन कार्य संचालन पर्यावरण से जुड़े मानक प्रौद्योगिकियों को अपनाने, श्रेष्ठ खनन व्यवहार आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास और पुन:स्थापन व श्रमिक संबंधी अनुपालन तथा सुरक्षा व बचाव में विभिन्न कारकों के आधार पर अवलोकन कर अंक आवंटन किया जाता है। इस स्टार-रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य सतत एवं हरित खनन पद्धतियों को प्रोत्साहन देना प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा देश में कोयला खनन के समग्र निष्पादन और निरंतरता को बढ़ाना है।

स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के दौरान नवाचारी पहलों के लिए भी मिला विशिष्ट पुरस्कार इस अवसर पर एनसीएल को केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी एवं माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत आयोजित विभिन्न नवाचारी पहलों स्वच्छता हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित करने एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सम्मानित किया गया।

उपचुनाव के लिए ईवीएम, वीवी पैट का प्रथम रेंडमाइजेशन हुआ सम्पन्न

अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा 277-कटेहरी विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के मतदान संबंधी व्यवस्थाओं के प्रभावी अनुश्रवण, नियंत्रण एवं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने हेतु प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के उपस्थिति में एन आई सी कक्ष में ईवीएम, वीवी पैट का प्रथम रेंडमाइजेशन सम्पन्न हुआ इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे प्रथम रेंडमाइजेशन का जायजा लिया गया। ई वी एम की रेंडमाइजेशन के लिए 39 कंट्रोल यूनिट, 39 बैलेट यूनिट, 39 वी वी पैट मशीन प्रशिक्षण के उद्देश्य से निकाली गई। शेष का पहला रेंडमाइजेशन किया गया, जिसमें सी यू 140 प्रतिशत , वी यू 140 प्रतिशत तथा वी वी पैट 150 प्रतिशत है। रेंडमाइजेशन के द्वारा जो मशीन सिलेक्ट हुई है अब उन मशीनों को अंदर से निकाल करके उनका स्क्रेनिंग करके नंबर मिलान करके अब विधानसभा के अनुसार रखा जाएगा, जो रेंडमाइजेशन में नंबर आता है उन्हीं नंबर की मशीनों को निकाल कर स्कैनिंग की जाती है। इस दौरान मौके पर अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.महेश चंद द्विवेदी, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी,कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

संस्था की प्रगति में निवारण सतर्कता निवारक महत्वपूर्ण: डॉ जितेंद्र कुमार

संवाददाता। प्रयागराज

इफको फूलपुर इकाई में समाज जीवन और कार्यस्थल में सतर्कता के आयाम विषय पर सतर्कता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन प्रशासनिक भवन स्थित बोर्ड रूम में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ जितेन्द्र कुमार उप मुख्य सतर्कता अधिकारी आईआरटीएस उत्तर मध्य रेलवे ने दीप प्रज्जवलन कर किया। मुख्य अतिथि डॉ जितेन्द्र कुमार ने कहा कि सतर्कता हमें कार्यस्थल पर व्यवस्थित मानक नियमों व पारदर्शी तरीके से कार्य करने की दिशा देता है। सतर्कता की भूमिका किसी भी व्यवस्था की शुचिता को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

उन्होंने कहा कि सतर्कता का प्रभाव हमारे कार्यस्थल के साथ साथ समाज की व्यवस्था और जीवन शैली

पर भी पड़ता है। किसी भी संस्था की प्रगति और विकास में निवारण सतर्कता निवारक बहुत महत्वपूर्ण होती है। सतर्कता का यह आयाम हमें कार्य की लापरवाही के पूर्व सचेत करता है। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक ईकाई प्रमुख संजय कुदेशिया ने कहा कि इफको विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है तथा इफको ने स्वयं पारदर्शी प्रकिया अपनाई है। यहाँ पर भुगतान कैशलेश प्रक्रिया के तहत होता है तथा सभी श्रमिकों का पीएफ कर्मचारी राज्य बीमा विनियम ईएसआईसी का पंजीकरण हमारे यहां ही है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय कुमार मिश्र ने कहा कि सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य सत्यनिष्ठा ईमानदारी पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा अनैतिक भ्रष्टाचार के प्रति कर्मचारियों और बच्चों में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी के नेतृत्व में इफको लगातार तरक्की कर रहा है। इफको शीर्ष प्रबंधन ने एक पारदर्शी संस्कृति अपनाई है जो हमारी नीति रही है। कार्यक्रम का संचालन शरद अग्निहोत्री तथा धन्यवाद ज्ञापन पी के वर्मा ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ महाप्रबंधक संजय वैश्य महाप्रबंधक ए पी राजेन्द्रन संजय भंडारी पी के सिंह संयुक्त महाप्रबंधक पी के पटेल अनीता मिश्रा अरूण कुमार रत्नेश कुमार अरवेन्द्र कुमार एस के सिंह ए के गुप्ता विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर आदि मौजूद रहे।

सभी के सहयोग से ही मिलनी संभव होगी टीबी रोग से मुक्ति

संवाददाता। मीरज़ापुर

टीबी रोग कोई असाध्य बीमारी नहीं है। यह बीमारी नियमित दवा के सेवन से ठीक किया जा सकता है। यह कहना है जिला कार्यक्रम सन्ध्या गुप्ता का है जो मंगलवार को जिला क्षय रोग विभाग के सभागार में आशाओं के प्रशिक्षण के दौरान कहा। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ओझा ने प्रशिक्षण के दौरान आशाओ को बताया कि यह बीमारी अधिकतर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। प्रधानमंत्री ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया हुआ है। इसी के तहत अमृत महोत्सव आईकोनिक वीक ऑफ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के खांसने व छींकने से यह बीमारी फैलती है। छोटे बच्चे इस बीमारी के शिकार जल्दी होते है। अगर किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रही होए बुखार का आनाए खांसी के साथ खून आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी शरीर के अन्य अंगों में भी फैल जाती है। इसके अलावा ग्राम स्तर पर भी आशाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। टीबी के मरीजों को बेहतर आहार के लिए 500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान भी किया जा रहा है उसको अब विभाग के द्वारा 1000 रूपया कर दिया गया है जो विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल है।

जिला क्षय रोग विभाग की जिला कार्यक्रम समन्वयक संध्या गुप्ता ने बताया कि जिन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता कम है वह चपेट में आ रहे हैं। इसलिए टीबी मरीजों में संक्रमण का खतरा दूसरे मरीजों से कई गुना ज्यादा होता है। टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति के एक बार खांसने पर लगभग 25 से 30 हजार टीबी बैक्टीरिया को हवा में छोड़ने का काम करते हैं। जिले में इस समय विभाग के द्वारा 4903 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 5471 मरीजों को टीबी मुक्त भी कर दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान दुर्गेश रावत, अखिलेश पाण्डेय व पंकज सिंह के अलावा तमाम कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।

जलभराव की समस्या का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, किया निरीक्षण

अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तहसील अकबरपुर के विकासखंड कटेहरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत अटवाई में रेलवे विभाग द्वारा निर्मित कराए गए रेलवे अंडरपास में विगत कई महीने से जल भराव होने से आस-पास की ग्रामीणों को आवागमन में आ रही समस्याओं की प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिशासी अभियंता सिंचाई अयोध्या सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का भौतिक परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अंडरपास के निर्माण में बगल से गुजर रहे नहर के जल रिसाव से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य न करने के कारण अंडरपास में जल भराव की समस्या प्रकाश में आयी। जिसके शीघ्र अति शीघ्र समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई रजनीश गौतम को तत्काल नहर के लाइनिंग का स्टीमेट बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ उन्होंने खंड विकास अधिकारी,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह को डीआरएम रेलवे तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही रेलवे एवं सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने और समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीणों की आवागमन समस्या का स्थाई समाधान हो सके और नियमित सुचार आवागमन सुनिश्चित हो सके।

लैंगिक समानता की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर किया गया कार्यशाला का आयोजन

बीजपुर, सोनभद्र। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एनटीपीसी परिसर शक्तिनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मंगलवार को मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अन्तर्गत लैंगिक समानता की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गाँधी के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिसर प्रभारी डॉ प्रदीप कुमार यादव ने किया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जीआईसी शक्तिनगर की प्राचार्य शालिनी सिंह उपस्थित रहीं। मिशन शक्ति फेज 5 के कोर उद्येश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शालिनी सिंह को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में स्वयं को एनएसएस का पूर्व स्वयं सेविका बताया और कार्यक्रम में सहभाग करने पर प्रसन्नता व्यक्त किया। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत संचालित योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा स्थानीय छात्र छात्राओं से इसमें सशक्त सहभागिता का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित शालिनी श्रीवास्तव ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित कविता पाठ प्रस्तुत किया। कार्यशाला में की-नोट स्पीकर के तौर पर समाजकार्य विभाग के डॉ मनिंदर कुमार डिसूजा ने लैंगिक भेदभाव और सामाजिक व्यवस्था पर गहन विचार प्रस्तुत किया, तथा जेन्डर जनित व्यवहार को बदलने के अभियान में मिशन शक्ति और एनएसएस के योगदान की सराहना की। छात्रा ज्योति ने बेटी पूछती जीने का अर्थ का मार्मिक गायन प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

डीएम ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, सोनभद्र के वित्त पोषित कार्यो की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की समीक्षा बैठक की गयी, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सोनभद्र को अब तक स्वीकृत किये गये 75 कार्यों की समीक्षा की गयी, समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि अब तक 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 46 कार्य प्रगति पर है, 09 कार्य निविदा स्तर पर और 03 कार्य विवादित होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सके, समीक्षा के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि में 213 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में वर्ष 2019-20 के स्वीकृत हुए थे, जिसमें से मात्र 83 आंगनबाड़ी केन्द्र अब तक हैण्ड ओवर विभाग को हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किये कि आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर हैण्डओवर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन कार्यों के धनराशि की आवश्यकता हो कार्य के सत्यापन के उपरान्त धनराशि तत्काल अवमुक्त कर दी जाये, खनिज विभाग के प्रर्वतन कैम्प कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल सहित अन्य कार्य 06 माह में अवश्य पूर्ण कर लिये जाये, ताकि अवैध परिवहन के वाहनों को सही स्थल पर रखा जा सके। जिन कार्यो पर जाँच लम्बित है जाँच अधिकारियों से सम्पर्क कर जाँच आख्या तत्काल प्राप्त कर ली जाये

छह अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से किया जायेगा लाभान्वित

सोनभद्र। विण्ढमगंज सड़क हादसे मे अनाथ हुए छः नाबालिक बच्चों के सम्बन्ध मे तत्काल संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा मौके पर ग्राम महुली बच्चों के घर पहुंच कर वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए सभी बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मौके पर पर ही आवेदन पत्र तैयार कराये जाने के लिए ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय द्वारा बताया गया की इन सभी बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सतत् निगरानी रखी जायेगी।

महिलाएं निडर होकर मनाएं दीवाली और छठ का त्योहार

सकलडीहा, चन्दौली। आगामी दिनों दिवाली, धनतेरस,डाला छठ सहित विभिन्न पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चौकसी बरती जा रही है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आदित्य लाग्हें के निर्देश पर महिला दरोगा पुलिस टीम के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थान और गांवों में मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त बुके लेट भी वितरण किया गया। शासन की ओर से महिला उत्पीड़न और अपराध को रोकने के लिये लगातार कवायद किया जा रहा है। जिससे महिलायें आत्मनिर्भर के साथ निडर होकर अपने अधिकार के प्रति कही आ जा सके।। इसके लिये लगातार महिलाओं को जागरूक करने का कार्य जिला पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मंगलवार को सकलडीहा इंटर कॉलेज, सकलडीहा पीजी कॉलेज, कस्बा, नागेपुर, टिमिलपुर आदि प्रमुख बाजारों में महिला दरोगा गुड़िया यादव पुलिस टीम के साथ महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया। इस दौरान 112, 1090 सहित विभिन्न मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के प्रति जागरूक किया।

इस बाबत महिला दरोगा गुड़िया यादव ने बताया कि महिलाये निडर होकर त्योहार मनाये। किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल हेल्प लाइन नंबर पर फोन करे पुलिस हर पल महिलाओं की सहायता के लिये तैयार है। इस मौके पर महिला पुलिस सरोज देवी, नेहा सहित अन्य मौजूद रहीं।

बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध चलाया गया जागरूकता अभियान

गाजीपुर। मिशन शक्ति अभियान फेस 05 के अंतर्गत शासन के निर्देश व जिलाधिकारी के आदेशानुसार में बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध आपरेशन मुक्ति अभियान चलाकर जागरुकता कार्यक्रम चंदनी पब्लिक स्कूल मुहम्मदाबाद व प्राथमिक विद्यालय व कम्पोजिट विद्यालय मिर्जाबाद भांवरकोल गाजीपुर मे आयोजित किया गया। इस अवसर पर चंदनी पब्लिक स्कूल सुरतपुर मुहम्मदाबाद में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शेखर सेंगर जी द्वारा मिशन शक्ति के विषय में बताते हुए बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किये साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरो की जानकारी प्रदान की गई। बाल अपराध, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बाल श्रम को रोकने, महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण निषेध व रोकथाम) अधिनियम 2013 के विषय पर चर्चा करते हुए आंतरिक परिवाद समिति के गठन के लिए सभी को जागरूक किया गया।

समितियों पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है कम्प्यूटराइजेशन: डीएम

गाजीपुर। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति निगरानी समिति की बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्टेड सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें कमेटी के सदस्य सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0, जी0एम0/ टी0डी0एम0 बी0एस0एन0एल0 एवं बी-पैक्स की ओर से मनियां (गदौरा) एवं महेशपुर समिति सचिव द्वारा भाग लिया गया। कमेटी के सदस्य संयोजक सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि0, द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 182 समितियां है जिनमें से 16 समितियां परिसमापनाधीन है शेष 166 समितियों में प्रथम चरण में 16 समितियां, द्वितीय चरण में 14 समितियां एवं तृतीय चरण में 76 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति निगरानी समिति द्वारा चयन किया गया है।

जम्मू कश्मीर
आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सात लोगों की नृशंस हत्या कर दी है। सात लोगों की कायरतापूर्ण नृशंस हत्या से जम्मू कश्मीर में लक्षित हत्याओं का परेशान करने वाला 'पैटर्न' फिर उभरता लग रहा है। मारे गए लोग एक निर्माण टीम का हिस्सा थे जो मध्य कश्मीर के गगनगिर से सोनामर्ग को जोड़ने वाली 'जेड मोर्ह सुरंग' पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही राजधानी में एक और बम धमाका हुआ जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। इससे विभिन्न आतंकी समूहों के बीच संभावित समन्वय तथा घाटी और उसके बाहर हिंसा फैलाने की चिंताजनक रणनीति का संदेह होता है। हालांकि, इन घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, पर व्यापक सुरक्षा खतरे की आशंका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह नवीनतम हमला क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की परेशान करने वाली प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है क्योंकि यह ऐसी पांचवीं घटना है। हालिया हत्याओं से कश्मीर में लगातार जीवन पर खतरा रेखांकित होता है। आतंकी हमलों की हालिया लहर सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण कमी का भी संकेत करती है। हालांकि, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन आतंकी हमलों की निन्दा की है तथा दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है, लेकिन बार-बार होने वाले इन हमलों

की प्रकृति से आतंकवाद-विरोधी उपायों तथा सुरक्षा प्रोटोकालों में गंभीर चुनौतियों का पता चलता है। इन हत्याओं की लक्षित प्रकृति एक जानी समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों में भय पैदा कर वर्तमान समय में जारी विकास परियोजनाओं में बाधा डालना है।

ढांचागत निर्माण में लगे प्रवासी कामगारों पर निशाना लगा कर आतंकी वे आर्थिक गतिविधियां रोकना चाहते हैं जिनसे इस क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। ऐसी घटनाओं से न केवल विकास बाधित होता है, बल्कि कामगारों का विश्वास भी डगमगाता है जो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही हमले व्यापक रूप से उस तुलनात्मक शांति को नष्ट करना चाहते हैं जो हालिया वर्षों में बनी हुई है। सुरक्षा उपायों में वृद्धि तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सेना की उपस्थिति के बावजूद आतंकी सिविलियनों पर हमले करने में सफल हो रहे हैं। इससे खुफिया सूचनायें प्राप्त करने में भारी कमी तथा आतंकियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में कमियों का लाभ उठाने की क्षमता प्रकट होती है जिससे वे आसान शिकार समझे जाने वाले समूहों पर निशाना लगाते हैं। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा उपायों की समग्र समीक्षा तत्काल जरूरी हो गई है। हालांकि सैनिक कार्रवाई जरूरी बनी हुई है, पर खुफिया सूचनायें एकत्र करने की प्रभावी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा अतिवादी तत्वों का मुकाबला करने के लिए 'समुदाय-आधारित दृष्टिकोण' अपनाना भी जरूरी हो गया है। वर्तमान स्थिति उन शिविरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के उच्चीकरण की जरूरत बताती है जहां प्रवासी श्रमिक रहते हैं। अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिकों को काम देने वाली परियोजनाओं को उपयुक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी आतंकी घटनायें बढ़ने से सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का मुद्दा भी सामने आता है। ऐसे में एक एकीकृत राजनीतिक रणनीति की जरूरत है जो न केवल तात्कालिक सुरक्षा चुनौतियों, बल्कि अशांति का कारण बनने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को भी संबोधित करे। स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसर प्रदान करने, शैक्षणिक पहलों तथा खुफिया नेटवर्क मजबूत करने से सुरक्षा स्थितियों में सुधार होगा।

पीएम-गतिशक्ति : महत्वपूर्ण पहल

'पीएम-गतिशक्ति' पहल भारत की ढांचागत संरचना में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। डिजिटल नियोजन उपकरणों के प्रयोग से परियोजनायें जल्दी पूरी होती हैं तथा बहुआयामी कनेक्टिविटी में सुधार होता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग-डीपीआईआईटी विभाग के सचिव अमरदीप सिंह ने अब तक 'पीएम गतिशक्ति' पहल में 208 बड़ी परियोजनाओं की संस्तुति की है जिनमें सड़क, रेलवे, शहरी विकास तथा तेल व गैस क्षेत्र की 1539,000 करोड़ की परियोजनायें शामिल हैं। इन परियोजनाओं की संस्तुति अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा की गई है जिसे नेटवर्क प्लानिंग समूह-एनपीजी कहा गया है। इसका गठन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान-एनएमपी के अंतर्गत हुआ है। अक्टूबर, 2021 में शुरू पीएम गतिशक्ति एनएमपी 100 लाख करोड़ की परियोजनाओं का संचालन करता है जिसका उद्देश्य अगले पांच साल में भारत की ढांचागत संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। इसका उद्देश्य एक विश्वस्तरीय समन्वित ढांचा तैयार करना है जो जीवन स्थितियों में सुधार करे, आर्थिक वृद्धि को गति दे तथा भारतीय बिजनेसों को ज्यादा प्रतियोगी बनाए। इसके लिए परियोजनायें पूरी करने में तेजी लाना, समय सीमा घटाना, बहुआयामी कनेक्टिविटी में सुधार करना, विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाना, लाजिस्टिक्स में सुधार करना, रोजगार सृजन करना तथा खोजों को बढ़ावा देना प्रमुख कार्य हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी का विकास एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में किया गया है।

यह गतिशील भौगोलिक सूचना व्यवस्था-जीआईएस प्लेटफार्म पर काम करती है। यहां ढांचागत संरचनाओं से संबंधित सभी 16 मंत्रालयों व विभागों की विशिष्ट कार्ययोजनाओं तथा राज्यों का डेटा एक समग्र डेटाबेस में समाहित होता है। एनएमपी पोर्टल में जियोस्पेटियल डेटा के 1,600 से अधिक स्तर हैं जिनमें किसी क्षेत्र के सभी भौतिक व सामाजिक ढांचागत डेटा प्रदर्शित होते हैं। इनमें भूमि, बंदरगाह, जंगल व राजमार्ग आदि शामिल हैं। एनएमपी लगभग सात प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है जो आर्थिक वृद्धि तथा सहज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। इन क्षेत्रों में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाईअड्डे, व्यापक परिवहन, जलमार्ग तथा लाजिस्टिक ढांचा शामिल है। इनको विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन और सहयोग मिलता है जिनमें ऊर्जा, संचार, आईटी संचार, पानी व सीवेज की उपलब्धता तथा सामाजिक ढांचा शामिल हैं। ऊर्जा के अंतर्गत सभी ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस व बिजली आदि आते हैं। अंतर-मंत्रालयी एनपीजी में कनेक्टिविटी, ढांचागत मंत्रालय व विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो नेटवर्क नियोजन विभाग के साथ विचार-विमर्श कर एकीकृत नियोजन व प्रस्तावों का समेकन सुनिश्चित करते हैं।

एनपीजी हर पखवाड़े मिलती है तथा ढांचागत परियोजनाओं पर विचार कर इनकी मल्टी-मोडेलिटी सुनिश्चित करती है। इसका अर्थ है कि फैक्ट्री, बंदरगाह व गोदाम से उपयोगकर्ता के स्थान तक अनेक परिवहन माध्यमों में समन्वय बनाया जाता है। इसके साथ ही परियोजना स्थल और उसके आसपास समग्र विकास के लिए प्रयासों में समन्वय होता है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की सभी ढांचागत परियोजनायें एनपीजी के माध्यम से लागू होती हैं। नियोजन स्तर पर डीपीआर बनाने के पहले ही एनपीजी की संस्तुति जरूरी होती है। इसके बाद परियोजना को सार्वजनिक निवेश बोर्ड-पीआईबी या सार्वजनिक निवेश बोर्ड-पीआईबी या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत खर्च विभाग और कैबिनेट की संस्तुति की सामान्य प्रक्रिया की जरूरत होती है। सरल भाषा में कहें तो एनएमपी एक केन्द्रीकृत पोर्टल प्रदान करती है जिसमें सभी वर्तमान परियोजनाओं या पहलों, क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं तथा नियोजन के स्तर पर परियोजनाओं की पूरी तस्वीर सामने आती है। इससे सभी मंत्रालयों व विभागों संबंधी सभी महत्वपूर्ण डेटा सामने आते हैं जिनकी आवश्यकता नियोजन या क्रियान्वयन को सक्षम बनाने के लिए होती है। इससे ढांचागत संरचना में महत्वपूर्ण कमियों का पता चलता है तथा परिवहन के सर्वाधिक सक्षम तरीके तलाशने में सहायता मिलती है। इससे खर्च कम होता है तथा विलंब न्यूनतम हो जाता है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत बंदरगाहों की ढांचागत संरचना में 156 कमियों की पहचान की गई है जो कोयला, सीमेंट, उर्वरक तथा अनाज जैसी बड़ी मात्रा में चीजों के परिवहन में सामने आती थीं।

इस योजना से परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में भी सहायता मिलती है। इसमें सभी क्षेत्रों से समुचित संवाद शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि मंत्रालय परियोजनाओं को एकसाथ रखने तथा संसाधनों का उपयुक्त आबंटन करने में सामंजस्य से काम करते हैं। इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को महत्व मिलता है तथा चीजों का दुहराव नहीं होता है और कमियां दूर की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा डीपीआर बनने से पहले ही एनपीजी की स्वीकृति से सही पसंद करने में आसानी होती है, विलंब से बचा जा सकता है तथा संसाधनों की भारी बरबादी थमती है। यह पहले की व्यवस्थाओं में आम बात थी जब मंत्रालय और विभाग अलग-अलग काम करते थे, उनके बीच समन्वय का अभाव था तथा वे दूसरे विभागों में कार्य की प्रगति से अनजान रहते थे।

इसके साथ ही उनको प्रमुख पैरामीटरों पर उपलब्ध डेटा का लाभ नहीं मिलता था। पीएम गतिशक्ति एक जीवन्त व्यवस्था है जो परियोजनाओं के नियोजन व क्रियान्वयन के निर्देशन में उपयोगी गतिशील ढांचा पेश करती है। इसमें निगरानी के लिए उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का प्रयोग होता है जिससे मंत्रालय कार्य की प्रगति पर नजर रख सकते हैं तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की क्षमता में असाधारण सुधार हुआ है। इनमें बंदरगाह, हवाईअड्डे, रेलवे, राजमार्ग, सड़कें, आदि शामिल हैं। यह पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने पहले बजट में अगले पांच साल में ढांचागत संरचना में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही थी। इसमें से 39 प्रतिशत या 3900,000 करोड़ केन्द्र तथा समान राशि राज्यों की ओर से आनी थी, जबकि बाकी 2200,000 करोड़ निजी क्षेत्र से आना था। इसके विपरीत पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत निवेश केवल 1539,000 करोड़ आया है जो केवल 15 प्रतिशत है। यदि हम इसे केन्द्र द्वारा निवेश प्रतिबद्धता का केवल एक हिस्सा मान लें तो भी यह लगभग 40 प्रतिशत होता है।

जहां तक राज्यों का सवाल है, वे 3900,000 करोड़ निवेश के अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ कर अनेक अन्य राज्यों ने अभी पीएम गतिशक्ति प्लेटफार्म पर स्वयं को जोड़ा भी नहीं है। यह प्लेटफार्म पारदर्शिता सुनिश्चित कर कमियों की पहचान करता है तथा संस्तुतियों की तेजी से सहमति में बेहतर समन्वय का काम कर सकता है, लेकिन यह विकल्प नहीं बन सकता है। केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर संस्तुतियां संबंधित अधिकारियों से ही मिलनी होती हैं। इसलिए परियोजनाओं में खासकर उन स्थितियों में काफी विलंब होता है, जब उनको पर्यावरण अनुमतियों की आवश्यकता हो या भूमि अधिग्रहण की अनुमति लेनी हो।

स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन परियोजनाओं में और ज्यादा विलंब का कारण बनते हैं। अपने पुराने दृष्टिकोण पर कायम रहने के कारण अक्सर संसाधनों पर दावों के मामले में विवाद होता है। सड़कों और रेलवे के मामले में ऐसे टकराव परियोजना में विलंब का कारण बनते हैं। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के बीच भी समन्वय का अभाव हो सकता है, जैसा कि 'सागरमाला' व 'भारतमाला' परियोजनाओं में हो रहा है। इसे परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है। पुराना या अधूरा डेटा भी बड़ी समस्या का कारण बनता है। उदाहरण के लिए केवल 13 राज्यों में भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण हुआ है। इससे राज्यों में परियोजनाओं में विलंब होता है। अनेक जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की नियमित निगरानी के अभाव में इनको पूरा होने में विलंब होता है।

ये बाधायें भारतीय बिजनेसों को ज्यादा प्रतियोगी बनाने तथा आम आदमी की जीवन सुगमता के रास्ते में आड़े आती हैं। ऐसे में पीएम गतिशक्ति की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों, खासकर राज्यों को एकसाथ आकर बाधायें दूर करनी होंगी।

बढ़ती वैश्विक मांग और भारत का कार्यबल

"इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारतीय प्रतिभाओं को अंतराष्ट्रीय नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।"

अदिति बनर्जी
(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भारत की श्रम शक्ति इसकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न उद्योगों में लाखों कुशल श्रमिक फैले हुए हैं। हालांकि, प्रतिभा की इस प्रचुरता के बावजूद, इनमें से कई श्रमिक देश के भीतर उपयुक्त रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं।

दूसरी ओर, वैश्विक श्रम बाजार में इन क्षेत्रों में लगातार कमी आ रही है। इस अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। पिछले एक दशक में, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में कुशल श्रमिकों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी, बदलती कार्य प्राथमिकताएँ और विकसित होती तकनीकी ज़रूरतों जैसे कारकों ने इन क्षेत्रों को भारत जैसे देशों से प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आईटी और लॉजिस्टिक्स कुछ ऐसे उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा कमी का सामना कर रहे हैं। हमें इस मांग को जल्दी पहचानने और कुशल भारतीय पेशेवरों को वैश्विक नियोक्ताओं से जोड़कर जवाब देने की ज़रूरत है। इससे भारतीय श्रमिकों के कौशल सेट को अंतरराष्ट्रीय मानकों और नौकरी की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में मदद मिलेगी, जिससे हजारों लोगों को विदेशों में सुरक्षित रोज़गार मिलेगा। वैश्विक लामबंदी के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। कार्यबल लामबंदी मॉडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए सुचारू और पारदर्शी हो।

संगठन कई प्रमुख चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है: प्रतिभा और कौशल अंतराल। हमें उम्मीदवारों का गहन मूल्यांकन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अंतर्राष्ट्रीय नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करके, वे उन उम्मीदवारों को कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जर्मनी, कनाडा और यूएई जैसे देशों में नियोक्ताओं के साथ स्थापित संबंधों के साथ, संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं से मेल खाने वाली भूमिकाएं दी जाएं। विदेश में नौकरी मिलना विनियामक बाधाओं से भरा होता है, लेकिन वीज़ा, दस्तावेज़ीकरण और कानूनी अनुपालन के साथ पूर्ण सहायता प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवार प्रशासनिक देरी के बिना अपने करियर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

संगठन नियुक्ति के बाद सहायता प्रदान करता है, स्थानांतरण के साथ सहायता प्रदान करता है और उम्मीदवारों को नए सांस्कृतिक वातावरण में समायोजित करने में मदद करता है। यह विदेश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है। उद्योग के भविष्य को आकार देना व्यक्तिगत नियुक्तियों से परे, संगठन का काम अंतरराष्ट्रीय श्रम प्रवास के व्यापक परिदृश्य को आकार देना है। निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। यह एक ऐसे उद्योग में महत्वपूर्ण है जो अक्सर श्रमिक शोषण और अनैतिक भर्ती एजेंसियों की कहानियों से ग्रस्त रहता है।

एक पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को विदेश यात्रा करने से पहले उनके अनुबंध की शर्तों के बारे में पूरी जानकारी हो। यह दृष्टिकोण न केवल भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक नियोक्ताओं के साथ विश्वास भी बनाता है।

कुशल श्रम की वैश्विक मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर है, और भारत में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिभा है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई संगठनों ने हाथ बढ़ाया है। 'मैजिक बिलियन' विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए सम्मानजनक, अच्छे वेतन वाले रोजगार के अवसर पैदा करता है। 2018 में शुरू होने के बाद से, इसने 4,000 से अधिक भारतीय श्रमिकों को वैश्विक भूमिकाओं में नियुक्त करने में मदद की है।

यह केवल व्यक्तियों को नौकरी खोजने में मदद नहीं कर रहा है; हम ऐसे स्थायी करियर का निर्माण कर रहे हैं जो श्रमिक और उनके परिवारों दोनों को ऊपर उठाएं।इस तरह के संगठन के काम का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पहलू महिलाओं और युवा पेशेवरों पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। वैश्विक नौकरी बाजार इन समूहों के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य जैसे उद्योगों में। लक्षित कार्यक्रमों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने और विदेशों में उच्च वेतन वाली नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

यह भारत जैसे देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ कई क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में बाधाएँ अभी भी व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, नर्सिंग पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के संगठन के प्रयासों ने सैकड़ों महिलाओं के लिए उन देशों में काम करने के अवसर खोले हैं जहां स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की मांग बढ़ रही है। इससे न केवल व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ता है।

भारत का कुशल श्रम बल न केवल उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में योगदान दे रहा है जहाँ वे काम करते हैं, बल्कि भारत को भी महत्वपूर्ण लाभ पहुँचा रहा है। विदेशी श्रमिकों द्वारा घर भेजे जाने वाले धन विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत हैं और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रमिकों को वैश्विक नौकरियों में रखकर, हम घरेलू बेरोजगारी के कुछ दबावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह विशेष रूप से निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भारत में कुशल श्रमिकों की अधिकता है।

आप की बात

आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार रात को हुए आतंकी हमले ने इस संघशासित क्षेत्र में शांति की नाजुक स्थिति एक बार फिर उजागर कर दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद आतंकवादियों ने फिर से अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्वक हो गए। विधानसभा चुनाव में तो हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई और दशकों बाद मतदाताओं ने बड़ी संख्या में रिकार्डतोड़ मतदान किया। यह आतंकवादियों के लिए बड़ी विफलता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाहिर हो गया कि कश्मीर से आतंकवाद समाप्ति की ओर है। जैसे बुझने के पहले दिया फड़फड़ाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकी अपने खात्मे के ताबूत में अंतिम कील ठोक रहे हैं। अब्दुल्ला सरकार को सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग देकर तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन को अधिक सजग करके स्थिति को काबू में रखना होगा । खासतौर से आतंकियों को सहयोग देने वाले स्थानीय नागरिकों को चिन्हित करना जरूरी है क्योंकि उनके सहयोग के बिना आतंकवादी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कश्मीर की सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार से एकजुटता दिखानी चाहिए।

–**सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

नेतनयाहू पर निशाना

हिजबुल्ला आतंकियों ने इस्राइली प्रधानमंत्री नेतनयाहू के घर पर ड्रोन से निशाना लगाकर अपनी मौत को आमंत्रित किया है। नेतनयाहू ने स्वयं कहा है कि उनको व उनकी पत्नी को मारने की कोशिश कर हिज्बुल्ला ने बड़ी गलती कर दी है। हिजबुल्ला के इस हमले ने नेतनयाहू को अपने देश और दुनिया में ज्यादा मजबूत कर दिया है। इससे नेतनयाहू की नीतियों का समर्थन न करने वाले लोग भी उनके साथ एकजुट हो गए हैं। इस्राइल की जनता का एक हिस्सा भले ही अनेक नीतियों के मामले में नेतनयाहू का समर्थक न हो, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वह पूरी तरह एकजुट है। हिजबुल्ला के इस हमले से नेतनयाहू के प्रति उसकी एकजुटता और मजबूत हुई है। इससे नेतनयाहू के नेतृत्व में इस्राइली सेना हिजबुल्ला के उसी तरह पूर्ण सफाए के लिए संकल्पबद्ध हो गई है जिस तरह उसने गाजा में हमास का सफाया कर दिया है। अमेरिका ने भी हूती विद्रोहियों पर इसलिए हमले किए हैं क्योंकि वे समुद्री परिवहन को खतरे में डाल रहे थे। निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में शांति जरूरी है, पर यह आतंकियों के सफाए की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इन आतंकियों में हमास, हिजबुल्ला व हूती के साथ उनका समर्थक ईरान भी शामिल है।

– **एम.एम. राजावत,** शाजापुर

महाराष्ट्र की राजनीति

चुनाव की घोषणा के बाद यह तय था कि महाराष्ट्र में मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए होगा। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से दोनों पक्षों की नींद उड़ा दी है। जरांगे ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वे दलित, मुस्लिम, मराठा एवं किसान की जुगलबंदी से महाराष्ट्र में नई राजनीतिक ताकत खड़ी करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस प्रयोग से किसे नुकसान होगा, अभी इसका आकलन करना मुश्किल है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विरोध करने का साहस किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर लीपापोती के प्रयास भी लंबे समय से जारी हैं। ऐसे में मनोज जरांगे की चुनावी सफलता संदेह के घेरे में है। वैसे भी महाराष्ट्र में बहुकोणीय मुकाबले लगभग तय हैं क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी तथा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। ये दोनों पार्टियां दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस-रांकापा व उद्धव ठाकरे की चिन्ता मुस्लिम वोटों के संभावित विभाजन से और गहरा गई है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की प्रबुद्ध तथा तुलनात्मक रूप से समृद्ध जनता राज्य में किसे सत्ता सौंपेगी।

–**वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

भारत-विरोधी रिपोर्ट

ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हमेशा दुनिया के देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना बहस का विषय बनती है। 2024 में भी यही स्थिति है। भूख के मामले में 127 देशों की सूची में भारत 105 वें नंबर पर है और इसे बहुत ही चिंताजनक माना गया है। भले ही पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति सुधार पर है पर पड़ोसी और आर्थिक रूप से खस्ताहाल देश हमसे कहीं आगे दिखाए गए हैं। पश्चिमी दुनिया के कुछ संगठन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर हमेशा भारत-विरोधी रिपोर्टें जारी करते रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका नमूना है। भारत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से मुफ़्त राशन दे रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सहायता योजना है। भारत की प्रगति के साथ ही ऐसी भारत-विरोधी रिपोर्टें उसके प्रति ईर्ष्या प्रकट करती हैं। नाबार्ड ने माना है कि पिछले दस साल में औसत भारतीय ग्रामीण परिवार की आमदनी में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसे में भारत की अधिकांश जनता ऐसी रिपोर्टों पर हंसती है।

–**अमृतलाल मारू,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

पायनियर
लखनऊ, बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024

त्यौहारों के दृष्टिगत एडीजी जोन ने लिया तैयारियों का जायज़ा

संवाददाता। संतकबीरनगर

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर डॉ0 के0एस0 प्रताप ने मंगलवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता की उपस्थिति में पुलिस लाईन स्थित सभागार कक्ष में आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा आदि पर्वों के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान त्यौहार की तैयारियों एवं व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

त्यौहारों के संबंध में शासन के दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया व सभी से आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारा, समरसता, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। गोष्ठी के दौरान पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार का विवाद न होने देने, त्योहारों पर अशान्ति व उपद्रव करने वाले अराजक तत्वो की पहचान कर तुरंत उच्चाधिकारीगण को सूचना देने, त्यौहार में कोई नई परंपरा न डालने, निर्धारित मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर का प्रयोग कराने के साथ साथ ही किसी भी प्रकार के अफ़वाह एवं झूठी व भ्रामक खबरों का तत्काल खण्डन करते हुए प्रचारित प्रसारित करने हेतु अवगत कराया गया।

एडीजी द्वारा आगामी त्योहारों दीपावली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भैय्या दूज आदि को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस लाईन सभागार कक्ष संतकबीरनगर में की गई गोष्ठी, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर डॉ0 के0एस0 प्रताप द्वारा पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता की उपस्थिति में मंगलवार को आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, भैय्या दूज, छठ पर्व आदि के दृष्टिगत जनपद में शांति / कानून व्यवस्था बनाये रखने व लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत मेंहदावल बाईपास से मधुकुंज चौराहा तक फ्लैग मार्च / पैदल गश्त कर शहर में पुलिस के सक्रियता की जांच की गयी।

तीन स्वचालित मौसम तंत्र व पंद्रह स्वचालित वर्षामापी यंत्र हुए स्थापित

श्रावस्ती, भिनगा। जनपद में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए आपदा विभाग की ओर से 3 स्वचालित मौसम केंद्र व 15 स्वाचालित वर्षामापी स्थापित किए गये हैं इन सभी संयंत्रों का राहत आयुक्त कार्यालय से भेजे गये मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार गुप्ता जिले से नामित अभियंता संतोष कुमार अजय कुमार आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र व ओबेल सिस्टम्स के प्रतिनिधि संतोष शुक्ला द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौसम वैज्ञानिक द्वारा सभी स्थानीय अधिकारियों को इन उपकरणों की कार्यविधि व रख-रखाव की जानकारी भी दी गयी। जनपद की प्रत्येक तहसील में एक स्वचालित मौसम केंद्र व प्रत्येक ब्लॉक में तीन स्वचालित वर्षामापी इस तरह लगाये गये हैं कि पूरे जनपद का सटीक पूर्वानुमान प्राप्त हो सके इन उपकरणों के माध्यम से वर्षा की मात्रा हवा की गति तापमान हवा की दिशा आद्रता वायुमंडलीय दाब की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

मौसम वैज्ञानिक अतुल गुप्ता ने बताया कि इन संयंत्रों की स्थापना के बाद संबंधित क्षेत्र का सटीक डाटा त्वरित रूप से प्राप्त होता रहेगा जिससे मौसम वैज्ञानिकों को उस क्षेत्र का सटीक पूर्वानुमान बताने में सहायता मिलेगी।

अवैध रूप से नहरों की कटान करने पर होगी एफआईआरः जिलाधिकारी

संवाददाता। गोंडा

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जनपद में आगामी रबी फसली 1432 में कृषकों को सुचारूरूप से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद की नहरों की सिल्ट सफाई ध् स्कैपिंग का कार्य कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एक्सईएएन सरयू नहर खण्ड-4 दुर्गेश कुमार गर्ग के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 190 नहरें तथा 1128 किलोमीटर की है। जिसमें केवल 165 नहरों की 850 किलोमीटर की सिल्ट सफाई का कार्य किया जाना है।

बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नहरों की सिल्ट सफाई के दौरान कार्य शुरू होने से पहले एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराया जाय। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जनपद में जितने भी नहरों की सिल्ट सफाई किया जाना है, उन सभी नहरों के लिए संबंधी विभाग से एई एवं जेई की ड्यूटी लगाई जाय, तथा उनको यह निर्देश दिया जाय, कि कार्य प्रारम्भ के समय बराबर निरीक्षण करें तथा अपनी उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण एवं समय से कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहरों की सिल्ट सफाई में यदि कहीं गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक में जनपद की नहरों तथा उस पर विगत वर्ष कराये गये सिल्ट सफाई कार्यों की भी चर्चा के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिल्ट सफाई स्कैपिंग कार्यों हेतु चयनित नहरों पर चर्चा की गयी जिसमें जनपद में लगभग 850 किमी0 नहरों की सफाई कराने की तैयारी कर ली गई।

गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने किया जनपद का भ्रमण

संतकबीरनगर। उपाध्यक्ष गोसेवा आयोग, उ0प्र0 महेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम उपाध्यक्ष गोसेवा आयोग, उ0प्र0 महेश कुमार शुक्ल को मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपाध्यक्ष गोसेवा आयोग, उ0प्र0 महेश कुमार शुक्ल ने सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि गौवंश के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा गोसेवा आयोग का गठन करके गोवंशों को संरक्षित करने के लिए छुट्टे पशुओं को वृहद टीम के आधार पर ग्राम प्रधानों के माध्यम से समिति गठित करके गौशाला में संरक्षित किया जा रहा है। समाज के सभी लोगो के सहयोग से गौवंशों का संरक्षण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में 15 लोगो की टीम बनाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में गोशालाओं के संचालन सहित गो संरक्षण से सम्बंधित बिन्दुओं को आकड़ेवार अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद के गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों हेतु हरा चारा उगाने के दृष्टिगत जमीन चिन्हित कर हरा चारा उगाया जा रहा है तथा शेष हेतु जमीन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास जारी है। उपाध्यक्ष द्वारा किसानों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंशों का पालन एवं सेवा करने हेतु प्रेरित करने का भी सुझाव दिया गया। उपाध्यक्ष ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित समस्त पशु चिकित्साधिकारियों से उनके अन्तर्गत आने वाले गोशालाओं में गोवंशों की स्थिति, स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन किया।

उन्नतिशील बीज के लिए किसान परेशान

अमेठी। उन्नतिशील बीज के लिए किसान परेशान है। सरकारी बीज बिक्री केंद्र पर खरीद रसीद नही मिलती है। यही निजी बीज की दुकान का हाल है। बाजार के अनाज को बीज बताकर उसे नयी बोरी मे पैकिंग कर मालामाल हो रहे है। गेंहू और सरसो के बीज मे निजी दुकानदार धडल्ले से खेल कर रहे है। बीज की जांच के नाम पर दुकानदारो से जिले भर मे लाखो रुपये की अबैध वसूली खुलेआम होती है। बीज के सेम्पुल सिर्फ दिखावा होता है। प्रमाणित बीज को फाउंडेशन बीज के नाम बीज बेचने का खेल आजकल सरकारी बीज बिक्री केंद्र पर चल रहा है।

सरकारी बीज की दुकान पर अगूठा लगाते है। पीएस मशीन से बीज बिक्री का मूल्य रसीद निकलती है। लेकिन किसी किसान को नही दी जाती है। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह ने नकली बीज बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई है। हाईब्रिड सरसो का बीज मूल्य आठ सौ बारह सौ रुपए है लेकिन पैदावार नही मिलती है। नकली बीज पर सरकार अंकुश लगाए। कांग्रेस किसान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश दूबे का कहना है कि बीज खरीदारी मे लूट मची। किसान ठगा जा रहा है। सरकारी बिभाग की दुकान पर निशुल्क मिनी कीट सरसो,चना,मटर,मसूर का किसानो से मूल्य वसूले जा रहे है । प्रदर्शन योजनाओ के नाम पर किसान ठगा जा रहा है। सरकारी बीज कर्मचारी बेच लेते हैं। आज की हाल खराब है । प्रदर्शन कही देख नही सकते है। सब खेल पर चल रहा है। जिलाधिकारी और मुख्य बिकास अधिकारी मामले की जांच पड़ताल करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी अपने-आप हो जाएगा।

डीएम ने ली जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक

अमेठी। आज जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, प्राचार्य डायट, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, पैक्सफेड प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कायाकल्प के 19 पैरामीटर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण की प्रगति, निपुण असेसमेंट टेस्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मध्याह्न भोजन योजना एवं सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गये। निपुण असेसमेंट टेस्ट में जनपद के बेहतर प्रदर्शन के लिए बेहतर रणनीति के साथ कार्य किए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

अग्नि सुरक्षा जन-जागरूकता प्रशिक्षण अभियान का किया गया आयोजन

अमेठी। अग्निशमन अधिकारी शिवदरस प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष दीपावली का मुख्य पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जायेगा व दीपावली पर्व पर प्रत्येक परिवार में दीप प्रज्जवलित कर तथा आतिशबाजी कर हर्षोल्लास से खुशियों से मनाया जाता है तथा ऐसे शुभ अवसर के समय थोड़ी सी लापरवाही माहौल को गम में परिवर्तित कर सकती है।

उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक अमेठी के आदेशानुसार अग्निशमन एवं आपात सेवा केन्द्र अमेठी द्वारा अग्नि सुरक्षा जन-जागरूकता प्रशिक्षण अभियान चलाया गया तथा जन-जागरूकता प्रशिक्षण अभियान में अग्निशमन अधिकारी अमेठी शिवदरस प्रसाद द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ रानी सुषमा देवी महिला पीजी कालेज देवीपाटन अमेठी में अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं, अध्यापक-अध्यापिकाओं एवं स्टाफ को जागरुक करते हुए आग लगने के सम्भावित कारकों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्यूशरों को चलाने के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए घरों एवं रसोईघरों में अग्निसुरक्षा, एलपीजी से बचाव एवं सावधानियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देकर जागरुक किया। इस दौरान जागरूकता अभियान में रानी सुषमा देवी महिला पीजी कालेज देवीपाटन अमेठी की प्राचार्या डॉ0 पूनम सिंह, शिक्षिका डॉ0 पूनम सिंह, डॉ0 कामना सिंह, डॉ0 कंचना पाण्डेय, प्रियंका मिश्रा, वंदना सिंह, प्रज्ञा मिश्रा व हौशला प्रसाद सहित उपस्थित छात्र-छात्राओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया तथा अग्निशमन तथा आपात सेवा केन्द्र अमेठी के प्रशिक्षक फायरमैन अमित कुमार, अरविन्द, आशीष सिंह, रोहित कुमार गौतम व सौरभ ने प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

महिलाओं को सशक्त बनाना मिशन शक्ति का उद्देश्यः दानिश हसनैन

गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व महिला कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत आपरेशन मुक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अपर जिला जज/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश हसनैन ने लोगों को विधिक जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, इसको खत्म करना हम लोगों की अहम जिम्मेदारी है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा ने बालिकाओं को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। संरक्षण अधिकारी चंद्र मोहन वर्मा ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप आदि योजनाओं के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी दी गई। महिला थाना प्रभारी प्रतिभा सिंह द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए जारी टोल फ्री नंबर 112, 181, 1090, 1098, 108, 102, 1076, 1930 आदि की जानकारी दी गई। सेंटर मैनेजर चेतना सिंह द्वारा जनपद में संचालित वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया गया।

मिट्टी खनन माफियाओं पर चलाया एसडीएम ने कानून का चाबुक

कोंच, जालौन। मंगलवार को कोच कोतवाली क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार कई दिनों से जोरो से चल रहा था जिसकी आज पुलिस प्रशासन को सूचना मिली तो मिट्टी खनन करने वाले बेखौफ हो चुके मिट्टी माफ्यिाओं पर एसडीएम, तहसीलदार के साथ पुलिस ने छापेमारी कर ट्रैक्टर सहित कई मशीनों को भी दबोच लिया। उक्त कार्यवाही के बाद अवैध मिट्टी कारोबार से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दे कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड पर ग्राम पनियार के पास में एक खेत से अवैध मिट्टी खनन करते हुए एसडीएम ज्योति सिंह व पर प्रभारी तहसीलदार जीतेन्द्र पटेल व कोतवाल अरुण कुमार रॉय ने मिट्टी धारण करते हुए मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्राली व छोटी जेसीबी को दबोच लिया।

पुलिस ने ट्रेक्टर ट्राली ओर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एसडीएम ज्योति सिंह ने कहा है अगर मिट्टी खनन किसकी भी तरह नही किया जाएगा अगर मिट्टी खनन की सूचना मिलती तो मिट्टी खनन माफ्यिाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जल-जीवन मिशन की खराब प्रगति पर डीएम नाराज़

संवाददाता। उरई, जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी एवं बेहतर ढंग से किया जाए ताकि सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ा जा सके और उनकी समस्याओं का भी बुनियादी समाधान हो सके। समीक्षा के दौरान प्रभारी परियोजना अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, जल संस्थान अधिशासी अभियंता अनुपस्थित व विभागीय प्रगति खराब होने पर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति में सुधार लाएं और टीम भावना के साथ कार्य करें। यदि किसी भी अधिकारी की प्रगति में शिथिलता पाई गई तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चेक करें। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि निमार्णाधीन सडकों एंव परियोजनाओं को समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। जल-जीवन मिशन में खराब प्रगति मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सडकों का बेहतर तरीके से रेस्टोरेशन कार्य कराया जाए। समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन हर घर जल, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत, प्रोजेक्ट अलंकार, व्यक्तिगत शौचालय, निपुण भारत की प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रगति में सुधार लाएं कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने श्रम आयुक्त को निर्देशित किया कि जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों का सत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। धान क्रय केंद्रों पर किसानों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित कर लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीद सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान की पराली को कोई भी किसान आग न लगाएं, किसानों से संपर्क कर पराली खेत से निकालकर गौशालाओं में भंडारण किया जाए जिससे आने वाले समय में उसका सदुपयोग किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, शिशु मातृत्व एवं बालिका मदद योजना के पात्र लाभार्थियों को अभियान चलाकर चिन्हित कर योजनाओं से जोड़ा जाए जिससे योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नरेंद्र देव शर्मा, प्रभारी जिला विकास अधिकारी महेंद्र चौबे, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीएसटीओ नीरज चौधरी आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

डेंगू के पैर पसारने से नागरिक चिंतित

लालगंज, रायबरेली। लालगंज खंड में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या से नागरिक चिंतित हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी चिकित्सकों के अस्पतालों तक डेंगू मरीज निकल रहे हैं। बढ़ते बुखार एवं प्लेट्लेट्स में तेजी से होने वाली गिरावट के बावजूद सरकारी अस्पताल में इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है। जांच में डेंगू बुखार निकलने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में बैठे चिकित्सक न तो मरीजों व उनके तीमारदारों को बता रहे हैं और न ही उनका प्रापर इलाज ही हो पा रहा है। वहीं निजी चिकित्सकों के यहां डेंगू का प्रापर इलाज लेकर बुखार से पीड़ित मरीजों को राहत मिल रही है। प्राइवेट पैथालाजी संचालकों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय बुखार की जांच के लिए आने वाले पांच मरीजों में तीन मरीज डेंगू बुखार से पीड़ित मिल रहे हैं। लालगंज नगर एवं क्षेत्रीय गांवों में बुखार से पीड़ितों की संख्या बढ़ने के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और न ही मच्छर भगाने के लिए कोई छिड़काव ही कराया गया है।

युवक के अपहरण का मामला निकला नाटक

लालगंज, रायबरेली। कोतवाली पुलिस के मलपुरा गांव से युवक के अपहरण का मामला महज नाटक निकला। अपहरण की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने जांच पड़ताल शुरू की। बीते करीब 20 घंटे बाद पुलिसिया जांच में मामला महज नाटक होने का पटाक्षेप हुआ। उल्लेखनीय है कि बीती रात मलपुरा गांव के रहने वाले रामू पुत्र छेदई के अपहरण की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी। समूचे जिले में सूचना प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आ गयी। गांव निवासिनी शिवभोली देवी ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे उसका बेटा रामू (19) रात को घर से शौच के लिए निकला था, जिसके बाद वह फिर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन की गई, लेकिन बेटा कहीं ढूंढे नहीं मिला। रामू अपने साथ अपना मोबाइल फोन भी लेकर गया है। सुबह युवक के मामा ने रामू को फोन किया तो उसने खुद को बचा लेने की बात कही। उसने मामा से बताया कि वह कहीं तकिया बीघापुर और कानपुर बीच किसी जंगल में है। कहा कि वह किसी तरह बदमाशों से दूर हटकर उससे बात कर रहा है। बदमाश उससे 50 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। गायब युवक के परिजनों ने यह सारी बातें पुलिस को भी बताई हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद युवक को बरामद कर लिया गया है।

बनारस के डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट कॉलेज का नाम बदले जाने पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध

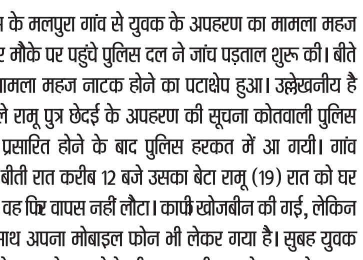

रायबरेली। रायबरेली में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने बनारस जनपद में स्थित वर्षों पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट कॉलेज का नवीनीकरण के नाम पर नाम बदले जाने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारद की जताते हुए विरोध किया है और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दे कि आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को रायबरेली जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है। मीडिया से बात करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट कॉलेज का नवीनीकरण के नाम पर नाम बदल दिया गया है जिसका अब नया नाम बनारस एक्सपोर्ट एकेडमी रखा गया है जिसका विरोध किया गया है कहां है कि ऐसे महान पुरुषों का नाम बदलना निंदनीय है ।

केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का किसान उठाएं लाभः गौरीशंकर

संवाददाता। उरई, जालौन

जमुना पैलेस उरई में फसल प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रबी उत्पादकता गोष्ठी एवं तिलहन मेला आयोजित किया गया। गोष्ठी में विधायक सदर गौरीशंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास ने फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात किसान द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया।

विधायक सदर गौरीशंकर वर्मा ने रबी फसलों की विशेषताएं, उर्वरक प्रबंधन, और नई तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है जिससे किसान अपनी फसल का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे है। उन्होंने किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित में योजनाएं बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे किसान सशक्त हो सके।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नवीनतम कृषि तकनीकी से कृषकों को अवगत कराना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कृषि निवेश, जैसे उर्वरक, बीज, पेस्टीसाइड और सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की शिल्ट सफाई का रोस्टर समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इससे किसानों को समय पर टेलों तक पानी प्राप्त होगा और उनकी फसलें सही समय पर सिंचाई हो सकेंगी। उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि किसानों को जल संकट का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जनपद में डीएपी खाद, यूरिया खाद आदि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किसान भाई सहकारी समितियां से आसानी से ले सकते हैं।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रोस्टर अनुसार सुनिश्चित रहे, जिससे किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि वर्षा के समय किसानों के घर फसलों की क्षति हुई, जिसका सर्वे कराकर किसानों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को खाद बीज आदि उर्वरक पानी की समस्या होने पर तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 9450072937 व 9670670065 पर शिकायत दर्ज कराएं जिससे 24 घंटे के अंदर शिकायत का समाधान किया जाता है, शिकायतों का मेरे द्वारा स्वयं परीक्षण किया जाता है।

सहकारी समितियों में पहुंच एसडीएम ने खाद वितरण व्यवस्था परखी

कालपी, जालौन। मंगलवार को उर्वरक की वितरण व्यवस्था की हकीकत को परखने के लिए उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने दमरास तथा इटौरा की सहकारी समितियो का औचक निरीक्षण किया। तथा जिम्मेदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय हो कि कालपी क्षेत्र में किसानों को सुगमता पूर्वक खाद वितरण करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

शीर्ष अधिकारियों को सहकारी समितियां से उर्वरक की बिक्री करने के लिए निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने दमरास में स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड का निरीक्षण किया गया तथा उर्वरक की बिक्री देखी। परिसर में गंदगी देखकर नाराजगी जताई। दमरास गांव में एक लाइसेंस धारक की दुकान को भी चेक किया। इसके पहले इटौरा सहकारी समिति लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो कर्मचारी नहीं मिले। उप जिलाधिकारी ने सहकारी समिति में उर्वरक की बिक्री के अभिलेखों की जांच की तथा निर्देश दिए के किसानों को सरलता पूर्वक खाद का वितरण किया जाए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाने पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

सफाईकर्मियों की लचर कार्यशैली के चलते शिक्षक कर रहे विद्यालय की सफाई

ऊंचाहार। सफाईकर्मियों की लचर कार्यशैली के चलते शिक्षक को ही विद्यालय में साफ सफाई करनी पड़ रही है। मंगलवार की सुबह पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का विद्यालय परिसर में साफ सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन विद्यालय पहुंचे सफाईकर्मियों की टीम ने साफ सफाई शुरू कर दी। वर्तमान में क्षेत्र की बिकई गांव निवासी बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी के पति पुतुन निर्मल पूर्व माध्यमिक विद्यालय सवैया राजे में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। उनका कहना है कि पिछले एक महीने से सफाई कर्मी विद्यालय नहीं आया, जिसके लिये अक्सर मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ती है। इस सम्बंध में एडीओ पंचायत संजीव शर्मा ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया है।

डीएम ने की जनपदीय स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

● सभी एमओआईसी व डिप्टी सीएमओ संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की करे साप्ताहिक समीक्षाः डीएम

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह की अध्यक्षता में जनपदीय स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में की गई। सर्वप्रथम गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। डीएम ने सभी एमओआईसी व डिप्टी सीएमओ को निर्देशित किया कि विभाग अन्तर्गत संचालित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की साप्ताहिक समीक्षा करें, जिन कार्यक्रमों के संचालन में कोई कमी पायी जाये उस पर विशेष जोर देकर कमियों को दूर कराया जाये। संचालित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों रेण्डम चेकिंग करायी जाये। डीएम ने सीवियर एनीमिया व हाईरिस्क प्रसव की लगातार मानीटरिंग करने के निर्देश दिये। जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कराया जायेए साथ ही मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने पर विशेष जोर दिया जाये। मातृत्व मृत्यु के कारणों का पता कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। डीएम ने सभी निजी अस्पतालों से मातृत्व मृत्यु दर संबंधी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश सीएमओ को दिये। एसएनसीयू के अन्तर्गत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त रहे। फैमली प्लानिंग, आभा आईडी आदि का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण किया जाये। गर्भवती महिलाओं व बच्चों के शत प्रतिशत टीकाकरण किया जाये। जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को संस्थागत प्रसव बढ़ाने व आशाओं के मानदेय का समय से भुगतान कराने के निर्देश दिये। डीएम ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिए। आरबीएसके टीम कमजोर बच्चों का चिन्हांकन कर प्रभावी कार्यवाही करें। बैठक में टीकाकरण, टीबी, तम्बाकू उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आदि की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए गए। तृतीय पक्ष डब्ल्यू एचओए यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वे की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान अन्तर्गत कार्ययोजनानुसार विभिन्न विभाग आपस में समन्वय करके साफसफाई व अन्य गतिविधियां समयान्तर्गत करें।

डीएम, सीडीओ व डीपीआरओ ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

गुरसहायगंज (कन्नौज)। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला व सी.डी.ओ., डी.पी.आर.ओ., अग्रणी जिला प्रबन्धक, ए.डी.ओ. पंचायत अनोगी, बी.डी.ओ. जलालाबाद द्वारा कौशल विकास केन्द्र में बंदियों द्वारा बनायी जा रही वस्तुओं का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपदीय अधिकारियों द्वारा कौशल विकास केन्द्र में वस्तुओं को बना रहे बंदियों को दो-दो टी-शर्ट व मिष्ठान का वितरण किया गया। सोमवार को बंदियों द्वारा कौशल विकास केन्द्र में बन रही वस्तुएं यथा बंदियों द्वारा बनायी जा रही जगमग झालरे लाइटे, फेटो प्रेम पर गणेश लक्ष्मी व विभिन्न प्रकार के फेटो लगाकर एलईडी लाइटे व विभिन्न रंगों के कपड़े के कैरी बैग की प्रशंसा की गयी। बंदियों में झालरों के प्रति अतिउत्साह देखा गया। इस दौरान जेल अधीक्षक मो. अकरम खॉं, कारापाल विजय कुमार शुक्ला, उपकारापाल श्रीरामबहाल दुबे, उपकारापाल उर्मिला सिंह, उपकारापाल आशादेवी पाण्डेय, चिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार, प्रभारी मुख्य कार्यालय पंकज कुमार के साथ सभी प्रशासनिक कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सहायक शिक्षाध्यापक मनोज कुमार कटियार द्वारा किया गया।

बंदी को उपहार भेंट करते डीएम व अन्य।

● अधिकारियों ने जेल में बनाई जा रही वस्तुओं को अवलोकन बांटी टी-शर्ट

झावर तालाब के बहुरेंगे दिन, पर्यटन को लगेंगे पंख

● विधायक और सीडीओ ने अफसरो संग बनाई रणनीति, दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी। मंगलवार को सीडीओ अभिषेक कुमार गोला गोकर्णनाथ पहुँचे, जहां उन्होंने विधायक अमन गिरि संग तहसील विकासखंड गोला के अंतर्गत ब्लॉक गोला की तीन ग्राम पंचायत में फैले 96 एकड़ के झावर तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के उद्देश्य से स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य रूप से पीडी एसएन चौरसिया, डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी, एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता, बीडीओ हनुमान प्रसाद मौजूद रहे।

विधायक गोला अमन गिरी ने सीडीओ अभिषेक कुमार के साथ झावर तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान झावर तालाब को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की रणनीति पर गहन मंथन हुआ।

सर्वसम्मति से तय किया कि प्रथम चरण में 30 एकड़ के क्षेत्र पर फोकस करते हुए विकसित किया जाए। सीडीओ ने मौजूद तकनीकी अफसरो को तय क्षेत्र का सुंदरीकरण के लिए प्लानिंग एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। इसमें बेसिक डिजाइनए फूड कोर्टए प्लांटेशन, ट्रेक और बेंच निर्माण आदि को शामिल किया जाए। उन्होंने जलकुंभी की सफाई, तालाब के किनारों का निर्माण किस प्रकार कराएंगे इस पर भी अफसरो संग रणनीति बनाई।

सीडीओ ने अवर अभियंता ;लघु सिंचाईद्ध को प्रथम चरण के लिए चिन्हित क्षेत्र को विकसित करने में आने वाली लागत के आगणन करने के निर्देश भी दिए। विधायक अमन गिरी ने अफसरो को आश्वस्त किया कि आप प्रोजेक्ट तैयार कराए। इस कार्य में विधायक निधि, ग्राम निधि, क्षेत्र पंचायत निधि, मनरेगा, सीएसआर से फंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विधायक ने तालाब के एप्रोच मार्ग को भी सुगम बनाने के लिए चर्चा की, ताकि इसके तैयार होने के बाद लोग यहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे।

डीएम आंगनबाडी केंद्र का निरीक्षण व उचित दर दुकान का उद्घाटन

फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम गुताशी पंचायत कार्यालय द्वारा ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई व मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी पंचायत सहायको का प्रशिक्षण कराया जाये। ऑगनबाडी केंद्र का निरीक्षण किया गया व निर्देशित किया गया कि ऑगनवाडी केंद्र में लर्निंग लैब विकसित की जाये। ऑगनवाडी केंद्र में 52 बच्चे पंजीकृत पाये गयेए जिलाधिकारीद्वाराऑगनबाड़ी किट उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये गये। डीएम द्वारा गुतासी आरोग्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मरीजों को दी जा रही दवाओं के एक्सपायर होने में 02 से 03 दिन शेष है। डीएम द्वारा निर्देशित किया गया कि मरीजो को ऐसी दवाएं उपलब्ध कराई जाये जिनकी एक्सपाइरी में कम से कम 06 माह शेष होए केंद्र पर तैनात एएनएम ट्रेनिंग में बरौन गये थे केंद्र पर आज कुल 13 मरीज देखे गये। इस अवसर पर सीडीओ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एडीओ पंचायत व संवंधित उपस्थित रहे।

शासी निकाय की बैठक में योजनाओ व कार्यक्रमों की हुईं समीक्षा, दिए गए दिशा निर्देश

फतेहपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। डीएम ने स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों से कहा कि अपने दायित्वों का निर्वाहन जिम्मेदारी के साथ करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए। स्वास्थ्य से संबंधित संचालित योजनाओ व कार्यक्रमो की प्रगति की अद्यतन स्थिति को जाना और संबंधितो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराते हुए सभी जांचे व अनुमन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये साथ ही गर्भवती महिलाओ व बच्चों का टीकाकरण समय से कराते हुए पोर्टल पर फीड कराये एवं हाईरिस्क गर्भवती महिलाओ की नियमित जाँच करते हुए गंभीर एनिमिक गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता अनुसार आयरन, सुक्रोस के डोज एवं अन्य सभी स्वास्थ्य सुविधाएं संवेदनशीलता के साथ मुहैया कराये और किस कारण से हाईरिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी मे है, का कारण भी बताये और उनको अवगत कराये कि प्रिकाशन/ स्वास्थ्य सुविधाओ व जांचो की आवश्यकता है, का पंपलेट हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराये, जिससे प्रेग्नेंसी के दौरान कोई असुविधा न हो। सभी लाभार्थीपरक योजनाओ से लाभार्थियों से लाभांवित करने के लिए समय से शत प्रतिशत भुगतान किया जाय एवं जिन स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों के भुगतान का प्रतिशत कम है से स्पष्टिकरण लेने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये। जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केन्द्र मे भर्ती किये गए कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों का डिस्चार्ज के बाद कितना औसत वजन बढ़ा है कि रिपोर्ट से अवगत कराते हुए डिस्चार्ज किये गए बच्चों की शतत् निगरानी बनाये रखने के निर्देश संबंधितो को दिये। स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओ की हुई मृत्यु की आडिट की रिपोर्ट से अवगत कराये साथ ही कारण का भी उल्लेख करें एवं मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है।

आजीवन कारावास सजायफ्ता बृद्ध कैदी की उपचार के दौरान मौत

फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार के एक आजीवन कारावास सजायफ्ता वृद्ध कैदी की आज मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के फतह नगला का निवासी शिवराम उम्र करीब 68 वर्ष पुत्र सीताराम को हत्या आदि एक मामले में फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत से आजीवन कारावास की सजा13.11.2006 को सुनाई गई।जेल सूत्रों ने बताया कि आजीवन कारावास सजायफ्ता 68 वर्षीय कैदी शिवराम 19.11.2006को सजा भुगतने के लिए फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में आया। इसके बाद काफी समय से बीमार इस कैदी को किडनी जैसे रोग की आज शिकायत हुई। जेल अधिकारियों ने बीमार किडनी रोग से पीडित कैदी शिवराम को आज मंगलवार प्रात हालात जब ज्यादा खराब हुई तो उसे फर्रुखाबाद के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया।

क्विक न्यूज

एसीएमओ ने फर्जी डाक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज के दिये निर्देश

फर्रुखाबाद। झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलाये जा रहे छापामारी अभियान में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध अलग.अलग स्थान में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने मुकदमा लिखने की संस्तुति की है। ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें थाना अमृतपुर में प्रेक्टिस करने वाले सुखबीर कुशवाहा, अजय पाल कुशवाहा के छापामारी की गई और उनसे आवश्यक कागजात तलब किए गए लेकिन निर्धारित तिथि तक वह कागराज नहीं दिखा सके इस कारण से एसीएमओ रंजन गौतम ने प्रभारी निरीक्षक अमृतपुर को इन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए संस्तुति की है। इसी तरीके से छापेमारी में मेरापुर के केपी हेल्थ सेंटर, राजेपुर के गांव सराह के निर्देश यादव एदहलिया के विजय, कमालगंज क्षेत्र के इंदिरा नगर में प्रेक्टिस करने वाले उमेश चंद्र पुत्र जदुनाथ सिंह, थाना कायमगंज के रविकांत गौतम, बंगालीएवीरेंद्र सिंह, हिमांशु बेरहामपुर आरिफखान, राजेंद्र अजय सभी के द्वारा आवश्यक कागजात अथवा स्पष्टीकरण न दे पाने के चलते के संबंधित थानों में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की संस्तुति विभाग द्वारा की गई है।

एसडीएम ने नकली उर्वरक का गोदाम किया सील

संडीला (हरदोई)। नकली खांद्य की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने जिला कृषि अधिकारी के साथ छापा मारा और वहां मिली खाद्य को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम डॉ0 अरुणिमा श्रीवास्तव को यह शिकायत मिली थी कि ग्राम टिकरा दाउदपुर में नकली डीएपी तथा अन्य खाद्यों की बिक्री की जा रही है। इस पर एसडीएम ने जिला कृषि अधिकारी डॉ0 सतीश पाठक के साथ पुलिसबल लेकर गोदाम में छापा मारा। दो अधिकारियों ने गोदाम के भीतर जाकर जब देखा तो वहां नकली बोरियों में विभिन्न प्रकार के उरर्वक वहां रखे थे। एसडीएम ने 188 कट्टा डीएपीए 64 बैग एनपीकेए एनपीएस 9 बैग तथा अन्य खाद्या 55 बैगए धागे के 14 डिब्बे 5 किलो का बांट और विभिन्न ब्रांडों के 24 नए कट्टे बरामद हुए। साथ ही साथ इन खाद्यो को तौलकर भरने के लिए यहां धर्मकांटा भी लगा था। एसडीएम ने तमाम खाद्यों के सैंपल लेने के बाद इस गोदाम को सील करा दिया है।

नहर से बरामद शव की हुई शिनाख्त

बकेवर (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के दिलावलपुर बेरॉव नहर से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने लगभग 24 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया था जिसकी शिनाख्त मृतक के परिजनों ने गुड्डू उर्फओम प्रकाश पुत्र स्व0 सिपाहीलाल निवासी जगराजपुर थाना सिबली जनपद कानपुर देहात के रूप मे करते हुए बताया कि दो दिन पूर्व वह घर से लापता हो गया था जिसकी तलाश रिश्तेदारों में की जा रही थी। मोबाइल में मिली फोटो के आधार पर परिजनों ने उसकी शिनाख्त पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर की है। परिजनों ने बताया कि मृतक चार दिन पूर्व बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक अपने कुछ साथियों के साथ वह घर से निकल गया और इसके बाद नहीं लौटा।

किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी अभिमन्यु ने आज सुबह अपनी पुत्री करिश्मा को किसी बात को लेकर डांट-डपट दिया। क्षुब्ध होकर उसने जहर खा लिया। कुछ समय बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे तत्काल सरकारी एंबुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल आए जहां चिकित्सक ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया। किशोरी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उधर परिजन शव को लेकर वापस गांव चले गए।

चारों ने नहीं बख्शा भाजपा विधान परिषद सदस्य का कॉलेज

संडीला (हरदोई)। भाजपा विधान परिषद सदस्य के डिग्री कॉलेज में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए पर हाथ साफ़कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार के संरक्षण में चलने वाले सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय की खिड़की का गिल काटकर अज्ञात चोरों ने कॉलेज में प्रवेश किया और अलमारी तोड़कर 2 लाख 57 हजार 250 रुपए चोरी कर लिए। दूसरे दिन जब कॉलेज के प्रिंसिपल वहां पहुंचे तो उन्होनें खिड़की का जाल कटा हुआ और अलमारी का लॉक टूटा हुआ देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताते चलें कि इसी महाविद्यालय में पहले भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है लेकिन पुलिस उसका खुलासा आज तक नही कर पाई है।

रोजगार मेले में 170 अभ्यर्थियो का प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया चयन

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में जिला सेवायोजन कार्यालय कानपुर देहात के द्वारा स्थान राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात के परिसर में 22.10.2024 को एक दिवसीय रोजगार मेला एवं कॅरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य काउंसलर अनिल द्विवेदी प्रवक्ता सरला द्विवेदी अकबरपुर, कानपुर देहात मे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 08 कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। लगभग 285 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया जिसमें 170 अभ्यर्थियो का प्राइवेट कम्पनियों द्वारा प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार मेले को सफल बनाने हेतु सेवायोजन कार्यालय के तेज प्रताप सत्यर्थी, अनुज यादव, रामकिशोर सोनकर, विनोद कुमार, राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात के प्राचार्य डॉ संन्जु व समस्त स्टाफ के सहयोग से मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

दस विकास खण्ड के 618 ग्राम पंचायतों एवं 02 नगर पालिका एवं 11 नगर पंचायतों में 25 अक्टूबर, 2024 से होगी 21वीं पशुगणना

संवाददाता। कानपुर देहात

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद में 25 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी 21वीं पशुगणनाए इसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा गणनाकार कार्मिकों की ट्रेनिंग सभी तहसीलों में करा ली गयी है। 20वीं पशुगणना 2019 में हुयी थी, जिसके हिसाब से 783944 (गौवंश व महिषवंश) पशुधन है इन पॉच वर्षों में जिले में पशुओं की संख्या बढ़ी या घटी 21वीं पशुगणना में स्थिति साफ हो जायगी।

पशुपालन विभाग द्वारा 21वीं पशुगणना के कार्य हेतु 25 सुपरवाइजर (उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी के अन्तर्गत 130 गणनाकार को लगाया गया है जिनमें पशुधन प्रसार अधिकारी/ पैरावेट/पशु मैत्री सम्मिलित है जो सभी अपने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पशुगणना का कार्य करेगें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 21वीं पशुगणना का कार्य 25 अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ होकर फरवरी 2025 के तक पूर्ण कर लिया जायेगा और पशुगणना का कार्य एन्ड्रॉइड मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल रूप से होगा जिसका ऐप 25 अक्टूबर 2024 को लांच किया जा रहा है, तत्पश्चात संकलित पशुगणना का डाटा परीक्षण के पश्चात भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। पशुगणना कि लिये डा. सुबोध कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

मनमोहक झांकियों के साथ धूमधाम से निकली श्री राम की बारात -जय श्रीराम के उद्घोष

गुरसहायगंज (कन्नौज)। नगर के तिर्वा रोड से नव निर्मित श्री आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की बारात का शुभारम्भ पूर्व राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय व समिति के अध्यक्ष मयंक गुप्ता व पदाधिकारियों ने आरती वन्दना कर किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात में बारातियों के रूप में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाराती बने नागरिकों ने जय श्रीराम का उद्घोष किया तो पूरा नगर राममय हो गया।

रामबारात में गणेश पूजन व अगुवाई करतीं पूर्व राज्यमंत्री व समिति अध्यक्ष।

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की बारात में शामिल मनमोहक झांकियां लोगो के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। जिसमें 65 भव्य रथों के साथ पार्टी के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित शिव ताण्डव, मुरली प्रदर्शन ने दर्शकों का मनमोहा तो प्रथम पूज्य गजानन के बाद क्रमशः राधा कृष्ण, सुदामा कृष्ण, मॉ जगदम्बा, शंकर परिवार, ब्रहमाजी आदि सहित अन्त में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण व गुरू वशिष्ठ के साथ विराजमान थे। राधा-कृष्ण बने कलाकार ने बृज की बयार बहा दी। काली अखाड़े के कलाकारों ने भी प्रदर्शन किया। कोई गली और सड़क ऐसी नहीं थी जहां भीड़ न हो। सड़कें सतरंगी रोशनी में सराबोर थीं। भगवान की बारात नगर के तिर्वा रोड से जीटी रोड, क्रासिंग, रामगंज होती हुई तिराहा स्थित मॉ संतोषी माता मन्दिर तक पहुची। श्रीराम के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। वही छतों पर बारात आगमन की प्रतिक्षा में बैठी महिलाओं ने पुष्पवर्षा कर मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की बारात का भव्य स्वागत कर अलौकिकता देखी। इस दौरान देवेन्द्र देव, विनय वर्मा, रामकुमार पाठक, गौरव दुबे, राजीव ठाकुर, शिवमराज वर्मा, रंजीत गुप्ता, संजय तिवारी, विकास गुप्ता, संदेश गुप्ता हीरो आदि ने भी फूलमालाओं से रामबारात का स्वागत कर शोभा यात्रा में भाग लिया।

विज्ञान प्रदर्शनी में चयनित हुईं सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां, 250 छात्र-छात्राओं ने किया प्रतिभाग

फतेहपुर। समग्र शिक्षा, माध्यमिक के अंतर्गत पीएमश्री राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रांगण में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उक्त प्रदर्शनी से पूर्व समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर समस्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का अयोजन कराया गया तथा सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को चयनित कर जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग कराया गया। उक्त प्रदर्शनी में 100 से अधिक विद्यालयों के 250 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदर्शनी में छात्र-छात्राओं के द्वारा विभिन्न विषयों एवं उपविषयों पर अपने मॉडल/प्रदर्श प्रस्तुत किये गये। प्रदर्शनी में सीनियर एवं जूनियर वर्ग में प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रदर्शनी में जिविनि एवं वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक) के द्वारा प्रतिभागियों के मॉडल्स एवं प्रदर्शों का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। प्रदर्शनी में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान मनीष कुमार कक्षा-12, पं0 दीन दयाल उपा0 राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज, बहुआ, द्वितीय स्थान शैलेन्द्र कुमार, कक्षा-11 ग्राम्य दर्शन इण्टर कॉलेज, कलयाणपुर कचरौली, तृतीय स्थान अर्श खान, कक्षा-12, राजकीय इण्टर कॉलेज, फतेहपुर द्वारा प्राप्त किया गया तथा जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सौरभ सिंह, कक्षा-9. सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, फतेहपुर द्वितीय स्थान शोभित यादव, कक्षा-9, राजकीय हाईस्कूल, बिजौली तथा तृतीय स्थान आदित्य, कक्षा-9, राजकीय इण्टर कॉलेज, फतेहपुर द्वारा प्राप्त किया गया। वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि विज्ञान जीवन को सहज बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है किन्तु हमें विज्ञान का सकारात्मक प्रयोग सीखना होगा और उसे समाज के लिए कल्याणकारी बनाना होगा तभी विज्ञान का प्रयोग मानवीय जीवन में सार्थक सिद्ध होगा। जिविनि एवं अन्य अनुवीक्षण समिति के सदस्यों के द्वारा समस्त प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

सदस्य, उप्र राज्य महिला आयोग ने कानपुर देहात के सर्किट हाउस में की महिला जनसुनवाई

कानपुर देहात। पीड़ित महिलाओं के प्रति दिखाए संजीदगी यह बात आज उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता द्वारा सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों से कही गयी। महिला संबंधी अपराध पर अपराधियो पर सख्त कार्यवाही की जाए। जन सुनवाई के दौरान महिला जनसुनवाई में 09 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें 01 शिकायत सदस्या महोदया द्वारा काउंसिलिंग कर तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया गया शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। राज्य महिला आयोग द्वारा भेजे गए पत्रो का समय सीमा में निस्तारण करने का निर्देश दिया साथ ही महिला संबंधी अपराध, दहेज हत्या, बलात्कार, छेड़खानी ए हत्या, दहेज उत्पीड़न आदि की समीक्षा कर जल्द आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम के पश्चात् सदस्य महोदया द्वारा जिला कारागार/ महिला बन्दी गृह का निरीक्षण किया जहाँ महिला बंदियों द्वारा बनाये गए उत्पादों को देख उनकी सराहना की साथ ही महिला बन्दी गृह में निरीक्षण दौरान महिला बन्दियों को फल तथा महिला बन्दियों के बच्चों को उपहार वितरित किये साथ ही महिला बन्दी गृह में रसोई घर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण दौरान रसोई घर की साफसफाई ठीक पायी गयी। जिला महिला चिकित्सालय व वन स्टाप सेंटर कानपुर देहात का भी निरीक्षण किया गया। उक्त जनसुनवाई कार्यक्रम मे तनु उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी (अकबरपुर), रेनू यादव जिला प्रोबेशन अधिकारी, सूचना अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष तथा निधि सचान, सेंटर मैनेजर, वन स्टॉप सेन्टर, संरक्षण अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मत्स्याखेट पट्टों की शुरुआत होते ही मत्स्य समिति के संचालकों व विभाग मे विवाद शुरु

हमीरपुर। नदी की जलधारा में मत्स्याखेट पट्टा को लेकर समिति के संचालकों व विभाग में बिवाद शुरु हो गया है। समिति के संचालकों का आरोप है कि विभाग मत्स्य आखेट पट्टों में शासनादेश को दर किनार कर अपनी मनमर्जी से पट्टा करने का कार्यवाही शुरु कर दी है,मामले की जांच डीएम ने एसडीएम सदर को दी है। चालू वित्तीय वर्ष में मत्स्य आखेट के पट्टों की कार्यवाही शुरु होने के पहले सहकारी समिति के संचालक व बिभाग आमने सामने हो गया है,मेरापुर समिति के अध्यक्ष हरिहर निषाद ने डीएम को बताया कि मत्स्य विभाग ने जलधारा के खंडो का निर्माण अपनी मनमर्जी से किया है। एडीएफ ने जो गलतिया की थी वही त्रुटियां बर्तमान एडीएफकर रहे है। जिससे शासन के राजस्व का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। मेरापुर सहकारी समिति का केवल चार लाख 74 हजार 860 रुपये का नुकसान हो रहा है। मनकी कला समिति का राजस्व आकलन 29,920 रुपये बढने के स्थान पर घटाया गया है। इसी गांव की दूसरी समिति का राजस्व करीब एक लाख रुपये बढाना चाहिये मगर कम कर दिया है। विलौटा समिति का सात लाख 66 हजार 356 रुपये कम कर दिया है जो घोर अनियमितता में आता है। भौली समिति का एक लाख बीस हजार 912 रुपये का राजस्व आकलन बढाने के स्थान पर घटा दिया है। चंदूपुर समिति के 69,858 रुपये बढाने के बदले कम कर दिया है। मेरापुर समिति का राजस्व चार लाख 74 हजार 860 रुपये ज्यादा बढा दिया गया है जबकि कम करना चाहिये। पत्यौरा समिति का दो लाख 10 हजार 670 रुपये बढाना चाहिये। सुरौलीबुजुर्ग का चार लाख 30 हजार 464 रुपये बढाना चाहिये जबकि कम कर दिया है। बरुवा नयी समिति का एक लाख 92 हजार 500 रुपये कम कर दिया है जबकि इतनी धनराशि और बढाना चाहिये।

मछली का आखेट करते लोग

सभी मत्सय पट्टे किये जा रहे है नियमानुसारः एडी झांसी

हमीरपुर। प्रभारी अपर निदेशक (मत्स्य) एडीएफ रमाकांत दोहरे का कहना है कि सारे पट्टे नियमानुसार किये जा रहे है मगर शिकायत कर्ता को केवल भ्रम है फिर भी जांच की जा रही है। मत्स्य आखेट के पट्टे काफी जगह बिभाजित हो गये है इसलिये लोगो को भ्रम हो रहा है। उप निदेशक मत्स्य झांसी ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी हुई है।

जल संरक्षण के प्रयासों के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूजल की घटती गुणवत्ता और मात्रा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को जल संसाधन के संरक्षण में सामूहिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने भारत के जल संसाधनों की गंभीर स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि जल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने आगाह किया कि संरक्षण के प्रयासों के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता।

नई दिल्ली में बांदा की जिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ में जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल।

राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करते हुए अपने संबोधन में कहा, भूजल तेजी से कम हो रहा है और प्रदूषण स्थिति को बदतर बना रहा है। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं को बनाए रखने में पानी की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि स्वच्छ पानी तक पहुंच सिर्फ एक आवश्यकता नहीं है बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और वंचित समुदायों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। मुर्मू ने पानी की कमी के बारे में जागरूकता और वास्तविक कदम के बीच अंतर की ओर भी इशारा किया। उन्होंने जल संचयन और संरक्षण कार्यक्रमों सहित सरकार की विभिन्न पहल की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक स्तर पर और अधिक काम करने की जरूरत है।

मुर्मू ने भारत में जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वज पानी की कमी का प्रबंधन करने के लिए गांवों और मंदिरों के पास जलाशय और तालाब बनवाते थे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि इस सदियों पुराने ज्ञान को भुला दिया जा रहा है तथा इनमें से कई जल निकायों पर अब निजी स्वार्थवश अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे सूखे की स्थिति में पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है और अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की उनके प्रयासों के लिए सराहना की और आग्रह किया कि उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यापक रूप से साझा किया जाए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित पुरस्कारों में नौ श्रेणियों में प्रयासों को मान्यता दी गई, जिसमें ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे तथा गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए गए थे।

सीबीआई ने शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए कर्नाटक सरकार के सहमति वापस लेने पर न्यायालय का रुख किया

नई दिल्ली। सीबीआई ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तेईस नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देने के संबंध में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 2019 के कदम को कानून के अनुसार नहीं माना और परिणामस्वरूप मंजूरी वापस लेने का फैसला किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिका को गैर-विचारणीय करार दिया, जिसमें कांग्रेस सरकार के सहमति वापस लेने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

नड्डा ने कुमारस्वामी से योगीश्वर को चन्नापटना सीट से जद(एस) का टिकट देने को कहा

बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा प्रमुख जे. पी. नड्डा ने उन्हें कर्नाटक की चन्नापटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जनता दल (एस) के टिकट पर भाजपा नेता सी. पी. योगीश्वर को मैदान में उतारने की सलाह दी है। कुमारस्वामी ने कहा, तीन दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन किया और कहा कि वह उनसे (योगीश्वर से) भाजपा से इस्तीफा देने और जनता दल(एस) में शामिल होने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें (योगीश्वर को) जनता दल (एस) के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाता है तो वह मंजूरी दे देंगे। (भाजपा के) राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके अलावा और क्या कह सकते हैं?

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, उन्होंने नड्डा से कहा कि गठबंधन महत्वपूर्ण है, सीट नहीं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि राजग जीते। उन्होंने कहा कि वह झुकने के लिए तैयार हैं। कुमारस्वामी के अनुसार, नड्डा ने कहा कि चन्नापटना सीट से जनता दल(एस) का उम्मीदवार होना चाहिए। कुमारस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, मैं ऐसे नेताओं के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, आप सभी को यह समझना चाहिए। क्या मुझे भाजपा के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेने चाहिए, जिसने हमें (जद-एस) केवल दो (लोकसभा) सीटें जीतने के बाद भी सम्मान दिया है?

कुमारस्वामी ने कहा कि उनका सम्मान करने वालों के अलावा किसी और के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। लोगों से चन्नापटना के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार पर आम सहमति बनने के लिए अगले तीन दिन तक इंतजार करने को कहा।

राज्य में बल्लारी के संदूर और हावेरी जिले के शिग्गांव के साथ चन्नापटना में उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। भाजपा ने संदूर क्षेत्र से बंगारू हनुमंथु और शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई को मैदान में उतारने की घोषणा की है। हालांकि, पार्टी ने चन्नापटना सीट पर उम्मीदवार का फैसला अपने सहयोगी जनता दल (एस) पर छोड़ दिया है क्योंकि यह सीट जनता दल (एस) का गढ़ मानी जाती है और कुमारस्वामी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से योगीश्वर को हराकर जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को मैदान में उतारना चाहते है, लेकिन चन्नापटना के मजबूत नेता योगीश्वर के कदम ने कुमारस्वामी परिवार को परेशान कर दिया है। योगीश्वर ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है।

वायनाड के लिए प्रियंका से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता: राहुल

भाषा। नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा के वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले मंगलवार को कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी वाद्रा बुधवार (23 अक्टूबर) को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी और इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वह वायनाड की जरूरतों की एक धुर समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज साबित होंगी। उन्होंने कहा, कल, 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़ें, जब वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रेम से वायनाड का प्रतिनिधित्व होता रहे।

वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थीं। उसके बाद से वह पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद, जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी तथा यह भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीन सदस्य - सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे। वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी।

मुस्लिम पुरुष अपना एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं: उच्च न्यायालय

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति हैं। अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी की उस याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें उनके विवाह को पंजीकृत करने का प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर को ठाणे नगर निगम के उप विवाह पंजीकरण कार्यालय को पिछले साल फरवरी में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर उस आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिसमें उसने अल्जीरिया की एक महिला के साथ अपनी तीसरी शादी को पंजीकृत किए जाने का अनुरोध किया है।

दंपति ने अपनी याचिका में प्राधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था तथा दावा किया था कि उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यह पुरुष याचिकाकर्ता की तीसरी शादी है। प्राधिकारियों ने इस आधार पर विवाह का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत विवाह की परिभाषा में केवल एक ही विवाह को शामिल किया गया है, एक से अधिक विवाह को नहीं। हालांकि, पीठ ने प्राधिकरण के इस इनकार को पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित करार दिया और कहा कि अधिनियम में उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो किसी मुस्लिम व्यक्ति को तीसरी शादी पंजीकृत कराने से रोकता हो।

अदालत ने कहा, मुसलमानों के पर्सनल लॉ के तहत उन्हें एक समय में चार विवाह करने का अधिकार है। हम प्राधिकारियों की इस दलील को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल एक विवाह पंजीकृत किया जा सकता है, यहां तक कि मुस्लिम पुरुष के मामले में भी। पीठ ने कहा कि यदि वह प्राधिकारियों की दलील को स्वीकार कर भी ले तो इसका अर्थ यह होगा कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को नकारता है औराया उन्हें विस्थापित कर देता है।

अदालत ने कहा, इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया है। उसने कहा कि अजीब बात यह है कि इन्हीं प्राधिकारियों ने पुरुष याचिकाकर्ता के दूसरे विवाह को पंजीकृत किया था। प्राधिकरण ने यह भी दावा किया था कि याचिकाकर्ता दंपति ने कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए थे। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि एक बार ए दस्तावेज जमा हो जाने के बाद ठाणे नगर निकाय के संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और 10 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण को मंजूरी देने या इससे इनकार करने का तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे। पीठ ने निर्देश दिया कि तब तक महिला याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। महिला के पासपोर्ट की अवधि इस साल मई में समाप्त हो गई थी।

संजौली मस्जिद ध्वस्तीकरण के काम की गति धीमी : देवभूमि संघर्ष समिति

शिमला। नगर निगम आयुक्त की अदालत के आदेश पर संजौली मस्जिद समिति द्वारा मस्जिद की तीन मंजिलों के ध्वस्तीकारण का काम शुरू करने के एक दिन बाद मंगलवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया कि काम की गति धीमी है जो चिंता का विषय है। अवैध संरचना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही देवभूमि संघर्ष समिति (डीएसएस) के सह-संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि सोमवार को एक दिन के काम में केवल चार चादरें हटाई गईं। उन्होंने कहा, जिस गति से ध्वस्तीकारण का काम जारी है वह चिंता का विषय है। अगर अवैध संरचना को गिराने के लिए मस्जिद समिति के पास धन नहीं है तो वह सनातनियों को बुला सकती है और हम एक रुपया भी नहीं लेंगे। हम अपने घरों से अपना खाना भी लाएंगे और मलबा भी वहां नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मस्जिद समिति द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकारण कार्य को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता और सनातनी लोगों को उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता राज्य की कांग्रेस सरकार की भूमिका भी देख रही है। वक्फ बोर्ड की हरी झंडी के बाद सोमवार को ध्वस्तीकारण शुरू हुआ। नगर निगम आयुक्त की अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश के बाद ध्वस्तीकारण का काम शुरू हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष को दो माह के भीतर अपने खर्च पर पांच मंजिला ढांचे की तीन मंजिलों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच छत को हटाने के साथ ध्वस्तीकारण शुरू हुआ। मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा से कहा, हमने छत हटाने का ठेका दिया है जो अक्टूबर में किया जाएगा और न्यायालय द्वारा दिए गए समय में ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा या हम अधिक समय मांगेंगे क्योंकि धन की कमी एक मुद्दा है। लतीफ ने कहा, धन मुख्य मुद्दा है क्योंकि न तो जनता और न ही सरकार संरचना को ध्वस्त करने के लिए राशि देगी और मस्जिद समिति को अपने सीमित संसाधनों से खर्च वहन करना होगा। लतीफ उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने 12 सितंबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ज्ञापन में मस्जिद की अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने की पेशकश की गई थी। उससे एक दिन पहले, मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान 10 लोग घायल हो गए थे। विरोध प्रदर्शन का आह्वान देवभूमि संघर्ष समिति ने किया। डीएसएस संयोजक भारत भूषण ने कहा कि अगर मस्जिद समिति के पास धन की कमी है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर वे चाहें तो हम मुस्लिम समुदाय का भी सहयोग करने को तैयार हैं। भूषण ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें नगर निगम आयुक्त की अदालत को शिमला में संजौली मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के 15 साल पुराने मामले में आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला 2010 का है और पांच अक्टूबर को अपनी 46वीं सुनवाई में नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वक्फ बोर्ड तथा संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे दो माह के भीतर पांच मंजिला विवादित ढांचे की तीन मंजिलों को अपने खर्च पर गिराएं, लेकिन मामले में अंतिम फैसला अभी लिया जाना है। हालांकि, ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन (एएचएमओ) ने कहा था कि वे इस आदेश को अपीली प्राधिकरण की अदालत में चुनौती देंगे और मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाएंगे इससे पहले, एएचएमओ के राज्य प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने आवेदन दिया है, उनके पास ऐसा कोई भी आवेदन देने का अधिकार नहीं है और नगर निगम आयुक्त की अदालत का आदेश तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि भूमि वक्फ बोर्ड की है, मस्जिद 125 साल पुरानी है और मंजिलें अवैध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्शों की मंजूरी का मामला अधिकारियों के पास लंबित है लेकिन नगर निगम अदालत ने मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, मस्जिद 125 साल पुरानी है और इसकी मंजिलें अवैध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्शों की मंजूरी अधिकारियों के पास लंबित है, इसके बावजूद नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मंजिलों को गिराने का आदेश दिया।

नीलेश राणे शिवसेना में शामिल होंगे, कुदाल विस सीट से लड़ेंगे चुनाव

भाषा। मुंबई

भाजपा के सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने मंगलवार को कहा कि वह एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में शामिल होंगे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुदाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में हुए सीट बंटवारे समझौते के तहत कुदाल सीट शिवसेना के खाते में जाएगी और यही वजह है कि नीलेश भाजपा से शिवसेना में शामिल होंगे। शिवसेना (यूबीटी) के नेता वैभव नायक कुदाल से मौजूदा विधायक हैं और राणे के पुराने प्रतिद्वंद्वी है। कुदाल सीट रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका प्रतिनिधित्व नारायण राणे कर रहे हैं। कुदाल से सटी कंकावली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व फिलहाल नीलेश राणे के छोटे भाई और भाजपा नेता नीतेश राणे कर रहे हैं। नीलेश राणे पहले कांग्रेस में थे और 2009 से 2014 तक वह रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से लोकसभा सदस्य थे। वह 2014 में भाजपा में शामिल हुए, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

झारखंड में बनेगी राजग सरकार, हार की ओर बढ़ रहा विपक्षी गठबंधन: चिराग

पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को भरोसा जताया कि झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया हरियाणा के बाद अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास के प्रमुख चिराग ने यह भी कहा कि वह झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनकी पार्टी को एक सीट की पेशकश किए जाने से संतुष्ट हैं। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि इस सीट समझौते से उन्हें अपमानित महसूस होना पड़ा है।

पासवान ने संवाददाताओं से कहा, बहुत से लोग हैं, जो मेरे और प्रधानमंत्री के बीच दरार डालना चाहते हैं। वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं यह बताना देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी न केवल खुश है बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट है कि भाजपा ने झारखंड में भी हमें उचित सम्मान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 अक्टूबर को उनकी पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस दौरान वह खुद झारखंड का दौरा करेंगे। पासवान ने कहा, अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के अलावा पार्टी अपने सहयोगियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए रणनीति तैयार करेगी।

झारखंड की 81 सदर्स्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा 68 सीट पर और उसके सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनइटेड दो और लोजपा एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। पासवान ने कहा, हमें विश्वास है कि राजग झारखंड में मजबूत सरकार बनाएगी और कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन हरियाणा के बाद अपनी अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है।

कोर्ट के निर्देश पर, फैजान ने भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे को 21 बार सलामी दी

भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोपी व्यक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को यहां एक पुलिस थाने पहुंचा और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी। फैजान नाम के व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निर्देश दिया था कि वह यहां स्थित मिसरोद पुलिस थाने में महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी दे और भारत माता की जय का नारा लगाए। मिसरोद पुलिस थाने के प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने पीटीआई-भाषा को बताया, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, फैजान आज महीने के चौथे मंगलवार को पुलिस थाने आया और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी। यह मीडिया की मौजूदगी में हुआ और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।

उन्होंने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और यह गतिविधि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी। फैजान ने पीटीआई-भाषा से कहा कि रील बनाना और इस तरह के (पाकिस्तान समर्थक) नारे लगाना एक बड़ी गलती थी और उसे इसका पछतावा है। उसने कहा, किसी को भी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कि वह अपने दोस्तों से इस तरह की रील न बनाने का अनुरोध करता है।

फैजान उर्फ फैजल को इस साल मई में मिसरोद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी के तहत एक मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह एक वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी के पालीवाल ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जो उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जहां उसका जन्म हुआ और वह रह रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा था, वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के समान था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था।

पेज 1 का शेष

हम विश्वास..

जैसा कि मई 2020 से पहले होता था। उस साल जून में गलवान में हुई झड़प के बाद, दोनों पक्षों ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था जिससे तनाव बढ़ गया था। एक बार गश्त शुरू होने के बाद, दोनों पक्ष अंततः अपने सैनिकों को एलएसी से हटाकर अपने-अपने क्षेत्रों में शांति के स्थानों पर वापस ले जाएंगे। इस कदम के बाद, क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। रक्षा थिंक-टैंक यूएसआई द्वारा आयोजित एक व्याख्यान देने के बाद एक बातचीत सत्र में बोलते हुए, सेना प्रमुख ने कहा, 'जहां तक ??हमारा सवाल है, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के विघटन, तनाव कम करने और सामान्य प्रबंधन पर विचार करेंगे। और एलएसी का यह सामान्य प्रबंधन सिर्फ वहां से शुरू नहीं होगा। इसमें भी चरण हैं। उन्होंने कहा, तो, मैं यही कह रहा हूँ। अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है... और आज भी यही है। इसलिए, अभी तक, हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास कैसे बहाल होगा। यह तब बहाल होगा जब हम एक-दूसरे को देख पाएँगे, और हम एक-दूसरे को समझा पाएँगे। उन्होंने कहा कि बफर ज़ोन के संबंध में जो बनाया गया है। सेना प्रमुख ने कहा, 'और, दोनों को एक-दूसरे को आश्वस्त करना होगा।' गश्त करने से आपको इस तरह का लाभ मिलता है, और यही शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा, और, जैसे ही हम विश्वास बहाल करेंगे, अन्य चरण भी पूरे होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को घोषणा की कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया है। इसे इस सप्ताह रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक से पहले चार साल से अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। विदेश सचिव ने कहा, 'पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक और सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं।' मिसरी ने कहा, इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों का समाधान हुआ है। बाद में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक सीमा पर गतिरोध शुरू होने से पहले की तरह गश्त फिर से शुरू कर सकेंगे। सेना प्रमुख द्विवेदी ने यह भी कहा कि भारत 2020 की स्थिति में लौटने के बाद सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि बनाए गए बफर जोन पर अतिक्रमण न हो। दोनों देशों के सैनिक पहले चार स्थानों से पीछे हटे थे, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है, जहां जून 2020 में एक घातक झड़प में 20 भारतीय सैनिक और कई चीनी सैनिक मारे गए थे। नया समझौता देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त की सुविधा प्रदान करेगा। जिन चार स्थानों से सैनिकों की वापसी हुई उनमें गलवान घाटी, पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा शामिल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बीजिंग से रिपोर्ट की, चीन ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है।

फर्जी...

ने तीन वाहकों - एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो से संबंधित 30 उड़ानों को भेजे गए बम की धमकी के संदेशों को 'झूठा या अस्पष्ट' घोषित किया। इस खतरे को 'अस्पष्ट' माना गया क्योंकि यह पाया गया कि एक एक्स हैंडल ने इन तीनों वाहकों की 10 उड़ानों के लिए रात 10.46 बजे से 11.42 बजे के बीच इन 'बम ऑनबोर्ड' संदेशों को पोस्ट किया था। सूत्रों ने बताया कि बीटीएसी द्वारा अपनाए गए प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है और नए 'लाल झंडों' के आधार पर अब एक अच्छा मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और संबंधित एयरलाइन सुरक्षा को यात्रियों, उनके सामान और विमान की तलाशी के लिए 'केंद्रित' सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि उड़ान की तैयारी के दौरान कुछ भी संयोग पर न छोड़ा जाए। जब यह स्थापित हो जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए बम या अपहरण की धमकी संदेश 'बिना किसी तर्क के' प्रकाशित किए गए थे, तो बीटीएसी इसे 'अविशिष्ट या धोखा' श्रेणी में डाल देगा, ताकि यात्रियों और एयरलाइन चालक दल को परेशान न किया जाए और उनका कीमती समय बर्बाद न हो, उन्होंने परिचालन कारणों से विशिष्ट विवरण के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा। सूत्रों ने कहा कि अभी भी कुछ मामले होंगे जहां एक संदेश या कॉल को 'विशिष्ट' घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा सामूहिक रूप से नहीं किया जाएगा। विमानन सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये नए उपाय इन फर्जी सोशल मीडिया या फोन कॉल संदेशों से उत्पन्न 'कुछ' परेशानी को कम करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि इनमें से कुछ खतरे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन से ट्रिगर होते हैं और ऐसे कई हैंडल, खास तौर पर एक्स पर, विभिन्न एयरलाइनों को धमकियाँ पोस्ट करने से कुछ घंटे या दिन पहले ही बनाए गए थे। हाल ही में सऊदी अरब में जेद्दा, रियाद और मदीना जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए उड़ानों को निशाना बनाया गया, इस्तांबुल और दोहा क्रमशः तुर्की और कतर की राजधानी हैं। इससे शेड्यूल में बाधा उत्पन्न हुई, एयरलाइनों को नुकसान हुआ और पीक फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रियों में दहशत फैल गई। यह पहली बार है कि फर्जी कॉल करने वालों ने मध्य पूर्व के देशों में जाने वाली उड़ानों को निशाना बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि एयरलाइनों को बम की धमकी देने वाले फर्जी कॉल करना एक संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा।

वक्फ बिल..

विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि विधेयक में उनका क्या हित है। भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि बनर्जी बोलने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें अध्यक्ष द्वारा कुछ हस्तक्षेप करने की भी अनुमति दी गई थी। जब उन्होंने बोलने के लिए दूसरी बारी मांगी, तो पाल ने मना कर दिया और उनके और गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिन्होंने बार-बार व्यवधान पर आपत्ति जताई। वक्फ (संशोधन) विधेयक को मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने वाले विधेयक ने वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना भी है। अपने उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने के लिए है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विधेयक में बोहरा और अगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।

पराली..

सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया है। अब तक 127 मामले आ चुके हैं। करनाल में 9 लोग गिरफ्तार किए गए और उन्हें जमानत भी मिल गई। 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

भारी...

और इसका शिकार होने से बच सकें। गुरुग्राम में यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करके साइबर सिटी में यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुग्राम में यातायात पुलिस द्वारा नियमों के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में यातायात की समस्या को रोकने के लिए हम समय-समय पर विशेष अभियान चलाते रहे हैं। हमने यातायात कर्मियों को सड़कों पर मौजूद रहने और यातायात उल्लंघन पर अंकुश लगाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

कानूनों में स्पष्टता की कमी से न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत होती है: अमित शाह

भाषा। गांधीनगर

जन्म दिन पर गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनों में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कानून बनाने के लिए जिम्मेदार लोग इसमें अस्पष्टता छोड़ देते हैं। केंद्रीय मंत्री विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए विधान तैयार करने के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला के तहत गुजरात विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, उससे विवाद पैदा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करेगी, जब आप कानून का मसौदा तैयार करने में कोई अस्पष्टता छोड़ देंगे। कानून में जितनी अधिक स्पष्टता होगी, अदालतों का हस्तक्षेप उतना ही कम होगा। सदन में विधायकों, सांसदों के साथ-साथ पूर्व विधायकों और अध्यक्षों की भी उपस्थिति थी।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कदम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जब अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह संविधान का एक अस्थाई प्रावधान है जिसे संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जाने वाले संशोधन के माध्यम से हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अब, अगर यह लिखा होता कि यह अस्थाई के बजाय एक संवैधानिक प्रावधान है, तो हमें मतदान के दौरान साधारण बहुमत के बजाय दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती। इस प्रकार, अधिक स्पष्टता से न्यायिक हस्तक्षेप कम होता है। अगस्त 2019 में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इसे अस्थाई प्रावधान बताते हुए निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। शाह ने दावा किया कि कानूनों का खराब मसौदा ही मुख्य कारण है कि आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है।

उन्होंने कहा, हमारा संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बारे में बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि सरकार नीतियां बनाएगी और विधायिका उन नीतियों के अनुसार कानून पारित करेगी। न्यायपालिका कानूनों को परिभाषित करेगी और कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी। लेकिन कानूनों को सही तरीके से तैयार नहीं किए जाने के कारण आज इन तीनों के बीच की रेखा धुंधली हो गई हैं। शाह ने कहा कि कानून बनाने की कला धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्एक विधान सभा को अपने कर्मचारियों के लिए मसौदा तैयार करने के कौशल को बढ़ाने को लेकर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को यह मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि कानून में क्या शामिल किया जाए और कौन से प्रावधान उस कानून के नियमों का हिस्सा बनने चाहिए। शाह ने कहा कि डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार और संपादित भारत का संविधान विधान तैयार करने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा, उस समय संविधान सभा में 72 बैरिस्टर शामिल थे...उनका लगभग 14 प्रतिशत समय मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने में व्यतीत हुआ। ऐसी गहन चर्चाओं के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। और आज, कुछ गैर सरकारी संगठन हमें मौलिक अधिकारों के मुद्दे पर सलाह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसी भी कानून का मसौदा तैयार करते समय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और आम आदमी को भी इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। उदाहरण देते हुए, शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। शाह ने कहा, अगले तीन-चार साल में जब ए कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई तक, तीन साल के भीतर न्याय मिलेगा। आने वाले दिनों में यह सुधार दुनिया का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा।

चांदी एक लाख के पार, सोना 350 रुपए की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड पर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 350 रुपए की तेजी के साथ 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 1,500 रुपए के उछाल के साथ एक लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव को पार कर गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। चांदी की कीमतों में लगातार पांचवे दिन बढ़त जारी रही और यह 1,500 रुपए के उछाल के साथ 1.01 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। शुक्रवार को चांदी की कीमत 99,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थीं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा कि चांदी में जारी तेजी का मुख्य कारण औद्योगिक मांग है। इसके अलावा आभूषण और चांदी के बर्तन खंड के कारण भी तेजी आई है। इसके अलावा, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 350 रुपए चढ़कर 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सर्राफा कारोबारियों ने सोने की कीमतों में उछाल की वजह त्योहारी और शादी-विवाह के मौसम में बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की खरीदारी में आई तेजी को बताया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के वायदा कारोबार में दिसंबर डिलिवरी वाला सोने का अनुबंध 208 रुपए बढ़कर 78,247 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले के एक मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।जिले की आशापुरी कॉलोनी में हुए इस हादसे में मारे गए लोगों के घर के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और परिवार के रिश्तेदारों को सांत्वना दी।सिकंदराबाद थाना क्षेत्र स्थित आशापुरी कॉलोनी में सोमवार रात एक मकान में रखे आक्सीजन सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया।विस्फोट इतना तेज था कि मकान की छत नीचे गिर गई।अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में रियाजुद्दीन (50), उसकी पत्नी रुखसाना (45), बेटे आस मोहम्मद (26), सलमान (16), बेटी तमन्ना (24) और नातिन हिफ्जा (तीन) की मौत हो गई।जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इस घटना में परिवार के दो-तीन अन्य लोग घायल हुए है जबकि घर में रहने वाले लगभग 10 अन्य लोग सुरक्षित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि रुखसाना नाम की महिला की तबीयत ठीक नही थी और उसे हाल ही में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि बीमार महिला के घर लौटने पर उसके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया था, जिसमें विस्फोट हो गया। मृतक रियाजुद्दीन के दामाद रिजवान ने बताया, उसने (तमन्ना ने) मुझे दो दिन बाद घर वापस ले जाने के लिए कहा था। मैने सोमवार शाम करीब पांच बजे उससे बात की थी। उसके बाद कोई बातचीत नही हुई। हादसे का शिकार हुए परिवार के पड़ोसियों ने पीटीआई-वीडियो से विस्फोट के बाद के हालात बयां किए।पड़ोस में रहने वाले आसिफ ने बताया, मैने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जब मै बाहर भागा तो देखा कि अफ्रा-तफरी मची हुई है। लोग मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे से चंद लम्हे पहले नमाज अदा कर लौटे एक अन्य पड़ोसी ने भयावह मंजर को याद करते हुए कहा, विस्फोट के कारण अचानक लाल चमक सी बनी, जिसकी थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। हमने अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन धूल बहुत ज्यादा फैली थी। हमें अपने मोबाइल फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा।

असम में पुलिस मुठभेड़ का मामला बहुत गंभीर , रिपोर्ट दाखिल करें : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम पुलिस द्वारा मई 2021 से अगस्त 2022 तक की गई 171 मुठभेड़ों से जुड़े मुद्दे को बहुत गंभीर करार देते हुए इन मामलों की जांच सहित विस्तृत जानकारी तलब की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ जनवरी 2023 में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने असम पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों पर चिंता जताते हुए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में असम सरकार द्वारा उसके समक्ष दायर हलफनामे का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक मुठभेड़ की 171 घटनाएं हुईं जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हुई और 145 घायल हुए।शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा, यह बेहद गंभीर मुद्दा है। 171 घटनाएं चिंताजनक है। असम सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने जब दलील दी कि उच्च न्यायालय जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नही था और इसे अपरिपक्व बताया, तो पीठ ने टिप्पणी की, इस तरह की याचिकाओं को अपरिपक्व बताकर खारिज नही किया जा सकता। याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि असम में बड़ी संख्या में मुठभेड़ हुई है और राज्य पुलिस मुठभेड़ मामलों की जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में 2014 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नही कर रही है।उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और असम मानवाधिकार आयोग इन मामलों में अपने कर्तव्यों का पालन नही कर रहा है।

उप्र मदरसा कानून को रद्द करने के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें मदरसों के संबंध में 2004 के उत्तर प्रदेश कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने लगभग दो दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के अलावा आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनी और इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गुजरात पुलिस ने फर्जी अदालत का भंडाफोड़ किया

न्यायाधीश बनकर फैसला सुना रहा था आरोपी

अहमदाबाद।(भाषा) गुजरात में पुलिस ने एक फर्जी अदालत का भंडाफोड़ किया है जिसमें एक व्यक्ति खुद को न्यायाधीश बताता था और वह गांधीनगर इलाके में खासतौर से भूमि सौदों में 2019 से फैसले पारित कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उसकी अदालत वैध है। पुलिस ने बताया कि इस साजिश के कर्ताधर्ता क्रिश्चियन ने भूमि सौदों में फंसे लोगों को अपने झांसे में लिया और भारी-भरकम रकम के बदले में उनके पक्ष में फैसले सुनाए। उसकी फर्जी अदालत बिल्कुल असली अदालत कक्ष की तरह लगती थी और वह सालों तक इसमें फैसले सुनाता रहा जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। इस फर्जी अदालत की शुरुआत 2019 में हुई। शुरुआती जांच से पता चलता है कि क्रिश्चियन ने भूमि विवादों में फंसे लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें मोटी फीस के बदले में त्वरित मुकदमा सुलझाने का वादा किया। न्यायाधीश की भूमिका निभाकर उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए न्याय की प्रक्रिया में हेरफेर करके कमजोर लोगों का शोषण किया। इस व्यापक साजिश में क्रिश्चियन के साथी भी शामिल रहे जो खुद को अदालत कर्मी बताते थे ताकि अपने झांसे में आए लोगों को ठगने के लिए यह विश्वास दिला सकें कि यह अदालत असली है। पुलिस ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि क्रिश्चियन ने 2019 में भी ऐसी ही चालबाजी से एक व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया। यह मामला जिलाधिकारी के तहत एक सरकारी जमीन से जुड़ा था जबकि उसके झांसे में आए व्यक्ति ने इस पर दावा जताया था और वह पालदी इलाके में स्थित जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ना चाहता था। इसके बाद क्रिश्चियन ने उस व्यक्ति को बताया कि उसे सरकार द्वारा आधिकारिक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, इसके बाद उसने अपनी अदालत में मुकदमे की फर्जी सुनवाई शुरू की और उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कलेक्टर को राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम जोड़ने का निर्देश दिया। इस आदेश को तामील कराने के लिए क्रिश्चियन ने शहर की दीवानी अदालत में एक अन्य वकील के जरिए एक अपील दार की और अपने द्वारा पारित फर्जी आदेश संलग्न किया। अदालत के पंजीयक हार्दिक देसाई ने हाल में पाया कि कि क्रिश्चियन न तो कोई मध्यस्थ है और न ही अधिकरण का आदेश असली है। देसाई की शिकायत पर यहां करांज पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 170 (किसी सरकारी सेवक के रूप में किसी भी पद पर रहने का ढोंग करना) और 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी रना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। विज्ञप्ति के अनुसार, क्रिश्चियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ शहर के मणिनगर पुलिस थाने में 2015 में भी धोखाधड़ी की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

अलीगढ़ मुस्लिम विवि को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने वाला निजी विधेयक पेश करने की तैयारी में सपा सांसद

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन संसद के आगामी सत्र में उच्च सदन में एक निजी विधेयक पेश करने की तैयारी में है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने का प्रावधान किया गया है। सुमन का कहना है कि वह शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक चरित्र की बहाली के लिए) विधेयक, 2024 पेश करेंगे। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार, जब तक केंद्र सरकार ने 1965 के संशोधन अधिनियम द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में छेड़छाड़ नहीं की थी, तब तक किसी को कोई संदेह नहीं था कि एएमयू मुख्य रूप से मुसलमानों के लाभ के लिए देश के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें आगे कहा गया है, इसके विपरीत, केंद्र सरकारों ने अपनी प्रतिबद्धताओं और वादों के बावजूद, विश्वविद्यालय की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं, इसके अल्पसंख्यक चरित्र, इसकी स्वायत्तता और इसकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को नष्ट कर दिया। 1979 में विभिन्न राष्ट्रीय दलों के चुनावी वादों के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने 1981 में संसद में एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को बहाल किया।

रितेश और जेनेलिया बने ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली। पोकेमॉन गो बॉलीवुड के पसंदीदा कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को भारत के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है। अपने आकर्षणए गर्मजोशी और भारतीय संस्कृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले यह कपल देश में पोकेमॉन गो के बढ़ते फैन बेस में अपनी अनूठी ऊर्जा लाने के लिए तैयार हैं।नियांटिक के सीनियर डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड स्पेशल प्रोजेक्ट यूकी कवामूरा ने भी इस साझेदारी के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। कहा हम रितेश और जेनेलिया डीश्सूजा देशमुख का पोकेमॉन गो परिवार में स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित हैं। भारतीय परिवारों के लिए उज्जवल दिवाली: लखनऊ। शॉप्सी बाय फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों को एक बार फिर अपनी बिग दिवाली सेल से खुश कर रहा हैए जो 29ए तक जारी रहेगी। यह आगामी त्यौहारी सेल ग्रैंड शॉप्सी मेलाए द बिग बिलियन डेज़ सेल और चल रहे दिवाली स्वागत सेल की सफलता के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किए गए डील्स की एक अद्भुत श्रृंखला पेश करने का वादा करती है। शॉप्सी की बिजनेस हेड प्रथ्यूषा अग्रवाल कहती हैंए राखी से लेकर दिवाली तक भारत का समृद्ध त्यौहारी कैलेंडर खरीदारी के रुझान को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है।

मंत्रिमंडल जाति जनगणना पर चर्चा करेगा, रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए: कर्नाटक के मंत्री

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसे जातिगत जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ना होगा और यदि आवश्यक्ता हुई तो कर्नाटक सरकार अन्य राज्यों की तरह इस पर चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। परमेश्वर ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति जनगणना रिपोर्ट मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखी जाएगी और इसके पक्ष-विपक्ष पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। संभवतः मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वेक्षण में करीब 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अगर रिपोर्ट लोगों के सामने नही रखी गई तो यह बेकार हो जाएगी तथा लोगों को कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। मंत्री ने कहा, अगर इसे सार्वजनिक नही किया गया तो हमारी सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जाएंगे कि हमने रिपोर्ट को दबा दिया.।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में नरमी की आशा :हरदीप पुरी

नई दिल्ली।(भाषा) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के पास पर्याप्त कच्चा तेल है और बाजार में आपूर्ति अधिक हो रही है, इससे कच्चे तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत कहा, तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर तनाव के कारण संघर्ष वाले क्षेत्रों से बचने के लिए माल ढुलाई और बीमा शुल्क बढ़ जाता है जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। पुरी ने उम्मीद जताई कि बेहतर समझ कायम होगी और कूटनीति को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव के बावजूद दुनिया में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और ब्राजील और गुयाना जैसे देशों से अधिक आपूर्ति बाजार में हो रही है। मंत्री ने कहा कि उपलब्धता को लेकर कोई चिंता नहीं है, हम समस्या से पार पाने को लेकर आश्वस्त हैं। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है और वैश्विक दरों में कोई भी वृद्धि न केवल आयात बिल को बल्कि मुद्रास्फीति को भी बढ़ाती है। उन्होंने कहा, निजी तौर पर मेरा मानना है कि तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी और नीचे आएंगी...। इस महीने की शुरुआत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 78 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई थीं। इसका कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव था। बाजार यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या इजराइल, ईरान के हमले के बाद कोई जवाबी कार्वाई करेगा। उसके बाद से तेल के दाम गिरकर 73-74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल, ईरान में तेल या परमाणु सुविधाओं को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ तेहरान या तो इजराइल पर सीधा हमला करके या फिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्ग... होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करके जवाब देने का विकल्प चुन सकता है। इससे तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल का पांचवां हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है। सभी प्रमुख तेल उत्पादकों... सऊद्दी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से तेल जलडमरूमध्य के रास्ते निर्यात किया जाता है। केवल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पास परिचालन पाइपलाइन हैं जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से उस पर असर नहीं होगा।

आरजी कर पीड़िता के पिता ने अमित शाह को लिखा पत्र, मांगी मदद

कोलकाता।(भाषा)पश्चिम बंगाल की राजधानी स्थित सरकारी आर.जी.कर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में करीब दो महीने पहले दुष्कर्म और हत्या की शिकार प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के पिता ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया। पिता ने कहा कि वह इस समय घोर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भेजे ई-मेल में कहा कि वह शाह से मार्गदर्शन और मदद चाहते हैं। पिता ने कहा, मैं अभया (काल्पनिक नाम) का पिता हूं और आपको यह पत्र इस विनम्र अनुरोध के साथ लिख रहा हूं कि आपकी सुविधा के अनुसार या आपके द्वारा सुझाए गए किसी स्थान पर मुलाकात का समय दिया जाए। हमारी बेटी के साथ घटी उस जघन्य अप्रत्याशित घटना के बाद से हम घोर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और अब असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ मुलाकात कर इस मामले से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं और आपसे मार्गदर्शन और मदद के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपसे बात करने और इस मुद्दे पर आपकी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसर के लिए वास्तव में आभारी हूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होगा। पिता ने केंद्रीय गृहमंत्री से कुछ मिनट उनके लिए निकालने के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप कब और कहां हमारे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं। फिर, हम खुद को तैयार रख सकते हैं। मैं आपके समय और इस अनुरोध पर विचार करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपकी अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं... मैं आपसे मिलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बाद में पीड़िता की मां ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जब वह व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और न्याय का अनुरोध करेंगी तो केंद्रीय गृहमंत्री से उन्हें मिलने का समय मिल जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी हमें समय देंगे। मैं उन्हें उस मानसिक पीड़ा के बारे में बताऊंगी जो हम अपनी बेटी को अबतक न्याय नहीं मिलने की वजह से महसूस कर रहे हैं। र.जी.कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला प्रशिक्षु चिकित्सक का शव नौ अगस्त को सेमिनार अर्द्धनग्न अवस्था में मिला था।

राजाधिराज श्रीकृष्ण की मनमोहक कहानी दिल्ली में अपना प्रदर्शन जारी रखेगी

लखनऊ। मुंबई में जबरदस्त सफल प्रदर्शन के बादए श्री कृष्ण पर दुनिया का पहला मेगा म्यूजिकल ष्राजाधिराज लव लाइफलीलाष नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है, जिसके शो 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक निर्धारित हैं। दूरदर्शी धनराज नथवानी द्वारा संकल्पित और जीवंत प्रस्तुति ने भारतीय रंगमंच को फिर से परिभाषित किया है जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले नाटकीय अनुभव के माध्यम से श्री कृष्ण की उदारता और अनुग्रह का अभूतपूर्व चित्रण पेश करता है।श्री कृष्ण के चमत्कार और महिमा का अनुभव करने के लिए दर्शकों को आमंत्रित करते हुए धनराज नथवानी ने कहा, ष्राजाधिराजरू लव लाइफलीलाश् का निर्माण मेरे लिए भक्ति और जुनून की यात्रा रही है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा का एक अंतहीन स्रोत हैए और इस संगीत के माध्यम से हमारा उद्देश्य उनके अवतार में निहित सुंदरताए ज्ञान और प्रेम को साझा करना है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सौर पार्क की स्थापना के लिए जीईएपीपी का यूपीडा से हुआ गठजोड़

नई दिल्ली।(भाषा) ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट (जीईएपीपी) ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 450-500 मेगावाट का सौर पार्क विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के साथ गठजोड़ किया है।जीईएपीपी ने मंगलवार को बयान में कहा कि भारत में अपनी तरह की पहली यह महत्वाकांक्षी परियोजना 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हरित ऊर्जा गलियारा स्थापित करेगी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र को सौर ऊर्जा संचालित बुनियादी ढांचे के लिए एक मॉडल में बदलने का काम करेगा।परियोजना की व्यवहार्यता का व्यापक अध्ययन करने के बाद जीईएपीपी ने एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 15-20 मीटर के निर्दिष्ट भूमि क्षेत्र पर 450 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की क्षमता की पुष्टि की। बयान के मुताबिक, लगभग 1,800 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिस्पर्धी दर पर बिजली पैदा होगी। इस सौर पार्क की स्थापना करीब 1,700 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। यह सौर पार्क निर्माण-स्वामित्व-परिचालन (बीओओ) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद से इसकी अवधि को 25 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना में एकल चरण की बोली प्रक्रिया शामिल है और बोलीदाता का चयन प्राधिकरण के साथ राजस्व हिस्सेदारी के प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यूपीडा आठ अक्टूबर को इस परियोजना के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित कर चुका है। भारत के 6,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसमें बुंदेलखंड सौर राजमार्ग परियोजना अकेले 10 गीगावाट बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है।

नई दिल्ली में छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सिंगापुर के समकक्ष एनजी इंग हेन के साथ

पायनियर
लखनऊ, बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024

भारत वृद्धि के नए अवसरों कालाभ उठाने की अच्छी स्थिति में: सीतारमण

न्यूयॉर्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक माहौल चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन भारत वृद्धि के नए अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, तो भारत को उम्मीद है कि वह वस्तुओं व सेवाओं के स्रोतों में विविधता लाने के इच्छुक कई देशों के लिए प्रमुख साझेदार बनेगा। सीतारमण ने सोमवार को कोलंबिया विवि में चुनौतीपूर्ण तथा अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच भारत की आर्थिक मजबूती व संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान में यह बात कही। भारत घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने तथा बाहरी झटकों के प्रति मजबूती विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। सीतारमण ने कहा, हालांकि पिछले दशकों में व्यापक बहुपक्षीय व्यापार के कारण वैश्विक वृद्धि हुई है लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले वर्ष रणनीतिक आर्थिक साझेदारियों द्वारा परिभाषित होंगे और भारत इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैश्विक आर्थिक वातावरण चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन भारत वृद्धि के नए अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है।

वित्त मंत्री ने कहा, अधिक विखंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जिसमें पुनर्परिभाषित गठबंधन तथा बदलते व्यापार तरीके शामिल हैं...वास्तव में भारत के लिए लाभकारी हो सकता है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, भारत को उम्मीद है कि वह वस्तुओं व सेवाओं के अपने स्रोतों में विविधता लाने की चाह रखने वाले कई देशों के लिए एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा। भारत की आर्थिक नीतियों पर इस व्याख्यान का आयोजन कोलंबिया के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में दीपक एवं नीरा राज सेंटर द्वारा किया गया था।

सीतारमण मैक्सिको की यात्रा संपन्न करने के बाद रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचीं। मैक्सिको में उन्होंने ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंडटेबल की अध्यक्षता की थी। मंत्री ने ग्वाडलजारा में टीसीएस मुख्यालय का दौरा भी किया था।

न्यूयॉर्क में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत में निवेश के अवसर पर एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही आईबीएम के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्ण के साथ उन्होंने भारत के दशकीय आर्थिक सुधारों तथा आर्थिक वृद्धि पर एक चर्चा में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क से सीतारमण वाशिंगटन डीसी जाएंगी। वहां वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी-20 वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठकों, जी-20 एफएमसीबीजी, पर्यावरण मंत्रियों एवं विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक और जी-7 - अफ्रीका मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगी।

वित्त मंत्री ने सिटीबैंक की सीईओ से मुलाकात की, भारत में बैंकिंग प्रणाली के भविष्य पर चर्चा की

न्यूयॉर्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यहां सिटीबैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जेन फ्रेसर से मुलाकात की और दशकीय सुधारों तथा भारत के भविष्य के मद्देनजर बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक खाते पर जानकारी दी, दोनों ने कृषि तथा शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा (एआई) के इस्तेमाल के साथ-साथ भारत के तेजी से बढ़ते औषधि क्षेत्र ... पर चर्चा की। फ्रेसर ने भारत के डिजिटल भुगतान परिवर्तन के लिए वित्त मंत्री की सराहना की। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए परिवेश तैयार करने के वास्ते बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु भारत द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों की सराहना की और कहा कि एमएसएमई को आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। बैठक में फ्रेसर ने कहा कि व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से व्यापार प्रक्रियाएं सुचारू होंगी। वित्त मंत्री ने वैश्विक निवेश एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले कंपनी ब्लैकरॉक के सीईओ लॉरेंस डगलस फिंक से भी मुलाकात की। दोनों ने एनआईआईएफ तथा आईएफएससी गिफ्टसिटी के जरिए वैश्विक निवेशकों के अवसरों के साथ-साथ ग्रीनटेक तथा बैटरी स्टोरेज के वित्तपोषण के अवसरों पर चर्चा की। फिंक ने बताया कि ब्लैकरॉक भारत में निजी भागीदारों के साथ काम कर रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है।

चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास किया

ताइपे। चीन ने ताइवान से सटे दक्षिणी फुजियान प्रांत के तट पर सैन्य अभ्यास किया जिसमें गोलियों और गोलाबारूद का इस्तेमाल किया गया। चीन ने इसे ताइवान के राष्ट्रपति द्वारा उसके (चीन के) संप्रभुता के दावे को खारिज करने के कारण दंड स्वरूप किया गया अभ्यास बताया है। चीन ने एक सप्ताह पहले ही ताइवान के खिलाफ व्यापक स्तर पर हवाई एवं समुद्री अभ्यास किया था। समुद्री सुरक्षा प्रशासन से जारी एक नोटिस के अनुसार, यह अभ्यास फुजियान प्रांत के पिंगटन द्वीप के निकट सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक किया गया। नोटिस में जहाजों को क्षेत्र में आने से बचने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इसमें अतिरिक्त विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। बयान के अनुसार, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन का यह सैन्य अभ्यास वार्षिक अभ्यास का हिस्सा था और वह उन पर नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की यह कार्वाई ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव को बढ़ाने वाली है और क्षेत्र में मुक्त आवागमन के संदर्भ में उसकी धमकी भरी कार्वाई के विस्तार के तरीकों में से एक है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन उसे अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर तनाव बढ़ गया है। चीन ने ताइवान के आस-पास के समुद्री और हवाई क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अब वह ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास के लिए बड़ी संख्या में युद्धक विमान और नौसेना के जहाज भेज रहा है और उसके तट रक्षक गश्त लगाते रहते हैं। पिछले सप्ताह चीन ने एक दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था, जिसका उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख क्षेत्रों की घेराबंदी करना था।

रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की खबर पर दक्षिण कोरिया की यक्रेन हथियार भेजने की चेतावनी

भाषा। सियोल

रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया द्वारा सैनिक भेजने की खबर पर दक्षिण कोरिया ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि वह भी यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति पर विचार कर सकता है। हालांकि,उत्तर कोरिया और रूस ने इन खबरों को खंडन किया है। दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया बयान रूस पर दबाव बनाने के लिए प्रतीत होता है ताकि वह इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों को शामिल नहीं करे। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को चिंता है कि रूस जटिल हथियार प्रौद्योगिकी से उत्तर कोरिया को पुरस्कृत कर सकता है जिससे दक्षिण कोरिया लक्षित उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूती मिल सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में, दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारियों ने उत्तर कोरिया द्वारा सैनिकों की कथित तैनाती की निंदा करते हुए इसे दक्षिण कोरिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बताया।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उत्तर कोरिया अपराधी समूह समूह है जो अन्यापूर्ण युद्ध में अपने युवाओं को किराए के सैनिक के तौर पर रूस को इस्तेमाल करने के लिए भेज रहा है। बयान के मुताबिक अधिकारी रूस-उत्तर कोरिया सैन्य सहयोग में हुई प्रगति के जवाब में चरणबद्ध जवाबी कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए कहा कि इन कदमों में कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य विकल्प शामिल हैं और दक्षिण कोरिया यूक्रेन को रक्षात्मक और आक्रामक हथियार भेजने पर विचार कर सकता है। यूक्रेन के साथ फरवरी 2022 में रूस का युद्ध शुरू होने के साथ उत्तर कोरिया के साथ उसका सहयोग प्रगाढ़ होता जा रहा है जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका नीत उन देशों में शामिल है जिसने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को मानवीय मदद पहुंचाई है। लेकिन सक्रिय रूप से संघर्ष में शामिल देशों को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने की अपनी नीति की वजह से सीधे तौर पर यूक्रेन को हथियार देने से बचता रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने पिछले सप्ताह पुष्टि की कि उत्तर कोरिया ने इस महीने अपने विशेष अभियान बल के 1500 सैनिकों को रूस भेजा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उनकी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि 10 हजार उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध में रूस का साथ देने के लिए तैयार हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अगस्त 2023 से अबतक 13 हजार कंटेनर, तोप, मिसाइल और अन्य पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति की है।

लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

लाहौर। पाकिस्तान के सांस्कृतिक शहर लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, क्योंकि यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 394 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने धूम कोहरे (स्मॉग) के प्रभाव को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना बनाई है। एक्यूआई हवा में विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता का माप है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 और 100 के बीच को संतोषजनक , 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 और 300 के बीच को खराब, 301 और 400 के बीच को बहुत खराब और 401 और 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। फसल के अवशेषों को जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण का संकट बढ़ गया है।

खतरनाक धूम कोहरे के कारण शहर के निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनमें खांसी, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और त्वचा संक्रमण शामिल है। पंजाब की सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,"कल लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। हमने इस मामले को सुलझाने के लिए कई पहल की हैं और अब हम शहर में कृत्रिम बारिश की योजना बना रहे हैं।

मरियम नवाज की पंजाब सरकार ने धूम कोहरा रोधी दल भी बनाया है जो इससे (धूम कोहरा से) प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। ए दल किसानों को फसल अवशेष जलाने के खतरों के बारे में शिक्षित करेंगे, सुपर सीडर के उपयोग को बढ़ावा देंगे तथा अवशेष निपटान के लिए वैकल्पिक तरीकों की जानकारी देंगे। पंजाब की पर्यावरण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा, धूम कोहरे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक प्रभाव आठ से 10 वर्षों में दिखाई देने लगेंगे। प्रांत में पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने किसानों से फसल अवशेष जलाने से बचने का आग्रह किया तथा कहा कि ऐसा करने से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है।

एअर इंडिया बम विस्फोट के संदिग्ध रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के दो आरोपियों ने अपना दोष स्वीकार किया

ओटावा। एअर इंडिया कनिष्क आतंकवादी बम विस्फोट मामले में बरी किए गए रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के दो आरोपियों ने कनाडा की एक अदालत में हत्या का दोष स्वीकार कर लिया है। टैनर फॉक्स और जोस लोपेज ने 75 वर्षीय मलिक की हत्या के मामले की सुनवाई की पूर्व संध्या पर सोमवार को ब्रिटिश कोलंबिया (बीसी) की उच्चतम न्यायालय में अपना दोष स्वीकार किया। मलिक की 14 जुलाई 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मलिक और सह-आरोपी अजायब सिंह बागरी को 1985 में हुए दो बम विस्फोटों से संबंधित सामूहिक हत्या और साजिश के आरोपों से 2005 में बरी कर दिया गया था। इन विस्फोटों में 331 लोग मारे गए थे। ग्लोबल न्यूज की खबर के अनुसार, सोमवार को न्यू वेस्टमिंस्टर की अदालत में फॉक्स और लोपेज ने सेकंड-डिग्री हत्या के दोष को स्वीकार कर लिया।

रूसी कृष्ण भक्तों ने भजन गाकर कजान में मोदी का स्वागत किया

कजान (रूस)। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मंगलवार को कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत इस्कॉन के कृष्ण भक्तों द्वारा संस्कृत स्वागत गीत, रूसी नृत्य और कृष्ण भजन के साथ किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल कॉर्स्टन में पीएम मोदी का स्वागत किया। वे भारतीय तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे। कई लोग अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेते भी दिखे। जब पीएम ने उनमें से कुछ लोगों से हाथ मिलाया तो उन्होंने संस्कृत में एक स्वागत गीत गाया। पारंपरिक भारतीय परिधान पहने रूसी कलाकारों की एक टीम ने रूसी नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे मोदी ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के कुछ भक्तों ने कृष्ण भजन की प्रस्तुति भी दी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक अद्भुत जुड़ाव। कजान में स्वागत के लिए आभारी हूं। भारतीय समुदाय ने अपनी उपलब्धियों से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता भी उतनी ही खुशी देने वाली है।

चीन और वेटिकन बिशप नियुक्ति पर समझौते को सहमत

बीजिंग। चीन सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह देश में कैथोलिक बिशप की नियुक्ति पर वेटिकन के साथ एक अस्थाई समझौते को चार वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गई है। साल 2018 में हुए इस समझौते का पहले भी दो बार विस्तार किया जा चुका है। पोप फ्रांसिस के तहत हुआ यह समझौता चीन में चर्च के नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को पाटने का एक प्रयास है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने समझौते के विस्तार की पुष्टि की। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष रचनात्मक भावना का पालन करते हुए संपर्क और संवाद बनाए रखेंगे तथा चीन-वेटिकन संबंधों में सुधार की कवायद जारी रखेंगे। चीन के साथ वेटिकन के रिश्ते लगभग 70 दशक पहले बिगड़ने लगे थे, जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। देश के अनुमानित 1.2 करोड़ कैथोलिक विभाजित हो गए थे। इनमें से कुछ की निष्ठा राज्य-मान्यता प्राप्त चर्च और कुछ की उस भूमिगत चर्च के प्रति थी, जो रोम के प्रति वफादार था। राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मामले के रूप में बिशप को नामित करने के विशेषाधिकार पर चीन के दावों को लेकर रिश्ते और तल्ख हो गए, क्योंकि वेटिकन का कहना था कि पोप को धर्मप्रचारकों के उत्तराधिकारियों का नाम देने का अधिकार है।

20 लाख रुपए की अवैध नकदी बरामद, दो भारतीय गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में गैरकानूनी रूप से 20 लाख रुपए की नकदी रखने के आरोप में मंगलवार को दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के निवासी सलमान कुरैशिया (33) और उमेश सखाराम खानडागले (39) को नेपाल-भारत सीमा पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। वे भारतीय नंबर प्लेट वाले अलग-अलग वाहनों में सवार थे। पुलिस ने उनके पास से कुल 20,50,000 भारतीय रुपए बरामद किए और वे इस रकम के संबंध में वैध दस्तावेज नही दिखा सके। नेपाल में उचित दस्तावेजों के बिना 25,000 या उससे अधिक भारतीय रुपए नकद रखना गैरकानूनी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों और बरामद नकदी को कपिलवस्तु जिले में राजस्व जांच विभाग को सौंपा गया है।

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा मिली

लीमा। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलेक्जांद्रो टोलेडो को ब्राजील की दिग्गज निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट से जुड़े एक मामले में सोमवार को 20 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यह ब्राजीलियाई कंपनी पूरे लातिन अमेरिका में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है जहां उसने सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों को रिश्वत के रूप में लाखों डॉलर दिए हैं। प्राधिकारियों ने टोलेडो पर इस दक्षिण अमेरिकी देश में एक राजमार्ग के निर्माण की अनुमति देने के बदले में ओडेब्रेक्ट से 3.5 करोड़ डॉलर की घूस लेने का आरोप लगाया था। पेरू की राजधानी लीमा में विशिष्ट आपराधिक न्याय की राष्ट्रीय सर्वोच्च अदालत ने बरसों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह सजा सुनाई है। यह भी विवाद था कि क्या 2001 से 2006 तक पेरू पर शासन करने वाले टोलेडो को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है। लातिन अमेरिका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल रहे ओडेब्रेक्ट ने 2016 में अमेरिकी प्राधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया था कि उसने पूरे क्षेत्र में सरकारी ठेकों के बदले में अच्छी-खासी घूस दी है। पेरू में प्राधिकारियों ने टोलेडो और तीन अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों पर इस निर्माण कंपनी से घूस लेने का आरोप लगाया है।

क्वाड देशों ने क्वाड साइबर चैलेंज जारी रखने की घोषणा की

वाशिंगटन। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड साइबर चैलेंज को जारी रखने की घोषणा की है, उद्देश्य जिम्मेदार साइबर परिवेशी तंत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देना तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है। क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इस वर्ष की चुनौती का विषय साइबर सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना और एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करना है। फरवरी 2023 में अमेरिका ने अपने क्वाड साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ मिलकर क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपने देशों और क्षेत्रों तथा उससे आगे भी, जिम्मेदार साइबर आदतों, चलन और अभ्यास को बढ़ावा देना है। संयुक्त बयान में कहा गया कि अक्टूबर में भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, देश के साइबर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से"साइबर स्वच्छता अभियान" के तहत छात्र समुदाय को एक संदेश देंगे।

ताइवान ने प्रीटोरिया से प्रतिनिधि कार्यालय हटाने की दक्षिण अफ्रीका की मांग खारिज

ताइपे (ताइवान)। ताइवान ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया में स्थित उसके प्रतिनिधि कार्यालय को हटाकर जोहानिसबर्ग में स्थानांतरित करने की उसकी मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेफ लियू ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्यालय को स्थानांतरित करने या बंद करने की मांग, औपचारिक राजनयिक संबंधों के विच्छेद के बाद दोनों पक्षों के बीच उनके पारस्परिक प्रतिनिधि कार्यालयों के स्थान को लेकर 1997 में हुए समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है।

लियू ने कहा, इस तरह की अनुचित मांग को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में दक्षिण अफ्रीका का एक संपर्क कार्यालय है और दोनों पक्षों के बीच मजबूत वाणिज्यिक संबंध है। लियू ने विदेश मंत्री लिन चिया-लंग द्वारा सोमवार को संसद में दिए गए बयान को दोहराया कि ताइवान इस मुद्दे पर सभी परिस्थितियों के लिए तैयार है।

लिन और लियू ने कहा कि यह कार्यालय ताइवान की संपत्ति है और ताइपे को इसका स्थान और स्थिति निर्धारित करने का अधिकार है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है और आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक अपने क्षेत्र में मिलाने की धमकी देता है। चीन लगातार ताइवान के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को कम करने का प्रयास करता रहता है, हालांकि इस स्वशासित द्वीप गणराज्य के अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले सप्ताह पुष्टि की कि उसने ताइवान से अपना संपर्क कार्यालय स्थानांतरित करने को कहा। दक्षिण अफ्रीका की इस मांग का कारण चीन का प्रभाव माना जा रहा है। चीन ने अपने प्रभाव का उपयोग करके ताइवान को संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संबद्ध शाखाओं से बाहर कर दिया है।

सिंगापुर के संस्थापक के बेटे यांग ने कहा, मैं अब ब्रिटेन में एक राजनीतिक शरणार्थी हूं

सिंगापुर। आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक, दिवंगत ली कुआन यू के सबसे छोटे बेटे ली सीन यांग ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रिटिश सरकार से शरण देने की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है और अब वह ब्रिटेन में एक राजनीतिक शरणार्थी हैं। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) ने यांग के एक फेसबुक पोस्ट के हवाले से खबर प्रसारित की, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अब भी सिंगापुर का नागरिक हूं और उम्मीद करता हूं कि किसी दिन (मेरे लिए) स्वदेश लौटना सुरक्षित होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के छोटे भाई यांग ने उनके खिलाफ सिंगापुर सरकार के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साल 2022 में अंतिम विकल्प के रूप में ब्रिटिश सरकार से शरण देने की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है और अब वह ब्रिटेन में एक राजनीतिक शरणार्थी हैं। यांग और उनकी बहन ली वे लिंग (जिनका अक्टूबर की शुरुआत में निधन हो गया) का लूंग के साथ इस बात को लेकर मतभेद है कि उनके पिता ली कुआन यू के गुजरने के बाद उनके आवास का क्या किया जाए। ली कुआन यू का 2015 में निधन हो गया था।

ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को दिए साक्षात्कार में यांग ने आरोप लगाया कि सिंगापुर में उनके खिलाफ चलाए जा रहे उत्पीड़न अभियान ने उन्हें ब्रिटेन से शरण की गुहार लगाने के लिए मजबूर किया। यांग के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंगापुर सरकार ने कहा कि यांग के खिलाफ उत्पीड़न अभियान चलाए जाने के आरोप और देश में राजनीतिक दमन के दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, सिंगापुर की न्यायपालिका निष्पक्ष है और स्वतंत्र रूप से फैसले लेती है। यही कारण है कि सिंगापुर के लोगों का न्यायपालिका पर बहुत अधिक का भरोसा है।

प्रवक्ता ने दावा किया कि यांग और उनकी पत्नी एवं वकील ली सुएत फर्न के सिंगापुर लौटने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। उन्होंने कहा, दोनों सिंगापुर लौटने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। पारिवारिक आवास के साथ क्या किया जाना है, इसे लेकर ली कुआन यू की वसीयत से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही में झूठे सबूत देने के संभावित अपराधों को लेकर यांग और उनकी पत्नी ने 2022 में पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। दोनों तभी से सिंगापुर से बाहर हैं। यांग और उनकी बहन लिंग ने आरोप लगाया था कि उन्हें घर को ध्वस्त करने की अपने दिवंगत पिता की इच्छा को पूरा करने की कोशिश में खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने लूंग पर अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए सरकार में अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया था।

भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन नेताओं ने नीतिगत मुद्दों पर कमला हैरिस की निंदा की

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े तीन भारतीय-अमेरिकी नेताओं बॉबी जिंदल, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कथित रूप से गलत आव्रजन, आर्थिक और विदेश नीतियों की आलोचना की है। लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल ने एक वीडियो में दावा किया कि हैरिस की चिकित्सा संबंधी मेडिकेयर योजना से 1.2 करोड़ अवैध प्रवासियों को गोल्ड प्लेटेड स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। जिंदल का यह वीडियो विज्ञापन के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

राजनीतिक मामलों की एक कार्य समिति अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वीडियो में जिंदल ने कहा, इससे अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने कहा, कृपया अपने परिवार और मित्रों को इस झूठ के झांसे में नहीं आने दें। जिंदल (53) 2008 से 2016 तक लुइसियाना के गवर्नर थे। 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का असफल प्रयास किया था। शुरू में चुनाव प्रचार और डोनाल्ड ट्रंप के अभियान से दूर रहने के बाद जिंदल अब पूर्व राष्ट्रपति को उनकी नीतियों पर समर्थन देने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं।

जिंदल के अलावा, साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और व्यवसाई से नेता बने विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रह चुके हैं। जिंदल 2016 में और अन्य दो 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रहे। अब इन तीनों ने राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप का समर्थन किया है। रामास्वामी ट्रंप के सबसे करीबी विश्वासपात्र बनकर उभरे हैं और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

सोमवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में हेली ने कहा, जब मैं दोनों उम्मीदवारों के बीच मुद्दों और मतभेदों को देखती हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को यह चुनाव जीतते देखना चाहती हूं। उन्होंने कहा, हम कमला हैरिस और टिम वाल्ज को क्रमश: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं देख सकते। आपको यह देखना है कि कमला हैरिस ने क्या कहा है। वह नहीं सोचतीं कि अवैध अप्रवासी अवैध हैं। वह सोचती हैं कि हमें इन अवैध अप्रवासियों को मुफ्त शिक्षा, रहने के लिए मुफ्त जगह, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए। हेली ने दावा किया कि हैरिस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वाल्ज के पास विदेश नीति का अनुभव नहीं है।इन तीन भारतीय-अमेरिकी नेताओं में रामास्वामी हैरिस के सबसे कटु आलोचक बनकर उभरे हैं। वह ट्रंप के पक्ष में समूचे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

संघर्ष विराम के प्रयासों को बहाल करने की उम्मीद से इजराइल पहुंचे ब्लिंकन

भाषा। तेल अवीव

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से 11वीं बार इस क्षेत्र की यात्रा पर मंगलवार को इजराइल पहुंचे। उनके हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद संघर्ष विराम के प्रयासों को फिर से शुरू करने की अमेरिका की उम्मीदों के बीच शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है। ब्लिंकन के इजराइल पहुंचने से कुछ घंटों पहले मंगलवार को हिजबुल्ला ने मध्य इजराइल में कई रॉकेट दागे, जिससे देश के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों और उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सायरन बजने लगे। अभी हमले में किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

इजराइली सेना ने बताया कि लेबनान से उनके देश में पांच रॉकेट दागे गए और ज्यादातर को इजराइली की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। एक रॉकेट एक खुले इलाके में गिरा। इजराइली सेना ने कहा कि इसी दौरान लेबनान की ओर से उत्तरी इजराइल में करीब 15 रॉकेट छोड़े गए।

ब्लिंकन के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है। इजराइल के बाद वह जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों की यात्रा कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा, विदेश मंत्री ब्लिंकन गाजा में युद्ध खत्म करने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और फलस्तीनी लोगों की पीड़ा दूर करने की महत्ता पर चर्चा करेंगे। ब्लिंकन की पिछली यात्राओं से युद्ध खत्म करने के प्रयासों में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन वह गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने में सफल रहे हैं।

हिजबुल्ला ने मध्य इजराइल में कई रॉकेट दागे

तेल अवीव। हिजबुल्ला ने मंगलवार को मध्य इजराइल में कई रॉकेट दागे, जिससे देश के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि इन हमलों में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह हमला गाजा युद्धविराम वार्ता को फिर से शुरू करने के मिशन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के क्षेत्र में पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ। इजराइली सेना ने कहा कि लेबनान से इजराइल में पांच रॉकेट दागे गए और इनमें से अधिकतर को इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया। एक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। रॉकेट हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल ने लेबनान में हमले तेज करने के साथ ही हिजबुल्ला द्वारा संचालित एक वित्तीय संस्थान को निशाना बनाया है तथा अमेरिका हमास नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा में संघर्ष विराम वार्ता को फिर से शुरू करने पर जोर दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और समूह द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को मुक्त कराने का संकल्प लिया है। वहीं, हमास का कहना है कि वह स्थाई युद्ध विराम, गाजा से इजराइली सैनिकों की पूरी तरह वापसी और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में ही बंधकों को रिहा करेगा।

पिछले साल सात अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए, 250 अन्य का अपहरण कर लिया गया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा में इजराइल के जवाबी हमले में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध से गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं और इसकी 23 लाख की आबादी में से लगभग 90 प्रतिशत लोग विस्थापित हो गए हैं।

अस्पताल के पास हुए इजराइली हमले में मृतक संख्या 13 हुई, 57 अन्य घायल

तेल अवीव। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बेरूत के एक मुख्य अस्पताल के पास हुए इजराइली हमले में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सोमवार देर रात हवाई हमला राजधानी के मुख्य सरकारी अस्पताल के सामने वाली इमारत पर हुआ। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमले में 57 अन्य लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए फुटेज से पता चला है कि हमला अस्पताल के प्रवेश द्वार के करीब हुआ। इजराइल का कहना है कि वह केवल आतंकवादियों को निशाना बनाता है तथा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करता है।

हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन सहित कई प्रमुख खेल ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर

भाषा। लंदन

भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है क्योंकि मेजबान शहर ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 में होने वाले खेलों के कार्यक्रम हटा दिया है तथा केवल 10 खेलों को इसमें जगह दी गई है। लागत को सीमित करने के लिए टेबल टेनिस, स्क्वाश और ट्रायथलॉन को भी हटा दिया गया है। बर्मिंघम में 2022 में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नौ खेल अगले खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। इन खेलों को केवल चार स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने बयान में कहा, इन खेलों में 10 खेल शामिल होंगे ताकि इन खेलों का बहु खेल वाले आयोजनों का स्वरूप भी बना रहे तथा वित्तीय और संचालन संबंधी चिंताओं से भी निपटा जा सके। इन दोनों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। बयान में कहा गया है, खेल कार्यक्रम में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (ट्रैक एवं फील्ड), तैराकी और पैरा तैराकी, कलात्मक जिमनास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग और पैरा ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा पावरलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और पैरा बाउल्स, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 23 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। ग्लासगो ने इससे पहले 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबानी की थी। बयान के अनुसार, इन खेलों का आयोजन चार स्थलों स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल तैराकी केंद्र, एमिरेट्स एरेना और स्कॉटिश प्रतियोगिता परिसर (एसईसी) में किया जाएगा। खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ को होटल में ठहराया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का यह कार्यक्रम भारत की पदक संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अधिकतर पदक उन खेलों में जीते थे जिन्हें हटाया गया है। निशानेबाजी को बर्मिंघम खेलों के कार्यक्रम से भी हटाया गया था और उसकी वापसी की कम उम्मीद थी।सीजीएफ ने ग्लासगो खेलों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा, ग्लासगो में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आठ मील के दायरे में स्थित चार स्थानों पर किया जाएगा। इन खेलों में 10 खेल को शामिल किया गया है। निशानेबाजी को इसलिए कार्यक्रम से बाहर किया गया है क्योंकि 2014 में इस खेल का आयोजन डंडी में बैरी बुडन सेंटर में किया गया था जो ग्लासगो से 100 किमी से अधिक दूर है। इसके साथ ही तीरंदाजी को भी नजरअंदाज किया जाता रहा है। यह खेल आखिरी बार दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा था।राष्ट्रमंडल खेल 2014 में हॉकी और कुश्ती की मेजबानी करने वाले ग्लासगो ग्रीन और स्कॉटिश प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र को आयोजन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जबकि सर क्रिस होय वेलोड्रोम, जहां उस वर्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इस बार केवल साइकलिंग की मेजबानी करेगा।आयोजकों ने खेलों को चार स्थानों तक सीमित रखने को सही ठहराते हुए कहा, इसके लिए लागत और संचालन संबंधी जोखिम मुख्य कारक थे। प्रत्एक स्थान का किराया, सुरक्षा, परिवहन इत्यादि के लिए अतिरिक्त लागत लगती है और इससे काम में जटिलता भी आती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि अतिरिक्त स्थान को जोड़ना महंगा सौदा होगा।

पदक दिलाने वाले खेलों को बाहर करने से भारतीय खेल समुदाय स्तब्ध

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख खिलाड़ी और खेल प्रशासक हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती को ग्लासगो में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से बाहर किए जाने के कारण देश की पदक संभावनाओं को झटका लगने से स्तब्ध हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेजबानी से हटने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी में इन खेलों का आयोजन सुनिश्चित किया गया। इन खेलों में केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं। टेबल टेनिस, स्क्वाश और तीरंदाजी भी उन खेलों ने शामिल हैं जिन्हें कार्यक्रम से हटाया गया है। लागत कम करने और संचालन संबंधी जोखिमों से बचने के लिए इन खेलों का आयोजन केवल चार स्थलों पर किया जाएगा। भारतीय खेल समुदाय हालांकि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) के इस फैसले से हैरान है।राष्ट्रमंडल खेलों में पिछले दो दशक में कई पदक जीतने वाले टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल ने कहा, यह बेहद अफसोसनाक है कि टेबल टेनिस को राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से हटा दिया गया है। दुर्भाग्य से यह उन 10 खेल का हिस्सा नहीं है जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह उन सभी खेलों के लिए करारा झटका है जिन्हें हटाया गया है, विशेष कर टेबल टेनिस के लिए जिसमें हमने कई स्वर्ण पदक जीते हैं। शरत के साथी जी साथियान ने कहा, यह निराशाजनक है। टेबल टेनिस जैसे मुख्यधारा के खेल को बाहर देखना आश्चर्यजनक है। भारतीय टेबल टेनिस बिरादरी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। देश की बेहतरीन स्क्वाश खिलाड़ियों में से एक दीपिका पल्लीकल से जब प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने निराशा व्यक्त की। दीपिका ने कहा, जब भी ऐसा लगता है कि हम खेल के लिए कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अचानक दो कदम पीछे हट जाते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है कि हमारे खेत को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 16 खेलों में 210 खिलाड़ी उतारे थे। इन खेलों में उसने 61 पदक जीते थे जिनमें 30 पदक उन खेलों में हासिल किए थे जिन्हें अगले राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से हटा दिया गया है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, उन अधिकतर खेलों को हटा दिया गया है जिनमें भारत पदक जीतता रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को इस मामले को उठाना चाहिए। अपनी तरफ से हमने एफआईएच (अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ) के सामने अपनी शिकायतें रखी हैं और वे इस मामले को सीजीएफ के साथ उठा रहे हैं।भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, यह निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह निश्चित रूप से भारतीय कुश्ती समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाला है।

हमें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम नहीं भेजनी चाहिए: गोपीचंद, विमल ने भी लगाई फटकार

नई दिल्ली। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद और विमल कुमार ने मंगलवार को 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन जैसे खेलों को बाहर करने के फैसले की आलोचना की और देश से इन खेलों में टीम नहीं भेजने का आग्रह किया क्योंकि इसका उद्देश्य भारत की प्रगति को रोकना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक की संभावनाओं को उस समय झटका लगा जब ग्लासगो ने बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 में होने वाले खेलों के कार्यक्रम हटा दिया है तथा केवल 10 खेलों को इसमें जगह दी गई है जो पिछले खेलों की तुलना में नौ कम हैं। लागत को सीमित करने के लिए टेबल टेनिस, तीरंदाजी, स्क्वाश और ट्रायथलन को भी हटा दिया गया है।

इन खेलों को हटाने से भारतीय खेल जगत स्तब्ध है और गोपीचंद तथा विमल ने सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूर्व भारतीय कोच विमल ने कहा, राष्ट्रमंडल खेलों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नजरिए से उन्हें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों की जगह ओलंपिक और एशियाई खेलों का आयोजन करना बेहतर है। यह दयनीय है, मैं बेहद निराश हूं। राष्ट्रमंडल खेल अपनी चमक, संदर्भ खो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम नहीं भेजनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रमंडल खेलों की जगह यह महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के तरीकों पर गौर किया जाए। राष्ट्रमंडल खेलों की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में अच्छे शारीरिक खेल होने चाहिए, अगर आप इन सभी को हटा दोगे तो फिर क्या जरूरत है। गोपीचंद ने खेल के आयोजकों के इस कदम को भयावह करार दिया। इस पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन ने कहा, मैं 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन को बाहर करने के निर्णय से बेहद स्तब्ध और निराश हूं। ऐसा लगता है कि यह फैसला भारत जैसे देशों की प्रगति को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। गोपीचंद ने कहा कि बैडमिंटन ने हमें बहुत गौरव और सफलता दिलाई है और यह हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

ग्लासगो खेलों में 400 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजेगा ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न। अपने प्रदेश विक्टोरिया के नाम वापिस लेने के बाद स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होने की पुष्टि से राहत महसूस कर रहे आस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह इन खेलों में 400 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजना चाहता है। आस्ट्रेलिया में हालांकि हॉकी और स्क्वाश समेत कई खेलों के प्रमुखों ने 2026 ग्लासगो खेलों से इन स्पर्धाओं को हटाए जाने पर निराशा जताई है। इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने ग्लासगो आयोजकों के फैसले का समर्थन किया है। आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष बेन ह्यूस्टन ने एक बयान में कहा , मैं 2026 खेलों की मेजबानी के लिए स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल खेल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम 400 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजेंगे। ए खेल आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे लेकिन बढती लागत के कारण उसने नाम वापिस ले लिया जिसके बाद स्कॉटलैंड मेजबानी के लिए तैयार हुआ। हॉकी आस्ट्रेलिया के सीईओ डेविड प्राइलेस ने हालांकि कहा , यह निराशाजनक है। सिर्फ हॉकी के लिए नहीं बल्कि उन सभी खेलों के लिए भी जो ग्लासगो खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। स्क्वाश आस्ट्रेलिया के सीईओ रॉबर्ट डोनागू ने कहा , इससे उन खिलाड़ियों को झटका लगा है जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने का सपना देख रहे थे।

कर्नाटक ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता

पणजी। कर्नाटक ने मंगलवार को यहां 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 392 अंक के साथ ओवरऑल खिताब जीता।महाराष्ट्र की टीम 378 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही जबकि राजस्थान ने 248 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 28 राज्यों के 518 तैराकों ने हिस्सा लिया जिसमें 360 पुरुष और 158 महिला प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में केरल के मोहम्मद आसिम को सीनियर चैंपियन, आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक को जूनियर चैंपियन और हरियाणा के रेवांश को सब जूनियर चैंपियन चुना गया।

पिकेलबॉल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स नई दिल्ली में 24 से

नई दिल्ली। पिकेलबॉल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स का आयोजन यहां डीएलटीए परिसर में 24 अक्टूबर से किया जाएगा जिसमें लगभग 750 पेशेवर और एमेच्योर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इंडिया मास्टर्स पीडब्ल्यूआर700 प्रतियोगिता है और यह पूरी तरह से पिकेलबॉल विश्व रैंकिंग (पीडब्ल्यूआर) के अधीन भारत में होने वाला पहला टूर्नामेंट है। पीडब्ल्यूआर विश्व टूर का जुलाई 2024 में यूएई के दुबई में अनावरण किया गया था। भारत के अरमान भाटिया और आदित्य रूहेला सहित दुनिया भर के कई शीर्ष खिलाड़ी इस 50 हजार डॉलर इनामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। द टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पिकेलबॉल भारत में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला खेला है।

भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराकर सुल्तान जोहोर कप में जारी रखा विजई अभियान

जोहोर बाह (मलेशिया)। तीन बार के चैंपियन भारत ने मंगलवार को यहां सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर अपना अजेय क्रम जारी रखा। इस जीत के बाद भारत नौ अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है जबकि न्यूजीलैंड पांच अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए शारदा नंद तिवारी (11वें), अर्शदीप सिंह (13वें), तालेम प्रियाव्रत (39वें) और रोहित (40वें मिनट) ने गोल किए, जबकि मलेशिया के लिए मुहम्मद दानिश अइमान (आठवें) और हैरिस उस्मान (नौवें मिनट) ने गोल किया। मलेशिया ने इस मुकाबले में जोरदार शुरुआत कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। घेरलू टीम ने कप्तान मुहम्मद अदी जाजमी जमलुस के बनाए मौके पर मोहम्मद दानिश अमान के मैदानी गोल से आठवें मिनट में बढ़त हासिल कर ली।

रूट में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता: कुक

दुबई। (भाषा) इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक का मानना है कि जो रूट अपनी भूख और अविश्वसनीय प्रतिभा की बदौलत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं। तेंतीस साल के रूट के नाम फिलहाल 12,716 टेस्ट रन हैं और वह भारतीय दिग्गज तेंदुलकर (15,921) से 3205 रन पीछे हैं। रूट फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उनसे आगे राहुल द्रविड़ (13,288), जाक कैलिस (13,289) और रिकी पोंटिंग (13,378) और तेंदुलकर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कुक के हवाले से कहा, मुझे लगता है कि जो रूट निश्चित रूप से इंग्लैंड टीम के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगर वह 16,000 टेस्ट रन बनाने वाला पहला व्यक्ति नहीं बन पाते तो इससे काफी करीब पहुंच सकते हैं। यह शानदार उपलब्धि होगी। रूट ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दौरान लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर कुक को पीछे छोड़ दिया था। रूट की इस उपलब्धि के बाद 39 वर्षीय कुक ने उन्हें इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देने के लिए फोन किया। कुक ने कहा, मैंने उस पल को देखा, फिर दिन का खेल खत्म होने के बाद मैंने उन्हें फोन किया। मुझे लिखित संदेश में लिखने के लिए सही शब्द नहीं सूझ रहे थे। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें फोन करूंगा और देखूंगा कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें फोन करूंगा और देखूंगा कि वे क्या कर रहे हैं। सुनिश्चित करूंगा कि उनके हाथ में बीयर हो, जो मुझे लगता है कि उनके हाथ में थी। पिछले चार वर्षों में रूट ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान अपने 35 टेस्ट शतकों में से आधे से ज्यादा शतक बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 60 के करीब है। कुक का मानना है कि वह वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन उनकी बराबरी के करीब हैं।

द. अफ्रीका ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसा

वेरिने ने 114 रन की पारी खेलते हुए दूसरा टेस्ट शतक जड़ा जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 308 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर 202 रन की बढ़त हासिल की

मीरपुर (बांग्लादेश)।(एपी) काइल वेरिने के शतक से दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वेरिने ने 114 रन की पारी खेलते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 308 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर 202 रन की बढ़त हासिल की। खराब रोशनी के कारण जब दूसरे दिन का खेल समाप्त किया गया तब बांग्लादेश ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 101 रन बना लिए थे। टीम को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 101 रन की दरकार है।

दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन 38 जबकि मशफिकुर रहीम 31 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों चौथे विकेट के लिए अब तक 42 रन की साझेदारी कर चुके हैं।

वेरिने ने इससे पहले वियान मुल्डर (54) के साथ सातवें विकेट के लिए 119 और डेन पीट (32) के साथ नौवें विकेट के लिए 66 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वह आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 144 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के मारे। दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 140 रन से की थी और उस पर मजबूत बढ़त लिए बिना आउट होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन स्पिन की अनुकूल पिच पर वेरिने ने एक छोर संभाले रखा और अपनी टीम को बड़ी बढ़त दिलाई। वेरिने और मुल्गर ने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का काफी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। वेरिने ने ताइजुल इस्लाम पर स्वीप से चौका जड़कर 67 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। मुल्डर ने भी ऑफ स्पिनर नईम पर रिवर्स स्वीप से चौका जड़कर 105 गेंद में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। तेज गेंदबाज हसन महमूद ने मुल्डर को स्लिप में शादमान इस्लाम के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा और फिर अगली गेंद पर केशव महाराज को खाता खोले बिना बोल्ड किया। वेरिने और पीट ने इसके बाद टीम की बढ़त को 200 रन के पार पहुंचाया। वेरिने ने ताइजुल पर एक रन के साथ 134 गेंद में शतक पूरा किया। मेहदी हसन मिराज ने पीट को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा। वेरिने ने मिराज (63 रन पर दो विकेट) पर दो छक्के मारे लेकिन इस स्पिनर ने उन्हें आउट करके दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत किया।

हसन महमूद ने 66 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि कल पांच विकेट चटकाने वाले ताइजुल को आज कोई सफलता नहीं मिली। बांग्लादेश की दूसरी पारी में शुरुआत खराब रही जब कागिसो रबादा ने तीन दिन गेंद में शादमान (01) और मोमिनुल हक (00) को आउट करके तीसरे ओवर में बांग्लादेश का स्कोर दो विकेट पर चार रन किया। महमूदुल और कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने 55 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की। महाराज ने हालांकि शंटो (23) को आउट करके बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया।

वार्नर भारत के खिलाफ खेलने के लिए संन्यास से वापसी करने को तैयार

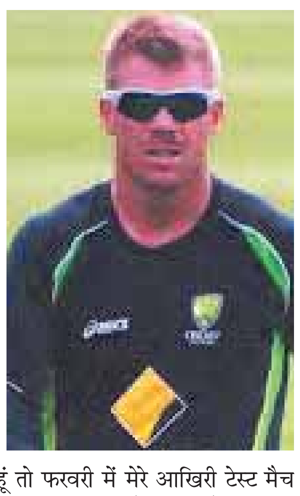

सिडनी। (भाषा) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी टीम को जरूरत होगी तो वह संन्यास से वापस आकर आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं। इस 37 साल के पूर्व खिलाड़ी ने इस साल पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास की घोषणा की थी। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में 34 और 57 रन की पारी खेली थी। इस वामहस्त बल्लेबाज ने कोड स्पोर्ट्स से कहा, मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं, बस फोन उठाना बाकी है। मैं इस बारे में हमेशा गंभीर रहता हूं। ईमानदारी से कहूं तो फरवरी में मेरे आखिरी टेस्ट मैच के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सिर्फ चार टेस्ट मैच खेले है, इसलिए मेरी तैयारी लगभग वैसी ही है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की संभावना को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए पांच मैचों की यह श्रृंखला काफी अहम है। इसका आगाज 22 नवंबर से पर्थ में होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड में भाग लेकर कड़ी तैयारी कर रहे हैं। वार्नर को अपनी फिटनेस हासिल करने और चयनकर्ताओं को फिर से प्रभावित करने के लिए इस घरेलू प्रतियोगिता में कुछ मैच खेलने होंगे। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो अगर उन्हें इस श्रृंखला के लिए वाकई मेरी जरूरत है, तो मुझे अगला शील्ड मैच खेलने को लेकर बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा, मैंने सही कारणों से संन्यास लिया था।

न्यूजीलैंड को तेजी से सामंजस्य बैठाना होगा

पुणे में स्पिन पिच की संभावना पर बोले मिचेल

पुणे।(भाषा) ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने कहा है कि न्यूजीलैंड को बेंगलुरू टेस्ट में मिली जीत को पीछे छोड़कर बृहस्पतिवार से यहां शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के दौरान संभावित रूप से स्पिन के अनुकूल हालात से तेजी से सामंजस्य बैठाना होगा। न्यूजीलैंड ने भारत को उसके मैदान पर 36 साल में पहली बार शिकस्त देते हुए तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाने का दावा मजबूत करने के लिए भारत के पुणे में स्पिन की अनुकूल पिच पर पलटवार करने की उम्मीद है। मिचेल ने मंगलवार को यहां न्यूजीलैंड के ट्रेनिंग सत्र के बाद मीडिया से कहा, एक जीत जो हम नहीं कर सकते, वह यह है कि हम सतह को नहीं बदल सकते। इसलिए हमारे सामने जो है हमें उसे देखते हुए प्रतिक्रिया देनी होगी और तेजी से सामंजस्य बैठाना होगा। उन्होंने कहा, कीवी खिलाड़ी के तौर पर हमें इस पर गर्व है कि हम वर्तमान में जीते हैं, हम अपने पैर जमीन पर रखते हैं और जितना अधिक संभव को वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं। मिचेल ने कहा, हम विकेट नहीं बदल सकते। वह जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि रणनीति के साथ उतरेंगे और 20 विकेट चटकाने का तरीका ढूंढ लेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ रन भी बनाएंगे। मिचेल ने कहा कि मेहमान टीम बेंगलुरू में मिली जीत से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।उन्होंने कहा, देखिए हमारे लिए अब यह एक अन्य टेस्ट मैच की तरह है। यह अतीत की बात है। बेशक वह टेस्ट मैच जीतकर मैं बेहद खुश हूं। इस ऑलराउंडर ने कहा, लेकिन साथ ही यह अलग मैदान हैं, अलग सतह और हम पहली गेंद फेंके जाने के लिए तैयार हैं। मिचेल ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों सरफराज खान और ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी से परेशान नहीं है। उन्होंने कहा, ऋषभ एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और मैं उनके क्रिकेट खेलने के तरीके का सम्मान करता हूं और यह एक शानदार साझेदारी थी। मिचेल ने कहा, लेकिन हम जानते हैं कि बेंगलुरू में तेजी से रन बनते हैं। हम मैच में अच्छी स्थिति में थे। हम जानते थे कि हमें बस विकेट लेने की कोशिश करते रहना है। उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहना है। मिचेल ने कहा कि भले ही दो टेस्ट मैचों के लिए मिट्टी की संरचना - पुणे में काली मिट्टी और मुंबई में लाल मिट्टी - की अहम भूमिका रहेगी लेकिन उन्हें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम इसका हल निकलने में सफल रहेगी।उन्होंने कहा, सभी देशों में खेलने की चुनौतियां अलग होती हैं।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह।
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।